

वर्ष : 22 | अंक : 01  
01 से 15 अक्टूबर 2023  
पृष्ठ : 48  
मूल्य : 25 रु.

*In Pursuit of Truth*

# ओक्स

पाक्षिक



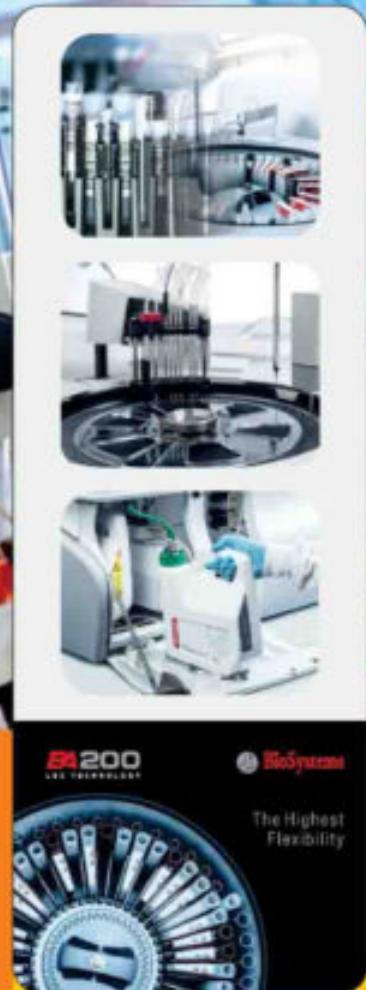
## आधी आबादी को पूरा हक कब तक?

2026 के बाद के चुनावों में ही  
लागू हो पाएगा नया कानून

देश में महिलाओं को पुरुषों के बराबर  
आने में 149 साल लगेंगे

# ANU SALES CORPORATION

We Deal in  
Pathology & Medical  
Equipment



Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

📞 9329556524, 9329556530 📩 Email : ascbhopal@gmail.com

## ● इस अंक में

### लालपीताशाही

9 | बेदाग रिटायर्ड हो  
गए दागदार चंदेल

कोई विश्वास करे या न करे, लेकिन मप्र वाकई अजब है, गजब है। इस बात पर मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण लगातार मुहर लगाता आ रहा है। विभाग का एक पुराना मामला वर्तमान में चर्चा में है। इसकी वजह है जिस...

### राजपथ

10-11 | क्षत्रपों पर दांव...

मप्र में भाजपा ने 230 विधानसभा सीटों में से तीन किस्तों (39+39+1) में 79 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लेकिन पहली सूची की तरह ही दूसरी सूची जारी होने के बाद असंतोष, विरोध और बगावत तेज हो गई है।

### विडंबना

20 | कई सरकारी प्रोजेक्ट अवैध

यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि मप्र के 50 फीसदी से ज्यादा सरकारी हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट अवैध हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन सरकारी प्रोजेक्टों में बिक्री भी नियमों-प्रावधानों को ताक पर रख की जा रही है। यह मामला रेरा कानून से जुड़ा है।

### बुंदेलखण्ड

23 | सूखे बुंदेलखण्ड में बह रही जल धारा

बुंदेलखण्ड जनपद विशेषकर दक्षिणी-पूर्वी बुंदेलखण्ड की भूमि पहाड़ी, पठारी, ढालू, ऊंची-नीची, पथरीली, ककरीली राकंड़, शुष्क वर्नों से भरपूर है। इस भूभाग की जमीन पर बरसाती जल ठहरता ही नहीं है, जिसके कारण बुंदेलखण्ड में पानी की कमी सदैव बनी रहती थी। करीब सवा करोड़ की...

### आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28



### राजनीति

30-31 | कांग्रेस के केंद्र में सिर्फ राहुल...

जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 4,000 किलोमीटर पैदल चलने वाली भारत जोड़े यात्रा शुरू की थी, तो किसी को आभास तक नहीं था कि सालभर में भारत शब्द राजनीति का बड़ा अखाड़ा बन जाएगा। संयोग ही है कि इस यात्रा के एक साल के भीतर ही विपक्ष ने सत्तारूढ़ भाजपा और एनडीए...

### महाराष्ट्र

34 | महाराष्ट्र में फिर पक रही खिचड़ी

महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने गौतम अडाणी से मुलाकात की और फिर राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के द्वारा गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। दोनों घटनाक्रमों के...



### 6-7 अंदर की बात

40 महिला जगत

42 अध्यात्म

43 कहानी

44 खेल

45 फिल्म

46 व्यंग्य

# चुनावी साल...हड्डताल ही हड्डताल...

वि

नोड बरक्सरी ने सरकारी कर्मचारियों और चुनावी राजनीति पर व्यंग्य करते हुए लिखा है कि...

चार साल तक जिन्हें मिलती रही उंट, उपट, फटकार

चुनावी साल में मिल रहा पुचकार, मनुहार और हुलार।

चुनावी साल में मप्र में यह बजारा देखा भी जा रहा है। अधिक से अधिक मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सरकार घोषणाओं पर घोषणाएँ करती जा रही है। सरकार के इस रूपर को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों ने भी अपनी मांगें मंगवाने के लिए मैदानी मोर्चा सभाल लिया है। इस कारण इस चुनावी साल में हड्डताल ही हड्डताल देखने को मिल रही है। चुनावी साल में पिछले एक महीने से सरकारी कर्मचारियों की हड्डतालों का ढौर चल रहा है जिसका ज्ञानियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। चुनावी साल के चलते ज्यादातर विभागों के अधिकारी-कर्मचारी अपनी लिपित मांगों को लेकर हड्डताल के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगे पूरी करना चाहते हैं। पटवारियों की हड्डताल से राजस्व के काम अटके पड़े रहे। मंडी व्यापारियों की हड्डताल से टिक्कान उपज नहीं बेच पा रहे थे और हम्मालों को मजदूरी नहीं मिल रही थी। वहीं परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने भी हड्डताल शुल्क कर सरकारों परेशानी में डाल दिया था। मंत्रालय से लेकर हड्डताल में धूना, प्रदर्शन और हड्डताल का क्रम चल रहा है। उधर सरकार सभी को साधने की जुगत में लगी हुई है। पुचकार, मनुहार और हुलार के साथ ही सरकार घोषणाओं का अंबार लगा रही है। इस साल में स्कूरे की जनता को जितनी बड़ी तादाद में सरकार के खिलाफ कर्मचारियों की मैदानी जंग देखने को मिली, उतनी 5 साल में नहीं नज़र आई। कर्मचारियों की शक्ति में हड्डताल करने वाली भी जनता ही थी और हड्डतालों का ज्ञानियाजा भुगतने और अपने काम न होने से परेशान होने वाली भी जनता ही थी। इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, लिहाजा हर कर्मचारी सरकार को अपनी नाराजगी और वोट की ताकत का अहसास करकर अपनी मांगें पूरी करना चाहता है। गुजरे एक साल में शायद ही कोई सरकारी महकमा हो, जिसने आंदोलन की हुक्मार न भरी हो। कर्मचारी संगठन सरकार का ध्यान खींचने का कोई नौकर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सरकार को भी इस परिस्थिति का अहसास है, इसलिए मांगें मानकरु, घोषणाएँ कर मान-मनौवत, पुचकार, हुलार में जुटी है। दूसरी तरफ विपक्ष इस असंतोष को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिशों में जुटा है। कर्मचारी संगठनों का मत है कि सरकार के कर्मचारी विशेष रूप से प्रदेश के कर्मचारी नाराज हैं। सरकारी महकमों में ही दो लालू से ज्यादा पड़े हैं। कर्मचारी ऑफिसरों से परेशान हैं। जिन मांगों को लेकर प्रदेशभू में धूने-प्रदर्शनों-आंदोलनों का ढौर चला या चल रहा है, उनमें स्विद्धा-कथाई कर्मचारियों के नियमितीकरण, वेतन वृद्धि, पुरानी पेंशन बहाली, विश्विता, प्रमोशन, समान वेतन, मंहगाई भर्ता, बकाया एवियर्स भुगतान, पेंशनरों को पेंशन में शहत जैसी मांग शामिल रही हैं। इन्हीं मांगों को लेकर कहीं कर्मचारी हड्डताल कर रहे, काम का बहिष्कार कर रहे, कहीं सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं या मत्रियों के बंगले घेर रहे हैं। मकसद किरण एक है कि चुनाव से पहले उनकी मांगें पूरी हो जाएं, बदला फिर कई साल संघर्ष करना पड़ेगा और सुनने वाला न मिलेगा। बता दें कि इस साल करीब 350 से ज्यादा आंदोलन हुए हैं। इस आंदोलन में एक हर्जन से ऊपर बढ़े और कई दिनों तक चले आंदोलन रहे हैं, जिसने सरकार को उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। सरकार भी ताबड़तोड़ फैसले लेकर सरकारी व्यवस्था करने में देरी नहीं कर रही है।

- श्रावेन्द्र आगाम

# आक्षस

वर्ष 22, अंक 1, पृष्ठ-48, 1 से 15 अक्टूबर, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाम

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लाट नंबर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्प्लेक्स,  
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर  
भोपाल - 462011 (म.प्र.),  
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com

Website : www.akshnews.com

RNI NO. HIN/2002/8718 MPPBL/642/2021-23

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

## ब्यूरो

कोलकाता:- इंद्रकुमार, छत्तीसगढ़:- संजय शुक्ला, मार्केंडेय तिवारी, जयपुर:- आर.के. बिनानी, लखनऊ :- मधु आलोक निगम।

## प्रदेश संचारद्वारा

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे  
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथरिया  
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार  
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमारी  
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

सावाणिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाम सारा आगाम प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल,  
एफ-03, मनोरमा कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

## क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईर्षे 294 माया इंकलेव मायापुरी  
फोन : 9811017939  
जयपुर : सी-37, नातिपथ, श्याम नार (राजस्थान)  
मोदीपुर : 09829 010331  
रायपुर : एपआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नार, फोन : 0771 2282517  
भिलाई : नेहरु भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोदीपुर 094241 08015  
इंदौर : नवीन रुवेंगी, रुवेंगी कॉलोनी, इंदौर, फोन : 9827227000  
देवास : जय रिहं, देवास  
फोन : 9900526104, 9907353976



## चुनावी घोषणाएं

प्रदेश में दो माह बाद चुनाव होने थे, ऐसे में चुनावी पार्टियां जनता का लुभावे में लगी हुई हैं। कोई महिलाओं के लिए अच्छी-अच्छी घोषणाएं कर रहा है, तो कोई किसानों का ऋण माफ करने की बात कर रहा है। इन चुनावी घोषणाओं का जनता पर क्या असर होता है, ये तो परिणाम पर ही पता चलेगा।

● थीर्जु शजपूत, भोपाल (म.प्र.)

## महिलाओं को मिला हक

महिला आवश्यक खिल पाक्ष होने से उन्हें वो हक मिला है, जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अब संसद में भी महिलाओं की आवादी बढ़ी गई, जिससे महिलाओं के लिए नए-नए कानून लागू हो सकेंगे। और तो और उन्हें रोजगार में भी बरबाद का हक मिल सकेगा।

● रक्षाति शिशा, शीता (म.प्र.)

## मिलेंगे आशियाने

प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवासहीनों के लिए स्कूकारू ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू की है। इसके लिए वे गरीब व्यक्ति पात्र होंगे, जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जुड़ पाए हैं। ये प्रदेश स्कूकारू की एक अच्छी पहल है, जिससे लोगों को आशियाने मिल सकेंगे।

● कुलबीर बिंदु, बैतूल (म.प्र.)



## प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत मजबूत

भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वह हासिल कर दिलाया जिसे राजनीतिक संकटों के समाधान के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय मंच हासिल नहीं कर पा रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघरक्षा परिषद यूद्ध को लकवाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही और अमेरिका जैसे मंचों के प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित न हो पाने के कारण निष्प्रभावी रहे। इसीलिए भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न जी-20 शिवार सम्मेलन के कुछ दिन पहले तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि घोषणा पत्र पर स्वरूप बन पाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय शिवार वर्ता में भारत की इस दावेदारी के समर्थन को दोहराया। इससे भारत की मजबूती का पता चलता है।

● शीमा शेख, शृंगरेन (म.प्र.)

## एक राष्ट्र एक चुनाव कितना ज़रूरी

हमारे देश के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव कितना ज़रूरी है, यह तो चर्चा का विषय है, लेकिन इसमें अने लाली कुछ स्वैदानिक चुनौतियां हैं। जैसे अनुच्छेद 356 कहता है कि बिना वैध कारण के किसी भी विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इस कारण जिन विधानसभाओं में विपक्षी दलों की बहुसंख्या है या जहां विपक्ष की स्कूकारू हैं वहां पर बड़ी अड़चन आ सकती है। स्वरक्षे बड़ी चुनौती यह है कि किसी विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता या पार्टीयां दूर जाती हैं, जिससे कारण विधानसभा को भंग करना पड़ता है तो उस स्थिति में क्या होगा?

● अनिलकुमार केवट, जबलपुर (म.प्र.)



## स्कूलों का हाल

प्रदेश के ज्यादातर स्कूकारू स्कूलों के हाल बद्या हैं यह परिस्कर्म में कदम बढ़ाते ही पता चल जाता है। दूसरी इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल आज भी बिजली, पेयजल और बच्चों के लिए बेहतर आवागमन व्यवस्था से रोज जूझते हैं। लेकिन व्यवस्था पर सवाल तब बढ़े होते हैं जब प्रदेश के महानगर कहे जाने वाले बड़े शहरों के स्कूल कश्तों के स्कूलों से भी पीछे नज़र आते हैं। स्कूकारू को इन स्कूलों के बारे में भी सोचना चाहिए।

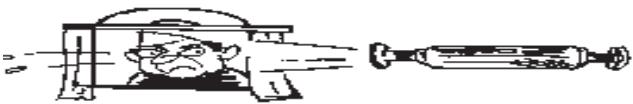
● अच्छा पाल, होशंगाबाद (म.प्र.)

## पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें।

## अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,  
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल



## बिधूड़ी की बढ़ेंगी मुश्किलें

भाजपा ने लोकसभा संसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले लोकसभा स्पीकर औम विरला ने उनके बयान पर गंभीर नाराजगी जताई है। औम विरला ने रमेश बिधूड़ी को फटकार लगाने के बाद उन्हें भाषा की मर्यादा का ध्यान रखने की चेतावनी दी है। वहाँ कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, एनसीपी के सुप्रिया सुले और बीएसपी के दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिखा है और इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का आग्रह किया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि विशेषाधिकार समिति में अगर यह मामला जाता है, तो बिधूड़ी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। असल में जब रमेश बिधूड़ी लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे तो उसी समय बसपा संसद दानिश अली ने टोका-टाकी शुरू कर दी। इससे नाराज होकर रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। बिधूड़ी की इस हक्कत से विपक्षी दल भी नाराज हैं। वहाँ पार्टी के अंदरखाने भी बिधूड़ी के इस बयान की निंदा हो रही है। उधर बहुजन समाज पार्टी के संसद दानिश अली ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि रमेश बिधूड़ी ने न केवल मेरा बल्कि पूरी संसद का अपमान किया है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक चुने हुए संसद के खिलाफ सदन में ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है।

## योगी कैबिनेट विस्तार के आसार

उपर में लोकसभा चुनाव के पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय माना जा रहा है। जिसमें एनडीए गठबंधन में शामिल हुए सुभासपा अध्यक्ष औपी राजभर को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है और साइकिल की सवारी छोड़ कमल का दामन थामने वाले दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये कथास तब लगाए जा रहे हैं, जब बीते दिनों सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। सुभासपा के एनडीए में शामिल होने के साथ ही राजभर का प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा था। ठीक ऐसी ही स्थिति दारा सिंह चौहान को लेकर भी थी। मगर घोसी सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में दारा सिंह को करारी हार का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद दारा के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों का कहना है कि दारा सिंह को एमएलसी बनाकर योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। एक तरफ जहाँ कुछ मौजूदा मंत्रियों की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहाँ अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल होना लगभग तय है। अब देखना यह होगा कि राजभर और दारा सिंह चौहान योगी कैबिनेट में मंत्री बनने के सपने को पूरा कर पाते हैं या नहीं।



## तय समय पर होंगे लोकसभा चुनाव!

अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाने की मोदी सरकार की घोषणा के बाद इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है। लेकिन सूत्रों की मानें तो जल्द चुनाव के आसार कम हैं। माना जा रहा है कि सरकार संसद के विशेष सत्र में यूसीसी, महिला आरक्षण, एक देश एक चुनाव जैसे कुछ अहम विधेयकों को पेश और पारित करके अपनी एक अलग छवि बनाने की जुगत में है। स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी पार्टियां जहाँ आपसी मतभेद भुलाकर मोदी हत्ता और अभियान में जुटी हैं, तो वहाँ सत्ताधारी भाजपा अपनी विकास परक छवि बनाकर 2024 में विपक्ष का खेल बिगाड़ने की तैयारी में है। समय पूर्व चुनाव की संभावना को इसलिए भी खारिज किया जा रहा है क्योंकि अयोध्या में भव्य रामर्मदिर का शुभारंभ अगले वर्ष 14 जनवरी के बाद होना है। भाजपा नेताओं का मानना है कि अयोध्या में 15 से 24 जनवरी के बीच रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद देश में जो राममय माहौल तैयार होगा, वह किसी भी अन्य बड़े निर्णयों के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रभावी होगा। ऐसे में फरवरी से पहले चुनाव में जाने की संभावना कर्तव्य नहीं है।

## विपक्षी एकता में दरार ?

विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट बंटवारे से लेकर दूसरे मुद्दों पर सहमति अब तक नहीं बन सकी है लेकिन दरार की खबरें पहले आने लगी हैं। इंडिया गठबंधन की तीन बैठकों के बाद भोपाल में संयुक्त रैली का आयोजन तय था लेकिन अचानक ही रैली रद्द हो गई है। कहा जा रहा है कि इसकी सूचना भी सहयोगी दलों को नहीं दी गई और मीडिया में रैली रद्द होने का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्षी एकता की बातें सिर्फ दावे भर हैं और हकीकत में गठबंधन में दरार आ चुकी है। रैली रद्द होने के पीछे कई तरह के कायास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो चुनावी प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की पहली रैली कराने से सभी पार्टियां हिचक रही थी। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रैली रद्द होने की पुष्टि जरूर की लेकिन बताया जा रहा है कि इस साल मप्र समेत जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ अब तक सीट शेरिंग और दूसरे मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन सकी है।

## कर्नाटक कांग्रेस में कलह

कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने बीते दिनों कहा कि धोती के साथ हब्लोट घड़ी पहनने वाले कुछ लोग समाजवादी होने का दावा नहीं कर सकते और कोई देवराज सामाजिक सुधारों के लिए पहचाने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री की कार में बैठकर उनकी तरह नहीं बन सकता। उनकी इस टिप्पणी को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर परोक्ष हमला माना जा रहा है। हालांकि हरिप्रसाद ने अपने भाषण के दौरान किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके ओर से दिए गए संदर्भों से स्पष्ट था कि उनके निशाने पर सिद्धारमैया थे। उन्होंने जी परमेश्वर मौजूदा सरकार में गृहमंत्री जैसे दलित नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए और अनुसूचित जनजाति से आने वाले सतीश जारकीहोली जैसे नेता के नाम पर उपमुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के विचार नहीं किए जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की थी। विधान पार्श्व हरिप्रसाद के बारे में माना जाता है कि वह राज्य मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से कुछ समय से नाराज हैं।

## रेत ठेकेदार के हाथ जिला प्रशासन का काम

महाकौशल के एक जिले में इन दिनों एक रेत ठेकेदार की तूती बोल रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इस ठेकेदार के हाथ में पूरा जिला प्रशासन है। यानी जिले में जो कुछ भी काम करना है ठेकेदार साहब आसानी से करा देते हैं। बस उनकी मांग के अनुसार आपको रकम देनी होगी। ठेकेदार के इस रसूख की पड़ताल की गई तो पता चला कि वे जिले के कलेक्टर और एसपी की आंख का तारा हैं। यानी वे दोनों अफसरों के लिए काम करते हैं। आलम यह है कि जब भी किसी का उल्टा-सीधा काम फंसता है, वह ठेकेदार साहब को पकड़ लेता है। ठेकेदार भले ही रेत का कारोबार करते हैं लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि वे हर उल्टे और गलत काम को सीधे तरीके से करा देते हैं। बताया जाता है कि जिले के कलेक्टर और एसपी साहब जब भी ठेकेदार को देखते हैं उनकी बांधे खिल उठती हैं। वजह भी साफ है। ठेकेदार उनके लिए लक्ष्मी का भरपूर जुगाड़ करते रहते हैं। सूत्रों का कहना है कि दोनों अफसरों की आड़ में ठेकेदार की भी जमकर पौं बारह हो रही है। वह मनमाने तरीके से रेत का कारोबार भी कर रहे हैं। बड़े साहबों का संरक्षण होने के कारण कोई उन्हें रोकता-टोकता भी नहीं है। बता दें कि यहां जिस जिले की बात हो रही है, यह जिला प्रदेश का सबसे संवेदनशील जिला है। नमस्ती गतिविधियों का केंद्र होने के कारण जिले में प्राकृतिक संपदा का भी खूब दोहन हो रहा है।

## करोड़ों का किस्सा... साहब का पुराना रिश्ता

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक आईपीएस अधिकारी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। चर्चा इसलिए हो रही है कि साहब ने प्रदेश के एक कमाऊ विभाग के एक अधिकारी को बचाने के लिए पूरा जोर लगा लिया, लेकिन साहब उन्हें बचा तो नहीं पाए। उल्टे उक्त अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज हो गए हैं। सूत्रों का कहना है कि उक्त आईपीएस अधिकारी अभी हाल ही में दिल्ली से वापस आए हैं। साहब ने जैसे ही प्रदेश में दस्तक दी, उनके पास करोड़ों के घालमेल का एक मामला लेकर एक अधिकारी पहुंच गए। साहब ने बड़ा मामला देखते हुए इसमें हाथ डाला और शराब की निगरानी वाले विभाग में पदस्थ अफसर को बचाने की ठान ली। सूत्रों का कहना है कि साहब ने इसके लिए अपने स्तर पर वह सबकुछ किया, जो वे कर सकते थे। लेकिन विंडबना यह रही कि साहब की दाल तनिक भी नहीं गली। ऊपर से उपरोक्त अफसर का काम और बिगड़ गया। करोड़ों के घालमेल के मामले में उक्त अफसर पर लोकायुक्त ने 420, 120 बी के तहत केस दर्ज कर लिया। बताया जाता है कि उक्त अधिकारी आईपीएस अफसर के नजदीकी हैं। ऐसे में साहब ने अपने तरफ से उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया, पर उनकी विधा के अफसर ही नागवार गुजरे।



## केवल रसोई ही अलग या...

प्रदेश में इन दिनों एक आईपीएस दंपति के वैवाहिक जीवन में आई खटास की हर तरफ चर्चा हो रही है। बताया जाता है कि दंपति ने अपनी-अपनी रसोई अलग कर ली है। केवल रसोई ही अलग हुई है या ये भी अलग हो गए हैं, यह अभी खोज का विषय बना हुआ है। सूत्रों का कहना है कि इस दंपति में पति सात्त्विक और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। वे उसी वर्ग से आते भी हैं। जबकि मैडम तेज तरार प्रवृत्ति की हैं। इनमें से मैडम सीनियर हैं, तो साहब उनसे जूनियर हैं। दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। इस कारण लोगों का यह भी मानना है कि इनके बीच खटास की एक बड़ी वजह वरिष्ठता भी हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि अपनी जाति के हिसाब से साहब हमेशा सौम्य रहते हैं, जबकि मैडम हसीन वादियों से आती हैं और वे हमेशा अपने आपको सर्वोत्तम समझती हैं। जानकारों का कहना है कि साहब और मैडम को जानने वाले यहां तक कहते हैं कि जब ये परिणय सूत्र में बंधे थे, तभी कुछ लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि इनका संबंध लंबा नहीं चलने वाला। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैडम का स्वभाव काफी चंचल किस्म का है। वे किसी बंधन में रहने की आदी नहीं हैं। हालांकि उनकी छवि ईमानदार अफसर की रही है। लेकिन वे अपने जीवनसाथी के प्रति कितनी ईमानदार रही हैं, इसकी खोजबीन शुरू हो गई है। दोनों के संबंधों को लेकर अब लोग तरह-तरह के किस्से-कहानी भी सुनाने लगे हैं।

## जो दिखता है वह बिकता है

चुनावी साल में प्रदेश में घोषणाओं की बरसात हो रही है। सरकार हर किसी को खुश करने की कोशिश में जुटी हुई है। प्रदेश भले ही कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, लेकिन लगता है जैसे सरकार को इसकी तनिक भी चिंता नहीं है। शायद यही वजह है कि सरकार प्रदेश में लगातार लोकलुभावन घोषणाएं कर रही है। सरकारी कर्मचारी हो या आम आदमी सभी को खुश करने का जोरदार अभियान चल रहा है। लेकिन इस अभियान की हकीकत यह है कि घोषणाएं अभी तक पूरी तरह चुनावी ही साबित हुई हैं। क्योंकि चुनावी साल में अब तक जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, उनमें लाडली बहना ही एकमात्र ऐसी योजना है जिसके हितप्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की जा रही है। फिलहाल तो प्रदेश में यही देखने और सुनने को मिल रहा है। बाकी अभी तक जितनी घोषणाएं की गई हैं, उनका लाभ चुनाव बाद ही मिलने की आशा है। हालांकि कई घोषणाओं में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन सरकार का खजाना खाली होने के कारण फिलहाल शायद ही उसका लाभ किसी को मिल पाए।

## फिर काहें के मंत्री...

चुनावी साल में हर नेता और मंत्री की कोशिश होती है कि उसके क्षेत्र, उसके विभाग के कार्यों का जब भी गुणगान हो या सौगात मिले वह फ्रंट पर खड़ा रहे। लेकिन देश के हृदय प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसका ताजा उदाहरण राजधानी भोपाल में आयोजित पथ विक्रेता महासम्मेलन में देखने को मिला। सम्मेलन में सरकार के मुखिया ने घोषणा की कि गांव और शहर में सड़क पर सामान बेचने वालों के पहचान पत्र बनाए जाएंगे। अलग-अलग जगह चिन्हित कर हॉकर्स कॉर्नर बनाए जाएंगे। पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड का गठन होगा। इस पर जमकर तालियां बजाईं, लेकिन इस अवसर पर विभागीय मंत्री का कहीं अता-पता नहीं था। सूत्रों का कहना है कि मंत्री जी तो कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें संदेश दे दिया गया कि आप तो अपने काम में लगे रहो... सरकार के मुखिया हैं तो आपकी कोई विशेष जरूरत नहीं है। उधर, इस दृश्य को देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा होता कि फिर किस काम के और काहें के मंत्री। जब विभाग के कार्यक्रम में मंत्री ही शामिल नहीं होंगे तो उनकी परफॉर्मेंस का आंकलन कैसे किया जाएगा। मंत्री अपनी अहमियत कैसे दिखा पाएंगे?

**अ**ब पूरा मप्र प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रडार पर रहेगा। इसके लिए मप्र में प्रवर्तन निदेशालय का नेटवर्क और बढ़ेगा। प्रदेश के ग्वालियर और जबलपुर जिले में भी अब ईडी का ऑफिस खोला जाएगा। इसे लेकर ईडी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल, प्रदेश में वित्तीय अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय सक्रिय है। प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में बैंक फ्रॉड, वित्तीय अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन जैसे मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने निचले स्तर तक अपना सशक्त नेटवर्क बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। राजधानी भोपाल के ईडी का जोनल ऑफिस खुला है। भोपाल ऑफिस में जल्द ही ज्वाइंट डायरेक्टर की नियुक्ति की जाएगी।

जानकारी के अनुसार मप्र में अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए ईडी ने नई भर्तियां भी शुरू कर दी हैं। राजधानी भोपाल, इंदौर सहित देश के तीन दर्जन बड़े शहरों के लिए डिप्टी व असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे पदों पर बड़ी संख्या में भर्ती के लिए डेपुटेशन पर आवेदन बुलाए गए हैं। ईडी मुख्यालय ने दो महीने पहले सुर्कुलर जारी कर भर्ती का अभियान शुरू किया है। ये अधिकारी भोपाल, इंदौर में पदस्थ किए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की नजर मप्र के भृष्णों पर पड़ गई है। ईडी अफसरों की चल एवं अचल संपत्ति के साथ नौकरी में आने से लेकर अब तक के वेतन का भी हिसाब कर रहा है।

दरअसल, मप्र सहित देशभर में बढ़ रहे आर्थिक अपराधों पर नकेल कसने के लिए ईडी ने अपने आप को सशक्त बनाने की कवायद शुरू कर दी है। मप्र सहित देश के कई राज्यों में बढ़ रहे बैंक फ्रॉड, हवाला जैसे वित्तीय अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन जैसे मामलों को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निचले स्तर तक अपना सशक्त नेटवर्क बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। भोपाल, इंदौर और रायपुर सहित देश के तीन दर्जन बड़े शहरों के लिए डिप्टी एवं असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे पदों पर बड़ी संख्या में भर्ती के लिए डेपुटेशन पर आवेदन बुलाए गए हैं। भोपाल में जोनल ऑफिस खुलने के बाद अब जबलपुर और उसके बाद ग्वालियर में भी ईडी कार्यालय खोलने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। भोपाल जोनल ऑफिस में ज्वाइंट डायरेक्टर की नियुक्ति का इंतजार हो रहा है, अभी अहमदाबाद जेडी के पास भोपाल का अतिरिक्त प्रभार चल रहा है। भोपाल में जोनल ऑफिस खुलने के बाद से यहां इंदौर के ज्यादातर मामलों की जांच ट्रांसफर हो गई है।



## ईडी के रडार पर मप्र जबलपुर में कार्यालय रखोलने की तैयारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इंदौर और भोपाल के बाद जबलपुर में भी आंचलिक कार्यालय खोलने की तैयारी कर रहा है। इसका लाभ यह होगा कि जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग से संबंधित मामले वहीं पर निपटाए जा सकेंगे। आरोपितों को भी पूछताछ के लिए भोपाल लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। शिकायत करने वालों के लिए भी सुविधा हो जाएगी। यहां पर उपसंचालक या सहायक संचालक स्तर के अधिकारी और अन्य स्टाफ रहेगा। ईडी सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में निदेशालय ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। दरअसल, मप्र में मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत शिकायतें बढ़ी हैं। इन शिकायतों की जांच के लिए प्रदेश में ईडी का पर्याप्त अमला नहीं है। इस कारण शिकायतों की जांच और न्यायालय में चालान पेश करने में देरी होती है। इससे आरोपितों को लाभ मिल जाता है। धार्मिक गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिए भी इस क्षेत्र में विदेश से अवैध तरीके से धन मिलने की भी शिकायतें आ चुकी हैं। जबलपुर डायोसिस के बिशप पीसी सिंह के मामले में भी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा प्रकरण दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने जांच शुरू की थी। इसके अलावा आतंकी फंडिंग के मामले में भी विदेशी धन के उपयोग की आशका है। एनआईए और मप्र आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) इस पहलू से जांच कर रहे हैं। गडबडी मिलने पर मामला ईडी को सौंपा जा सकता है।

अब जबलपुर में भी नया ऑफिस खोलने की कार्रवाई चल पड़ी है। महाकौशल में नया कार्यालय खोलने के पांछे तर्क यह है कि जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग से संबंधित मामलों की छानबीन वहीं से होने लगेगी। पड़ताल और पूछताछ के लिए भोपाल तक नहीं आना पड़ेगा। ऐसे मामलों के निपटारे में भी तेजी आएगी। ईडी की छानबीन के चलते जबलपुर डायोसिस के बिशप पीसी सिंह का मामला सुर्खियों में रह चुका है।

वर्तमान में ईडी में दूसरे सरकारी कार्यालयों के अधिकारी काम संभाले हुए हैं। इसको देखते हुए ईडी मुख्यालय ने दो महीने पहले सुर्कुलर जारी कर डेपुटेशन पर बड़ी संख्या में डिप्टी, असिस्टेंट डायरेक्टर की भर्ती का अभियान शुरू किया है। ये अधिकारी भोपाल, इंदौर के अलावा रायपुर में पदस्थ किए जाएंगे। ईडी के ज्यादातर कार्यालयों में मैदानी स्टाफ के बतौर आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और पुलिस विभाग के अधिकारी तैनात हैं। भर्ती सीधे और अन्य जांच एजेंसियों से की जाती है। वरिष्ठ स्तर पर आईआरएस, आईपीएस और आईएएस अधिकारी भी लिए जाते हैं। हाल ही में इंदौर, जबलपुर, सतना और धार में मनी लॉन्ड्रिंग व अन्य मामलों के कारण ईडी की सक्रियता सुर्खियों में रह चुकी है। वित्तीय अपराधों के मामले में जांच अधिकारियों ने कई ठिकानों पर सर्च कर बड़ी संख्या में दस्तावेज आदि जब्त किए हैं। यह जांच एजेंसी खासतौर पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम, विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन और धन शोधन निवारण अधिनियम के मामले अपनी पड़ताल में लेती है।

● सुनील सिंह

**को**

ई विश्वास करे या न करे, लेकिन मप्रवाकई अजब है, जब जब है। इस बात परमप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरणलगातार मुहर लगाता आ रहा है। विभागका एक पुराना मामला

वर्तमान में चर्चा में है। इसकी वजह है जिस अफसर की निगरानी में 2021 में बना पुल भरभारकर गिरगया था, वह जनवरी 2023 में बेदागरिटायर्ड हो गए। ये अफसर हैं

बीएस चंदेल। हैरानी की बात यह है कि जब चंदेल मुख्य महाप्रबंधक थे, तब सिवनी जिले के सुनवारागांव में बैनगंगा नदी पर बना पुल लोकार्पण से पहले ही गिर गया। इस मामले में महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक को निलंबित कर दिया गया, जबकि तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक बीएस चंदेल पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करते हुए उन्हें पुरस्कार स्वरूप मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का प्रमुख अभियंता बना दिया गया।

गौरतलब है कि 2021 में सिवनी जिले के सुनवारा गांव में बैनगंगा नदी पर 150 मीटर लंबा और 9.28 मीटर ऊंचा पुल का निर्माण हो चुका था जिसकी लागत करीब 4 करोड़ आई थी। पुल बनानेवाले भोपाल के ठेकेदार एसवी कंटकशंस कंपनी थी। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को घटियानिर्माण के कारण पुल धराशायी हो गया। पुल धराशायी होने पर तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक बीएस चंदेल द्वारा पुल का निरीक्षण किया और महाप्रबंधक मेहरा, सहायक प्रबंधक एसके अग्रवालको निलंबित करवा दिया, जबकि बीएस चंदेल नेस्वयं को और ठेकेदार को लंबी सांठांग करके बचा लिया। दरअसल, पुल निर्माण में हुई अनियमितताको छिपाने के लिए रिपोर्ट में पुल को बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से गिरना बताया गया।

जानकारों का कहना है कि पुल की डिजाइन में खामी थी, जिसके कारण वह लोकार्पण से पहले ही बह गया। इस बात को चंदेल भलिभांत जानते थे, इसलिए उन्होंने पुल की डिजाइन एवं अन्य खामियोंपर पर्दा डलवा दिया। इसके लिए पुल की जांच बीएस चंदेल द्वारा अपने दो भरोसेमंद महाप्रबंधकोंसे करवाई गई। जांच के बाद कंसलेंसी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया और कार्यवाही का मात्रनाटक किया गया। नियमानुसार विभाग को जांच ब्रिज विशेषज्ञ से कराना चाहिए थी। लेकिन बीएस चंदेल को बचाने के लिए ऐसा खेल खेला गया कि लगे कि इस मामले पर बहुत गंभीरता से काम किया गया है। पुल को टूटे हुए 2 साल से अधिक कासमय हो गया है, लेकिन आज तक इसका जिम्मेदारकौन है, यह तथ्य नहीं हो पाया है। पुल के निर्माणमें खर्च हुए 4 करोड़ रुपए की रिकवरी भी नहीं हो पाई है। उधर, क्षेत्र के ग्रामीण पुल के निर्माणमें भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहनाहै कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क इकाई दो के ठेकेदार ने गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य कराया था जो बाढ़ के



## बेदागरिटायर्ड हो गए दागदार चंदेल



### चंदेल को बचा लिया

जानकारों का कहना है कि पुल के बहने के बाद नियमानुसार उसकी जांच विशेषज्ञों से करवाई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। विभाग के अधिकारी आरोप लगाते हैं कि मंत्री को बीएस चंदेल को मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का प्रमुख अभियंता के पद पर पदोन्नत करना था, इसलिए उन्हें बचा लिया गया। खानापूर्ति के लिए पहले विभाग द्वारा बीएस चंदेल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जब चंदेल ने जवाब भेजा, तो



बीएस चंदेल द्वारा ली गई बैठक में रिटायर्ड अधिकारी क्या कर रहे हैं। चित्र में बाएं से दाएं से रिटायर्ड उपर्याकी और मंत्री के पूर्व ऑफिसरी ब्रजेश श्रीवास्तव एवं दाएं से ग्रामीण यात्रिकी सेवा के प्रमुख अभियंता रिटायर्ड वीके श्रीवास्तव ऑफिसर कार विभागीय मीटिंग में किस उद्देश्य से बैठे हैं।

व्योमिंग नदी पार करने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं है। गौरतलब है कि हाल ही में मप्र कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के किसी मिश्रा ने प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के ओएसडी ब्रजेश श्रीवास्तव के तीन वीडियो जारी कर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मिश्रा के अनुसार श्रीवास्तव मंत्री के अधीनस्थ तत्कालीन प्रमुख अभियंता बीएस चंदेल के कक्ष में विभिन्न संभागों के मजबूत और मजबूर स्थानों से अपने रुठवे के साथ अवैध वसूली की बात कर रहे हैं। मिश्रा का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही इस मामले में संज्ञान नहीं लिया तो मैं जल्द ही एकआईआर कराऊंगा, व्योमिंग सरकारी बैठक में 2 रिटायर्ड अफसर बैठे हैं। चंदेल के बारे में कहा जाता है कि उन पर विभागीय मंत्री की कृपा बरसती रही है। चंदेल पर मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के प्रमुख अभियंता के प्रभार के साथ ग्रामीण यात्रिकी सेवा के प्रमुख अभियंता का भी प्रभार रहा। साथ ही वाल्मी में मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का ट्रेनिंग सेंटर है, उस ट्रेनिंग सेंटर में संचालक का पद भी चंदेल के पास था। हैरानी की बात यह है कि मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के जबलपुर क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक के पद का प्रभार भी इन्हीं के पास था और जनवरी 2023 में सेवानिवृत्त होने तक यह सभी प्रभार इनके पास रहे।

पानी का दबाव नहीं झेल सका। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी पुल निर्माण के दौरान आते थे और खानापूर्ति करके चले जाते थे। जबकि ठेकेदार कंपनी एसडीवी कंसलेंस कंसलेंस भोपाल मनमाने ढंग से पुल का निर्माण करती रही। ग्रामीणों का कहना है कि पुल की गुणवत्ता का आंकलन इसी से लगाया जा सकता है कि बरबसपुर हरदुली से सुनवारा सड़क में बना पुल जब 2021 में 29-30 अगस्त की दरमियानी रात बहा तो उसके निर्माण को एक माह ही हुआ था। बहने से 2 साल पहले पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिसका लोकार्पण होना बाकी था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डैम से पानी छोड़ जाने के बाद नदी के निचले हिस्से में आई बाढ़ के

कारण बैनगंगा नदी के प्रचंड बेग को पुल नहीं झेल सका। पुल का ऊपरी हिस्सा (स्लैब) बाढ़ के पानी के साथ बह गया। वही टाइप के नीचे खड़े किए गए टी गार्डर भी बाढ़ में ध्वस्त हो गए। पुल के कई मीटर लंबे अपार्टमेंट व पेयर नदी में पानी कम होने के बाद पत्थरों के बीच अस्त-व्यस्त हो गए थे। अब इस घटना को 2 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन किसी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। किसी मामले में किसी को सस्पेंड कर देना कार्यवाही के नाम पर मात्र खानापूर्ति ही माना जाता है, जो मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ने 4 करोड़ के पुल बहने के बाद किया।

● जितेंद्र तिवारी



**मग्र में भाजपा ने 230 विधानसभा सीटों में से तीन किसी (39+39+1) में 79 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लेकिन पहली सूची की तरह ही दूसरी सूची जारी होने के बाद असंतोष, विरोध और बगावत तेज हो गई है। दूसरी सूची आने के बाद भाजपा में जनना, सीधी, श्योपुर और नागदा-खावरीद में विरोध शुरू हो गया है। नागदा में टिकट की लेकर खुलकर विरोध शुरू हो गया है। कुलीनों का कुनबा कहे जाने गली भाजपा में पहली बार इस तरह का माहौल देखा जा रहा है। इससे सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि यह असंतोष, विरोध और बगावत मिशन 2023 की राह में भाजपा को भारी न पड़ जाए।**

**म**ग्र में भाजपा ने तीन सूचियों में 79 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दूसरी सूची में 39 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। खास बात यह है कि भाजपा ने इस लिस्ट में तीन केंद्रीय मंत्रियों सहित सात सांसदों पर दांव लगाया है। दरअसल, जिन 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, इनमें से 36 पर पार्टी 2018 के चुनाव में हार गई थी। तीन सीटों पार्टी के कब्जे में आई थी—मैरर से नारगण त्रिपाठी, सीधी से केवरा नाथ शुक्ला और नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल। हालांकि, इस बार तीनों के टिकट काट दिए गए हैं। इस सूची से साबित हो रहा है कि भाजपा इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है और किसी भी हाल में वह यहां जीत हासिल करना चाहती है। तभी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारा है। कमजोर सीटों पर पार्टी को अपनी स्थिति खराब नजर आ रही थी। इसलिए पार्टी ने कददावर नेताओं को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। जानकारों का कहना है कि दूसरी सूची में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें चारों ऐसे वरिष्ठ नेताओं को टिकट दिया गया है, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा सकते हैं। 39 उम्मीदवारों में छह महिला उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 14 एससी-एसटी उम्मीदवार हैं। यह सूची देखकर साफ लगता है कि भाजपा के टिकट वितरण का एकमात्र फॉर्मूला केवल जिताऊ पर दांव लगाना है।

गौरतलब है कि भाजपा ने इस बार प्रदेश में रिकॉर्ड जीत की रणनीति बनाई है। इस रणनीति के आधार पर टिकटों का वितरण किया जा रहा है। पार्टी ने दूसरी सूची में जहां दिग्गजों पर दांव लगाया है, वहीं उन नेताओं को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है, जो पार्टी के लिए परेशानी का सबक बने हुए थे। वहीं ज्योतिरादित्य समर्थकों को मैदान में उतारकर संकेत दिया है।

## क्षत्रियों पर दांव चुनाव जीतो, जिताओ

### दूसरी सूची में ज्योतिरादित्य सिधिया का दबदबा

मग्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्री और मग्र के चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख नरेंद्र सिंह तोमर का नाम मुरैना की दिमनी सीट से घोषित कर पार्टी ने चौकाया है। इस सूची में अंचल की तीन सीटों से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिधिया के समर्थकों को टिकट मिलना भी स्पष्ट संकेत दे रहा है कि पार्टी में उनका दबदबा कायम है। सिधिया ने अपनी खास समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन को डबरा, मोहन सिंह राठड़ को भितरवार और रघुराज कंसाना को मुरैना सीट से टिकट दिलाकर उन आशंकाओं को निर्मल साबित कर दिया है कि 2020 में सिधिया और भाजपा के बीच हुई डील पूरी हो गई है। अब उन्हें पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह रहना होगा। संगठन ने दूसरी सूची में इस बात के भी संकेत दिए हैं कि केंद्रीय मंत्री सिधिया को गवालियर संसदीय क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी। गवालियर जिले की छह विधानसभा सीटों में से दो सिधिया समर्थकों को टिकट मिल चुका है। गवालियर सीट से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम भी लगभग तय है। इस हिसाब से गवालियर में सिधिया की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत हो जाएगी।

की श्रीमंत पर इन्हें जिताने की जिम्मेदारी रहेगी। इंदौर-1 से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को प्रत्याशी बनाया गया है। इस सीट से कांग्रेस के संजय शुक्ला विधायक हैं। कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलने के बाद उनके बेटे व इंदौर-3 से विधायक आकाश विजयवर्गीय का टिकट खतरे में पड़ गया है। मुरैना से सांसद व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से प्रत्याशी बनाया गया है। दिमनी से कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर विधायक हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट मिलने के बाद उनके बेटे रामू तोमर को टिकट मिलना मुश्किल है। रामू गवालियर से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। दिग्गजों-सांसदों को मैदान में उतार पार्टी ने यह संदेश दिया है कि हमारे लिए इस बार एक चेहरा नहीं महत्व नहीं रखता है। पार्टी इस बार जीत का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। फिर वह उसे किसी को भी मैदान में उतारना क्यों न पड़े।

भाजपा की दूसरी सूची काफी चौंकाने वाली है। भाजपा ने नया प्रयोग करते हुए विधानसभा चुनाव में तीन केंद्रीय मंत्रियों समेत सात सांसदों का मैदान में उतारकर सभी को चौंका दिया है। पार्टी ने टिकट वितरण में परिवारवाद पर भी ध्यार से कैंची चला दी है। तीन वर्तमान विधायकों के टिकट काटे गए हैं। पार्टी ने सीधी से भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटकर सांसद रीती पाठक को चुनाव मैदान में उतारा है। केदारनाथ शुक्ला के विधायक प्रतिनिधि का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक आदिवासी पर पेशाब करता नजर आ रहा था। ऐसे ही नरसिंहपुर से विधायक जालम सिंह पटेल का टिकट काटकर उनके भाई व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को मैदान में उतारा गया है। जालम पटेल के स्थान पर उनके भाई प्रहलाद को टिकट देकर पार्टी ने परिवारवाद पर कैंची चला दी है। इसके साथ ही दमोह जिले

में पार्टी के भीतर चल रहे विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। बताया जाता है कि प्रहलाद पटेल की पूर्व मंत्री जयंत मलैया से पटरी नहीं बैठ रही थीं। भाजपा ने मैंहर से विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट काटकर श्रीकांत चतुर्वेदी को चुनाव मैदान में उतारा है। नारायण त्रिपाठी लंबे समय से पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। उन्होंने विंध्य जनता पार्टी नाम से राजनीतिक दल भी बनाया है। इसलिए पार्टी ने उनका टिकट काटकर पिछली बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े श्रीकांत चतुर्वेदी को प्रत्याशी बनाया है। चतुर्वेदी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। पार्टी ने दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारकर उन्हें अपने—अपने क्षेत्र तक सीमित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मप्र चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं। उन पर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी है, लेकिन दिमनी से टिकट मिलने के बाद अब वे वहां ज्यादा सक्रिय रहेंगे। ऐसे ही कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल भी चुनाव में पूरे प्रदेश की बजाय अब अपने—अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाएंगे।

भाजपा की दूसरी सूची लोगों को चौंका रही है कि 2018 में चुनाव जीतने वाले मैंहर से नारायण त्रिपाठी, सीधी से केदारनाथ शुक्ला और नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल के टिकट काट दिए गए हैं। वहीं हरललों को टिकट दिया गया है। इनमें श्योपुर से भाजपा के पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय, मुरैना से रघुराज कंसाना, सेवढ़ा से प्रदीप अग्रवाल, डबरा से इमरती देवी, करैरा से रमेश खटीक, कोतमा से दिलीप जायसवाल, सिहावल से विश्वामित्र पाठक, जुनारदेव से नवथन शाह, खिलचीपुर से हजारीलाल दांगी, थांदला से कल सिंह भाबर, देपालपुर से मनोज पटेल और सैलाना से संगीता चारेल का नाम शामिल है। सिंधिया के साथ भाजपा में आई और 2020 का चुनाव प्रागीलाल हार गए थे। इस बार इनका टिकट काट दिया गया है। भाजपा ने यहां से रमेश खटीक को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा सिंधिया के



करीबी मोहन सिंह राठौर को भितरवार सीट से टिकट दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ राघौगढ़ में भाजपा ने हीरेंद्र सिंह बंटी बना को उम्मीदवार बनाया है। इनके पिता मूल सिंह विधायक रह चुके हैं। हीरेंद्र भी दिग्विजय के करीबी रहे हैं। ये डेढ़ साल पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे। अभी राघौगढ़ में दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह कांग्रेस से विधायक हैं।

भाजपा की दूसरी सूची में जिन तीन केंद्रीय मंत्रियों और चार सांसदों को पार्टी ने चुनावी समर में उतारा हैं, उसके पीछे कई कारण हैं। अबल तो ये कि ये सभी नेता अपने—अपने क्षेत्रों में मजबूत जमीनी पकड़ रखते हैं। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर, गुना और मुरैना में प्रभावी हैं। गणेश सिंह सतना, राकेश सिंह अपने क्षेत्र जबलपुर, उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद, रीति पाठक सीधी क्षेत्र में प्रभावशाली नेता हैं। जो अपनी विधानसभा के अलावा आसपास की कई विधानसभा सीटों को प्रभावित कर पार्टी की झोली में सीटों की संख्या को बढ़ा सकती है। भाजपा की दूसरी सूची में जहां जीते हुए विधायकों के टिकट काटे गए हैं तो वहीं सिंधिया समर्थक नेता जो घिछले उपचुनाव में हार चुके हैं उन्हें एक बार फिर टिकट दिया गया है। दूसरी सूची में सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए 5 नेताओं को टिकट मिला है। इनमें

इमरती देवी, रघुराज कंसाना, हीरेंद्र सिंह बंटी, मोहन राठौर और श्रीकांत चतुर्वेदी का नाम हैं। इमरती देवी और रघुराज कंसाना 2020 में हुए उपचुनाव हार गए थे लेकिन उन्हें फिर से टिकट मिलने से यह साफ हो गया है कि भाजपा में सिंधिया का दबदबा कायम है।

भाजपा ने 79 टिकट घोषित कर दिए हैं। इनमें से 76 टिकट हारी सीटों के हैं। कुल 103 सीटें भाजपा की हारी हुई हैं। अब 27 सीटें और बाकी हैं। इन सीटों को लेकर भी भाजपा सरप्राइज़ चेहरे उतारने की रणनीति अपना सकती है। करीब 12 सीटों पर पूर्व की बैठकों में नाम लगभग तय हो चुके थे, लेकिन फाइनल नहीं होने से घोषित नहीं किए गए। अब आगे मंथन के बाद टिकट घोषित होंगे। गौरतलब है कि जब भाजपा की पहली सूची जारी हुई थी तो 39 में से 16 सीटों पर प्रत्याशियों का विरोध हुआ था, लेकिन पार्टी ने डैमेज कंट्रोल कर लिया। अब दूसरी सूची जारी होने पर 12 से ज्यादा सीटों पर असंतोष के सुर चुलंद हो रहे हैं। विरोध को देखते हुए डैमेज कंट्रोल की जद्दोजहद भी शुरू हो गई है। भाजपा अब आगे की रणनीति बना रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूरेंद्र यादव, संगठन महामंत्री हितनानंद शर्मा व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अलग-अलग बैठकें कर रहे हैं।

● कुमार राजेन्द्र

## तोमर 15, तो फग्गन 33 साल बाद लड़ेंगे विस चुनाव

प्रहलाद पटेल अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। फग्गन सिंह 33 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वे 1990 में विधायक चुने गए थे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद राकेश सिंह भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दिमनी सीट जिस पर तोमर की पसंद का प्रत्याशी होता था, इस बार वे खुद इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी 10 साल बाद फिर युनाव मैदान में उतर रहे हैं। इन्हें भाजपा ने इंदौर-एक सीट से प्रत्याशी बनाया है। दोनों सूची मिलाकर भाजपा ने 230 में से 79 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। दूसरी सूची में भाजपा ने दो विधायकों (केदारनाथ शुक्ला व नारायण त्रिपाठी) के टिकट काटने पर मुहर लग गई है। यानी चार विधायक छाप होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये सूची थोड़ी राहत देने वाली है। इसमें उनके 5 समर्थकों के भी नाम हैं। इमरती देवी के साथ रघुराज सिंह कंसाना, श्रीकांत चतुर्वेदी, हीरेंद्र सिंह बंटी बना, मोहन सिंह राठौर को भी भाजपा ने टिकट दिया है। मोहन सिंह कांग्रेस सरकार के समय मंत्री रहीं इमरती देवी के सहायक भी रहे।

**म** प्र में जल्द ही वाहन फाइनेंस पर लेने वाले वाहन मालिकों को लोन चुका देने के बाद वाहन के रिकार्ड से फाइनेंस निरस्त करवाने के लिए आरटीओ ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोन पूरा होने के बाद फाइनेंस कंपनियां ही परिवहन विभाग के पोर्टल पर वाहन के रिकार्ड के फाइनेंस को निरस्त कर सकेंगी। इसके लिए विभाग नए साल से प्रदेश में नई प्रक्रिया लागू करने जा रहा है।

नया या पुराना वाहन खरीदने पर अगर वाहन खरीदने वाला व्यक्ति पूरी राशि खुद नहीं चुकाता है और उसे किसी बैंक से फाइनेंस करवाता है तो वाहन के रजिस्ट्रेशन में खरीदार के साथ ही फाइनेंस कंपनी भी वाहन की मालिक बनती है। रजिस्ट्रेशन के बक्त इसे रिकार्ड में दर्ज किया जाता है और रजिस्ट्रेशन कार्ड पर भी वाहन के फाइनेंस होने का उल्लेख होता है। लोन पूरा हो जाने पर बैंक द्वारा एक एनओसी जारी की जाती है, जिसमें उल्लेख होता है कि वाहन पर अब कोई लोन बाकी नहीं है। इसे वाहन मालिक द्वारा आरटीओ ऑफिस में जमा करने के साथ फाइनेंस निरस्त करवाने की प्रक्रिया की जाती है, जिसे हाइपोथिकेशन कहा जाता है। इसमें वाहन मालिक को पहले फाइनेंस कंपनी और बाद में आरटीओ ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जिसमें कई बार भ्रष्टाचार का सामना भी करना पड़ता है। वाहन मालिक की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए परिवहन विभाग इस व्यवस्था को ऑनलाइन करने के साथ ही इसके अधिकार फाइनेंस कंपनियों को देने जा रही है। जिसके बाद फाइनेंस कंपनियां ही वाहन पर फाइनेंस चढ़ाने और निरस्त करने की प्रक्रिया कर सकेंगी। देश के कई राज्यों में इस प्रक्रिया को पहले ही लागू किया जा चुका है, अब मप्र का परिवहन विभाग भी इसे लागू करने जा रहा है। इससे परिवहन विभाग पर इस काम का दबाव भी कम होगा और आम लोगों के लिए भी यह काम आसान हो जाएगा।

नई प्रक्रिया से जहां वाहनों के रिकार्ड पर



## अब नहीं लगाने पड़ेंगे आरटीओ के चक्कर...

फाइनेंस चढ़ाने और निरस्त करने का काम फाइनेंस कंपनियों को ही दिए जाने से वाहन मालिकों को सुविधा मिलेगी, वहीं इससे सीजिंग के वाहनों के सीधे ट्रांसफर जैसी गड़बड़ी का रस्ता भी खुल जाएगा। विशेषज्ञों ने बताया कि लोन देते बक्त ही फाइनेंस कंपनियां वाहन मालिक से वाहन ट्रांसफर के दस्तावेज साइन करवा लेती हैं। किश्त ना चुकाने पर फाइनेंस कंपनियां वाहनों को जब्त कर लेती हैं, जिसे सीजिंग कहा जाता है। इसके बाद लोन की भरपाई के लिए इन्हें अन्य लोगों को बेचा या नीलाम किया जाता है। परिवहन कानून कहता है कि ऐसी स्थिति में फाइनेंस कंपनियों को पहले वाहन को अपने नाम ट्रांसफर करवाना होता है और बाद में उसे बेचा जा सकता है, लेकिन अक्सर कंपनियां खर्च से बचने के लिए ऐसा ना करते हुए वाहन को सीधे ट्रांसफर करवाती हैं, जो गलत है। अभी ऐसे कई मामलों में विभाग ट्रांसफर को रोक भी देता है। लेकिन नई प्रक्रिया के बाद विभाग इसे नहीं रोक पाएगा और ऐसे वाहन सीधे पहले मालिक से दूसरे मालिक को ट्रांसफर हो जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि नई प्रक्रिया में फाइनेंस कंपनी द्वारा लोन चुका देने के बाद वाहन के ऑनलाइन रिकार्ड से फाइनेंस निरस्त कर दिया जाएगा। वाहन मालिक डीजी लॉकर या एम-परिवहन एप पर अपडेटेड रजिस्ट्रेशन भी डाउनलोड कर सकेंगे, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर फाइनेंसर का जो नाम प्रिंट है वह तो यथावत रहेगा। इसे बदलने के लिए आवेदक को

आरटीओ ऑफिस में डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा, जिससे उसे नया कार्ड मिलेगा, जिस पर फाइनेंसर का नाम नहीं होगा।

परिवहन अधिकारियों ने बताया कि नई व्यवस्था से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वाहनों के फाइनेंस निरस्त करवाने जैसे फर्जी बाड़े पर भी रोक लग जाएगी। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब वाहन मालिक ने लोन चुकाने से बचने के लिए फाइनेंस कंपनी की फर्जी एनओसी पेश करते हुए फाइनेंस निरस्त करवा लिया और बाद में वाहन को बेच दिया। ऐसे मामलों में फाइनेंस कंपनियां एफआईआर तक दर्ज करवा चुकी हैं। नई व्यवस्था में फाइनेंस निरस्त करने का अधिकार फाइनेंस कंपनियों के पास ही होने पर ऐसी गड़बड़ीयों पर पूरी तरह से रोक लग सकेगी।

इंदौर आरटीओ प्रदीप शर्मा का कहना है कि देश के अन्य प्रदेशों की तरह मप्र में भी वाहनों के फाइनेंस चढ़ाने और निरस्त करने के अधिकार बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को दिए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत फाइनेंस कंपनियों को वाहन पोर्टल पर इस काम का विशेष एक्सेस दिया जाएगा। इसके लिए पोर्टल में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। कंपनियों को भी इसकी जानकारी दी जा रही है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में तीन से चार माह लगेंगे और वर्ष 2024 में लोग इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इससे आवेदकों को काफी सुविधा मिलेगी।

● लोकेंद्र शर्मा

## परमिट ट्रूरिस्ट बस का, ढो रहे सामान्य सवारी

प्रदेश में आने वाली कई ट्रूरिस्ट बसों में बेरोकटोक सवारियां ढोई जा रही हैं। इन बसों के संचालक कभी आईएसबीटी से तो कभी शहर के विभिन्न पिकअप प्यॉइंट्स से सामान्य सवारी बैठाते हैं। लोगों का कहना है कि यह जानकारी आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को है। लेकिन, बस संचालकों के रसूख के चलते उन पर कार्रवाई नहीं होती। इससे बस चालकों की मनमानी बढ़ गई है। मेला, बारात, पर्यटन आदि में लोगों को लाने-ले जाने के लिए ट्रूरिस्ट परमिट जारी किया जाता है। यह 24 घंटे से लेकर एक माह तक का होता है। ट्रूरिस्ट परमिट वाली बसें सफेद रंग की होनी चाहिए। बसों के सामने के शीशे पर ट्रूरिस्ट परमिट की कॉपी चर्पा होनी चाहिए। ये किसी भी सरकारी बस स्टैंड में नहीं जा सकती।

**मु**ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अगर 1.31 करोड़ लाडली बहनों को सस्ता सिलेंडर मिलना शुरू हुआ तो सरकार को हर माह 490 करोड़ सब्सिडी देना पड़ेगा। योजना में अभी गैस रिफिल कराने वाली 20 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी महिलाओं को 60 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी। यदि सभी 82 लाख उज्ज्वला कनेक्शनधारियों को सिलेंडर दिया गया, तो सब्सिडी की राशि बढ़कर 246 करोड़ रुपए हो जाएगी। ऐसे ही लाडली बहनों की बच्ची हुई 49 लाख हितग्राहियों में से करीब 10 लाख के नाम से ही गैस कनेक्शन हैं, उन्हें 50 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी। यदि योजना में इन सभी 49 लाख महिलाओं को सस्ता सिलेंडर दिया गया, तो सब्सिडी के रूप में 245 करोड़ देना होंगे।

खास बात यह है कि इस योजना के दायरे में आने वाली पात्र महिलाओं की संख्या करीब 1 करोड़ 31 लाख है, लेकिन फिलहाल लगभग 30 लाख महिलाओं को ही 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। यह कुल पात्र महिलाओं की संख्या के मुकाबले एक चौथाई से भी कम है। यही वजह है कि सरकार को योजना पर वर्तमान में हर महीने सब्सिडी के बतौर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को महीने दर महीने योजना पर सब्सिडी की राशि बढ़ने का अनुमान है। इसकी दो वजह हैं। पहला, सस्ता सिलेंडर मिलने पर उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी महिलाओं के गैस सिलेंडर भरवाने की संख्या बढ़ेगी। दूसरा जिन लाडली बहनों के नाम अभी गैस कनेक्शन नहीं हैं, वे अपने नाम पर गैस कनेक्शन कराएंगी। जैसे-जैसे महिलाओं के नाम गैस कनेक्शन बढ़ेंगे, योजना में सब्सिडी के रूप में खर्च होने वाली राशि बढ़ेगी।

दरअसल, प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में हितग्राहियों की संख्या 1 करोड़ 31 लाख है। इनमें 82 लाख महिलाएं वे हैं, जो उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी हैं। इनके अलावा बच्ची हुई लाडली बहनों की संख्या 49 लाख है। उज्ज्वला योजना की 82 लाख हितग्राहियों में से सिर्फ 20 लाख महिलाएं ही गैस रिफिल कराती हैं, इसलिए उन्हें ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। बच्ची हुई 62 लाख महिलाएं गैस सिलेंडर महंगा होने के कारण गैस रिफिल नहीं करती हैं। ऐसे ही बच्ची हुई 49 लाख लाडली बहनों में से 10 लाख के नाम पर गैस कनेक्शन हैं। इस तरह सरकार को वर्तमान में योजना में सिर्फ 30 लाख महिलाओं को सब्सिडी देनी पड़ेगी। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने तय किया है कि यदि कोई लाडली बहन भविष्य में अपने नाम पर गैस कनेक्शन करा लेती है, तो उसे भी योजना का

# बहनों को 490 करोड़ की सब्सिडी



## आचार सहित से पहले मिलेगी बहनों को बड़ी सौगात

लाडली बहना योजना शिवराज सरकार के लिए गेमवेंजर है। इस योजना के जरिए महिला वोटरों पर सरकार और पार्टी फोकस कर रही है। हर महीने की 10 तारीख को लाडली बहना योजना की किस्त लाभार्थियों के खाते में पहुंचती है। मुख्यमंत्री शिवराज ने इस योजना की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए करने की घोषणा कर दी है। 250 रुपए रक्षा बंधन से पहले और 1000 रुपए 10 सितंबर को उनके खाते में आ गए हैं। अब दावा किया जा रहा है कि इस बार लाडली बहनों को यह राशि इससे भी ज्यादा बढ़कर यानी 1500 रुपए मिल सकती है। वह भी 2 अक्टूबर को ही। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर आ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि लाडली बहना योजना की पांचवीं किस्त भी इसी कार्यक्रम में प्रदान की जा सकती है। दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यह ऐलान कर चुके हैं कि लाडली बहना योजना की राशि हम बढ़ाकर 3000 रुपए तक ले जाएंगे। तीन महीने बाद ही इसकी राशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई है। वहीं, अब तैयारी है कि 1250 रुपए की जगह इसे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी जाए। अगर ऐसा होता है तो यह भाजपा का बड़ा दांव होगा। दरअसल, कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा की है। शिवराज सरकार की कोशिश है कि हम चुनाव से पहले ही महिलाओं को 1500 रुपए देने लगें। मगर में अभी तक लाडली बहना योजना के तहत 1.32 करोड़ महिलाएं जुड़ चुकी हैं। हर महीने सरकार को इस योजना पर अभी 16000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है कि अब इस योजना में 21 वर्ष की अविवाहित महिलाएं भी शामिल होंगी।

लाभ देते हुए 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। विभाग का अनुमान है कि अक्टूबर से ही योजना में पात्र महिलाओं की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी। प्रमुख सचिव खाद्य उमाकांत उमराव का कहना है कि योजना के दायरे में सभी 1.31 करोड़ महिलाएं आएंगी। यदि कोई लाडली बहन भविष्य में अपने नाम गैस कनेक्शन कराती है, तो उसे भी 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा।

जनसंपर्क एवं लोक स्वास्थ्य योग्यिकी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने महिलाओं की लाडली बहना आवास योजना को महिला कल्याण की अनूठी पहल बताया। रीवा जिले में लगभग एक लाख हितग्राहियों को इस नई आवास योजना से पक्के आवास मिलेंगे। जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों का अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल किया जा रहा है। इसके भी आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। सभी आवेदन-पत्र गांव में ही भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया। जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल, स्थानीय जनप्रतिनिधि रीवा कलेक्टर के एनआईसी कक्ष से कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। कार्यक्रम में रीवा विकासखंड के ग्राम दुआरी की हितग्राही आशा साकेत, सीती यादव, बिनू साकेत, राजकली यादव तथा शंकुलता यादव के आवेदन पत्र भरवाए गए।

● धर्मेंद्र सिंह कथूरिया

**टे** श में सेवा एंव वस्तु कर को लागू हुए करीब 6 साल हो चुके हैं। सरकार लगातार सिस्टम को दुरुस्त करने में लगी है, ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके। लेकिन मप्र में सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों और केक कंपनियों के गठबंधन से सरकार को हर साल अरबों रुपए की चपत लगाई जा रही है। शातिर लोग तरह-तरह से टैक्स चोरी के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा ही टैक्स चोरी का हथकंडा मप्र में सड़कों के निर्माण में अपनाया जा रहा है।

गौरतलब है कि मप्र में सरकार पिछले कई सालों से सड़कों का जाल बिछा रही है। 20 साल में 4.10 लाख किमी सड़कों का निर्माण हुआ है। इन सड़कों के निर्माण में डामर यानी बिटुमेन का उपयोग किया गया है। नियमानुसार प्रदेश में सड़क निर्माण में लगने वाला डामर केवल सरकारी रिफायनरियों से लेने का नियम है। साथ ही ठेकेदारों को डामर का बिल लोक निर्माण विभाग में जमा कराना पड़ता है। लेकिन मप्र में अधिकारियों, ठेकेदारों और कंपनियों की साठगांठ से आयातित डामर का उपयोग किया जा रहा है और सरकारी रिफायनरियों का फर्जी बिल जमा कर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि देश की सरकारी रिफायनरियों से मिलने वाला बिटुमेन ठेकेदारों को महंगा पड़ता है। उस पर उहें जीएसटी का भी भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में नियमों को दरकिनाम कर ठेकेदार ईरान से इम्पोर्ट होने वाला सस्ता बिटुमेन लगाते हैं और सरकारी रिफायनरियों का फर्जी बिल जमा कराकर भुगतान ले रहे हैं। ठेकेदारों की मानें तो इम्पोर्टेंड बिटुमेन की क्वालिटी सरकारी रिफायनरियों जैसी ही है लेकिन 20 प्रतिशत सस्ता होने और उधारी में मिल जाने के कारण इम्पोर्टेंड डामर लगाया जाता है।

लोक निर्माण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में लगातार सड़कों का निर्माण और सुधार का कार्य चलता रहता है। इस कारण प्रदेश में बड़ी मात्रा में डामर का उपयोग होता है। इसको देखते हुए इम्पोर्टेंड डामर के कई सप्लायर प्रदेश में वर्षों से सक्रिय हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में एक सीजन में 500 से 1000 करोड़ का इम्पोर्टेंड डामर बेचा जा रहा है। इस कारण अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए कई लोग अवैध तरीके से डामर सप्लाई करने में लग गए हैं। डामर सप्लायर बकायदा सरकारी रिफायनरी के बिल के साथ डामर देने को राजी हो जाते हैं। इसमें अधिकांश भुगतान नकद में किया जाता है। हमारे पास ऐसे फर्जी बिलों की कॉपी है, जिन्हें सरकारी विभागों में जमा करने के लिए बनाया गया है।

प्रदेश में डामर सप्लाई करने वालों का नेटवर्क कितना सशक्त और शातिर है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि



## मप्र सरकार को करोड़ों का चूना

**मप्र में एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार के विलाफ सरका नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों और कंपनियों की मिलीभगत से सरकार को करोड़ों की चपत लगाई जा रही है। ऐसा मामला प्रदेश में सड़कों के निर्माण में सामने आया है।**

### इसलिए चल रहा रखेल

जानकारी के अनुसार डामर कारोबारी मप्र में ही करीब 2000 करोड़ रुपए तक का कारोबार सालाना करते हैं। क्योंकि सरकारी रिफायनरी की डामर के मुकाबले यह जहां 20 प्रतिशत तक सस्ती होती है। वहीं दूसरी ओर सड़क निर्माण से जुड़े कारोबारियों का मुनाफा बढ़ जाता है। इसके साथ ही बड़े ट्रेडर से थोक में सौदा कर लोकल डामर एंजेंट सड़क ठेकेदारों को सरकारी रिफायनरी के फर्जी बिल के साथ डामर मुहैया कराता है। प्रदेश में लगातार सड़कों के निर्माण और सुधार का कार्य चलता रहता है। इस कारण प्रदेश में बड़ी मात्रा में डामर का उपयोग होता है। यदि इनके ठेकेदारों द्वारा लगाए गए डामर खपत बिलों की जांच कराई जाए तो करोड़ों रुपए का जीएसटी पोटाला सामने आ सकता है। इस संदर्भ में लोक निर्माण विभाग के सचिव आरके मेहरा का कहना है कि अभी कोई शिकायत विभाग को नहीं मिली है। इस तरह के प्रकरणों को रोकने केंद्र सरकार द्वारा जारी परिप्रत्र विचाराधीन है।

रिफायनरियों के नकली बिल बकायदा क्यूआर कोड के साथ तैयार किए जाते हैं। जिसे स्कैन करने पर रिफायनरी का फर्जी बिल पेज खुलता है, जिस पर डामर सप्लाई का फर्जी बिल नंबर और लॉट नंबर दिखाई देता है। जब इस संदर्भ में डामर सप्लाई करने वाले एंजेंटों से बात की तो पता चला कि सरकारी रिफायनरी से 20 प्रतिशत सस्ता डामर 24 घंटे में सप्लाई की गारंटी ली जाती है। साथ ही क्वालिटी टेस्ट करने के बाद भुगतान करने पर भी डामर एंजेंट तैयार हो गए। क्वालिटी की गारंटी के नाम पर कई बड़े ठेकेदारों के नाम भी लिए गए। दरअसल, यह पूरा काम सुनियोजित और साठगांठ से हो रहा है।

डामर के सभी इम्पोर्टर महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। ये इम्पोर्टर सरकारी रिफायनरियों को भी डामर सप्लाई करते हैं, जिसके लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी रिफायनरियां बकायदा टेंडर जारी करती हैं और लाखों टन डामर खरीदा जाता है। ऐसे कई टेंडर दस्तावेज इंटरनेट पर मौजूद हैं। इम्पोर्टेंड डामर के सप्लायर भी यही तर्क देकर ठेकेदारों को डामर की गुणवत्ता पर भरोसा दिलाते हैं। गुजरात, राजस्थान और ऐसे कई राज्यों में इम्पोर्टेंड डामर को कुछ नियम एं शर्तों के साथ मान्यता मिली हुई है। मप्र में इम्पोर्टेंड डामर की आपूर्ति गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों से होती है। यहां से बड़े ट्रेडर थोक में सौदा कर डामर प्रदेश में लाते हैं। इसके बाद लोकल डामर एंजेंटों का काम शुरू होता है जो सरकारी रिफायनरी के फर्जी बिल के साथ ठेकेदारों को डामर सप्लाई कराते हैं।

● कुमार विनोद

**ट** शकों से नक्सली समस्या से जूझ रहे बालाघाट जिले में मप्र पुलिस की हॉकफोर्स को बड़ी सफलता मिली है। 29 सितंबर को

तड़के हॉकफोर्स ने 14 लाख रुपए के ईनामी नक्सली 25 वर्षीय कमलु को मार गिराया है। वह टाडा दडेकसा दलम का सक्रिय सदस्य था। तड़के रूपज्ञर थाना अंतर्गत कुंदल-कोददापार और सोंगुदा के जंगल में एसडीजी बिरसा हॉकफोर्स की जंगल सर्चिंग के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने जवानों पर फायर किया। इसके जवाब में हॉकफोर्स ने भी फायरिंग की और नक्सली कमलु को मार गिराया। वह बीजापुर का रहने वाला है। नक्सली कमलु को मार गिराने के बाद वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आईजी संजय कुमार, एसपी समीर सौरभ और सीईओ हॉकफोर्स ने हालात का जायजा लिया। एसपी समीर सौरभ ने बताया कि मुठभेड़ में कुछ और नक्सली घायल हुए हैं। मुठभेड़ के बाद क्षेत्र के जंगल में सर्चिंग तेज़ कर दी गई है।

मप्र और छत्तीसगढ़ में इन दिनों विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। राजनीतिक पार्टियों के साथ ही शासन-प्रशासन का पूरा फोकस चुनावी तैयारी में है। ऐसे में खुफिया विभाग को खबर मिली है कि चुनावी साल में नक्सली बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के बड़े माओवादी लीडरों ने पिछले 2 महीने से बस्तर में डेरा जमा रखा है। दंतेवाड़, बीजापुर और सुकमा जिले के सरहदी इलाकों में नए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। इनका फोकस छत्तीसगढ़ के इन जिलों के साथ ही मप्र के बालाघाट और मंडला पर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नक्सली मप्र में अपना सेंटर बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। लेकिन पुलिस की लगातार सक्रियता के कारण वे सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए वे छत्तीसगढ़ में युवाओं को ट्रेनिंग देकर मप्र के बालाघाट, मंडला आदि जिलों में भेजने की फिराक में हैं। जानकारी के अनुसार 40 लाख का ईनामी खूंखार नक्सली कमांडर चैतू, डीवीसीएम, एसीएम कैडर के हथियारबंद नक्सली नए युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं।

यह इस वर्ष की तीसरी बड़ी सफलता है। इससे पहले 22 अप्रैल को गढ़ी थाना अंतर्गत कदला के जंगल में बालाघाट पुलिस ने 14-14 लाख रुपए की ईनामी महिला नक्सली एरिया कमांडर और गार्ड भोरम देव में एरिया कमांडर, टांडा दलम और वर्तमान में विस्तार दलम में काम कर रही एसीएम सुनीता और नक्सली कबीर की गार्ड रही खटिया मोचा दलम में एसीएम और वर्तमान में विस्तार दलम में सक्रिय सरिता को मार गिराया था। उनके पास से बंदूकें, कारतूस, बड़ी मात्रा में नक्सली असलहा और खाने-पीने की सामग्री बरामद की गई थी। बीते वर्ष बालाघाट पुलिस ने छह बड़े नक्सलियों को मार



## लम्हे की तैयारी में नक्सली

### लंबे समय बाद दिखी मूवमेंट

पुलिस का दावा है कि, नक्सली कमांडर चैतू हाल ही में इस तरफ आया है। लंबे समय बाद उसका मूवमेंट देखने को मिला। अगस्त में नक्सलियों ने सुकमा-बीजापुर जिले के सरहदी इलाकों में शहीदी सासाह मनाया था। सूत्रों के अनुसार, बड़े नक्सली लीडर आज भी बस्तर के जंगलों में डेरा जमाए बैठे हैं। मीटिंग ली जा रही है। नए कैडर्स की भर्ती कर रहे हैं। चुनाव से पहले बड़े नक्सली हमले की आशंका के बीच फोर्स अलर्ट मोड पर हैं। दक्षिण बस्तर के जिलों में जवानों को लगातार ऑपरेशन पर भेजा जा रहा है। वहीं बालाघाट में भी नक्सलियों की सक्रियता देखी गई है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों जिलों बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में हॉक फोर्स और जिला पुलिस बल को पूरे क्षेत्र की चप्पे-चप्पे पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया है। आशंका जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस की कार्रवाई के डर से सीमावर्ती जिलों के नक्सली में मप्र में दाखिल हो सकते हैं। यहीं वजह है कि किसी भी बड़ी घटना से बचने के लिए पुलिस ने सर्कता बढ़ा दी है। बता दें कि नक्सल प्रभावित तीनों जिलों में करीब 125 नक्सली सक्रिय हैं। इनमें 35 से 40 महिलाएं भी हैं। ज्यादातर नक्सली छत्तीसगढ़ से ही मप्र में आए हैं।

गिराया था। दरअसल, मामला 29 सितंबर की सुबह रूपज्ञर थाना इलाके में कुंदल-कोददापार और सोंगुदा के जंगल का है। जब एसडीजी बिरसा हॉकफोर्स जंगल सर्चिंग पर निकला था। इस दौरान नक्सलियों ने अचानक पुलिस जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें एक नक्सली ढेर हो गया। मरने वाले

नक्सली की पहचान 25 वर्षीय कमलु के रूप में हुई है। ये नक्सली दलम टाडा दडेकसा गेंग का सक्रिय सदस्य था और इस पर 14 लाख रुपए का ईनाम घोषित था। वहाँ, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मुठभेड़ में और भी नक्सली घायल हुए हैं। एक नक्सली की मौत के बाद वो मौके से भागने में कामयाब हो गए। हालांकि, घटना के बाद इलाके में हॉकफोर्स की सर्चिंग तेज़ कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले 22 अप्रैल को गढ़ी थाना इलाके के कदला के जंगल में भी पुलिस ने 14 लाख की ईनामी महिला नक्सली सरिता को मार गिराया था। पुलिस ने महिला नक्सली के पास से बंदूकें, कारतूस, बड़ी मात्रा में नक्सली असलहा समत खाने-पीने का सामान बरामद किया था।

गौरतलब है कि इसी महीने बालाघाट जिले के चौरिया चिलौरा जंगल में सर्चिंग के दौरान हॉकफोर्स तथा सीआरपीएफ की टीम ने नक्सलियों द्वारा डम्प किए गए विस्फोटक बरामद किए हैं। ये विस्फोटक सामग्री नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला करने के उद्देश्य से छुपाकर रखी गई थी। बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के अनुसार जिले के लांजी थानांतर्गत प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिट पार्टी माओवादी के मलाजखंड तथा टांडा दलम के नक्सली सदस्य अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। पुलिस बल तथा सुखबिंदु से सूचना मिली थी कि कुछ नक्सलियों द्वारा इलाके में विस्फोटक रखे जा रहे हैं, जो शायद किसी की हत्या करने के उद्देश्य से रखे गए हैं। नक्सल विरोध अभियान के तहत हॉकफोर्स तथा सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त सर्चिंग अभियान चलाकर लांजी थानांतर्गत चौरिया चिलौरा के जंगल में नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखा गया विस्फोटक बरामद किया।

● प्रवीण सक्सेना

2020 में सत्ता गवाने के बाद कांग्रेस ने मप्र में सरकार बनाने के लिए हर मोर्चे पर चुनावी तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए पार्टी के कृद्वावर नेताओं को क्षेत्रगार जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं भाजपा का मुकाबला करने के लिए आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को मैदानी मोर्चे पर सक्रिय कर दिया है। जबकि संगठन सभालने की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को दे दी है। पार्टी को उम्मीद है कि इस रणनीति से कांग्रेस देश में और मजबूत र संगठित होगी।

**म**प्र में कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है सत्ता में वापसी। इसके लिए अब कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को चुनाव के लिए पूरी तरह प्री हैंड डे दिया है। यानी अब दिग्विजय और कमलनाथ का पूरा फोकस चुनावी रण पर रहेगा। अब कमलनाथ-दिग्विजय अपनी टीम के साथ चुनावी मैदान संभालेंगे। वर्हीं प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के हाथ में संगठन की जिम्मेदारी रहेगी। ताकि कांग्रेस के दिग्गज नेता अपना अधिक से अधिक समय जनता के बीच दे सकें।

गौरतलब है कि मप्र विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी सत्ता को बरकरार रखने की जंग लड़ रही है तो कांग्रेस वापसी के लिए बेताब है। इसके लिए कांग्रेस ने कमलनाथ के चेहरे को आगे कर रखा है तो दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे रहकर सियासी तानाबाना बुन रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति का यह हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि मप्र का राजनीतिक मिजाज हिंदुत्व के रंग में चढ़ा हुआ है। वहीं वजह है कि कमलनाथ फ्रेंटफुट पर तो दिग्विजय बैक डोर से भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का खेल खेल रहे हैं?

बता दें कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ही मप्र में कांग्रेस के धुरी बने हुए हैं, लेकिन दोनों ही उम्र में लगभग बराबर हैं। 76 साल के दोनों कांग्रेसी नेता अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। दोनों ही राज्य के दूसरे नेताओं पर भारी पड़ते हैं। दोनों का गांधी परिवार के साथ अच्छा तालमेल है। पिछले साल जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, तब मलिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आने से पहले तक दोनों नेताओं के नाम इस रेस में लिए गए थे, लेकिन पुराने सियासी घोड़ाओं के बीच समानताएं यहीं खत्म नहीं होती हैं। कमलनाथ पांच साल बाद भी पीसीसी प्रमुख बने हुए हैं और पहले की तुलना में मप्र और मुद्रदों से कहीं ज्यादा परिचित हैं। लेकिन वह सड़क यात्रा से अभी भी बचते हैं। कांग्रेस विधायकों और नेताओं ने पहले कुछ सालों में अक्सर शिकायत की थी कि उन तक पहुंचना आसान नहीं था। माना जाता है कि उन्होंने उन्हें (नेताओं को) केवल मिनटों का समय दिया। वर्हीं, दिग्विजय पहले से ज्यादा फिट हैं और आज भी सड़क मार्ग से लंबी दूरी तय करते हैं। उन्हें उन



## राजनीतिक हिंदू बनाम व्यक्तिगत

जानकार बताते हैं कि कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता धार्मिक हैं, लेकिन दिग्विजय खुद को कमलनाथ के विपरीत सार्वजनिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष दिखाते हैं। कमलनाथ खुद को सार्वजनिक रूप से हनुमान भक्त कहते हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कमलनाथ ने बाबरी मस्जिद के विधंस के बाद भड़के हुए माहौल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धार्मिक शरिष्ठियों की सेना का मुकाबला करने के लिए साधुओं के समूह को काम पर रखा था। साधु अलग-अलग गांवों में जाते थे और जब गांव वाले देखते थे तो नाथ को आशीर्वाद देते थे। वहीं, दिग्विजय सिंह अपने व्यक्तिगत मामलों में कहीं ज्यादा धर्मनिष्ठ हिंदू हैं। वह नियमित रूप से पंद्रहपुर और तिरुपति जैसे स्थानों का दौरा करते रहे हैं और सालभर कई उपवास रखते हैं। हालांकि वह आरएसएस, भाजपा और इसके द्वारा चलाए जा रहे हिंदुत्व के खुले तौर पर आलोचक भी हैं। सार्वजनिक मंच और मीडिया से बात करके हुए दिग्विजय अक्सर भाजपा के हिंदुत्व की अलोचना करते हैं। भगवा आतंकवाद, पुलवामा हमले और बाटला हाउस मुठभेड़ के बारे में दिग्विजय सिंह के आरोपों और आक्षेपों ने कई बार कांग्रेस को एक अजीब स्थिति में डाल दिया। पार्टी को कभी-कभी उनकी टिप्पणियों से खुद को दूर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके विपरीत कमलनाथ भगवा आतंकवाद जैसे विवाद संभावित मुद्दों पर टिप्पणी करने से बचते हैं। वह सार्वजनिक रूप से अपनी हिंदू साख का दिखावा करते हैं और अक्सर अपने निर्वाचन क्षेत्र में खुद के द्वारा बनाई गई 101 फुट ऊँची हनुमान प्रतिमा के बारे में बात करते हैं।

66 विधानसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है, जिस पर पार्टी बार-बार हारती रही है। इस तरह दिग्विजय ने उन्हें 66 सीटों पर अपना फोकस कर रखा है और साथ ही इसमें असहमति के स्वरों को शांत करना और कैडर्स को फिर से सक्रिय करना शामिल है।

वहीं पार्टी की रणनीति के अनुसार विधानसभा चुनाव होने तक अब संगठन के काम से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ दूर रहेंगे। संगठन की कमान अब प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के हाथ में रहेगी। सूत्रों का कहना है कि सुरजेवाला का जोर इस बात पर है कि प्रत्याशी कोई भी हो, चुनाव कांग्रेस संगठन लड़े। इसके लिए संगठन को तैयार किया जा रहा है। नेता समन्वय बनाकर काम करें और

जिम्मेदारियों का निर्धारण भी आपसी सहमति के आधार पर हो ताकि सभी की पूरी क्षमता का उपयोग भाजपा को हराने में किया जा सके। उन्होंने पदाधिकारियों को भी स्पष्ट कर दिया है कि कर्नाटक की तरह सत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संगठन की होगी।

कमलनाथ व दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान के अग्रिम मोर्चे पर रहेंगे। चुनाव प्रचार की कमान इन्हें दोनों नेताओं के हाथों में होगी। प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही कमलनाथ की विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं शुरू होंगी। वहीं, वरिष्ठ नेताओं को भी अलग-अलग अंचलों की जिम्मेदारी देकर भेजा जाएगा। वरिष्ठ विधायकों को आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में भी ध्यान देना होगा। संगठन ने प्रचार अभियान की

कार्ययोजना तैयार की है। जनआक्रोश यात्रा के बाद राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार अभियान की जो कार्ययोजना बनाई है, उस पर काम शुरू हो गया है। इसके तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को संगठन के कामों से मुक्त रखा जाएगा ताकि वे चुनाव प्रबंधन से लेकर प्रचार पर अधिक ध्यान दे सकें। उनके विधानसभा क्षेत्रवार दौरे निर्धारित किए जा रहे हैं, जो प्रत्याशियों की घोषणा के साथ तेज हो जाएंगे। प्रत्याशी चयन को लेकर सितंबर के अंतिम और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बैठकें होंगी, जिसकी तैयारी कमलनाथ वरिष्ठ नेताओं से विचार-विमर्श करके कर रहे हैं। प्रयास यही किया जा रहा है कि वे कम से कम एक बार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अवश्य पहुंचें इसलिए एक दिन में दो से तीन कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भी कार्यक्रम होंगे। वे डेढ़ माह में उन 66 विधानसभा सीटों का दौरा कर चुके हैं, जहां पार्टी लगातार हार रही है। इन क्षेत्रों में प्रत्याशी चयन के बाद दिग्विजय फिर दौरा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि अब संगठन से जुड़े सभी काम प्रदेश प्रभारी रणनीति सिंह सुरजेवाला देखेंगे।

गौरतलब है कि पांच साल पहले मप्र में 2018 विधानसभा चुनाव को 2 महीने से भी कम समय बचा था, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कैमरे पर एक बात कहते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो चुनावों में प्रचार करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि उनके भाषणों का असर कांग्रेस पार्टी को मिलने वाले वोटों पर पड़ता है। दिग्विजय के इस बयान ने सत्ता पर काबिज भाजपा के लिए चारे का काम किया। भाजपा ने दिग्विजय का मजाक उड़ाते हुए दावा किया कि सबसे पुरानी पार्टी ने वोट डाले जाने से पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए। दिग्विजय ने पूरे चुनाव अभियान में खुद को लो-प्रोफाइल रखा था। नतीजों में कांग्रेस को बहुमत से 2 सीटें कम मिली थीं और 15 साल के बाद मप्र की सत्ता में कांग्रेस वापसी करने में कामयाब रही थी। पिछले हफ्ते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1 मई 2018 को उनके प्रदेश



कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले ज्यादातर लोग उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। मई 2018 तक कमलनाथ मप्र में करीब चार दशक बिता चुके थे। इन 40 सालों में ज्यादातर समय वह छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद रहे। 2018 का चुनाव जीतकर वह मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 15 महीने ही चल पाया। कमलनाथ के बयान पर भाजपा ने तंज कसा और कहा कि मप्र में पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने लोगों लिए कुछ नहीं किया।

दिग्विजय सिंह ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले नर्मदा परिक्रमा पूरी की। महीनों तक पवित्र नर्मदा नदी की पैदल यात्रा की। राज्य में कांग्रेस समन्वय समिति के अध्यक्ष नामित किए जाने के बाद उन्होंने एक और यात्रा की, लेकिन ये बहुत अधिक आकर्षण हासिल नहीं कर पाई। कांग्रेस को लंबे समय तक देखने वालों का कहना है कि दिग्विजय सिंह ज्यादातर निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानीय नेताओं को नाम से जानते हैं, जबकि कमलनाथ के साथ ऐसा नहीं

है। दिग्विजय की याददाशत बहुत तेज है। वह मप्र को अपने हाथ के पिछले भाग की तरह जानते हैं। कमलनाथ स्ट्रेटेजी बनाने और नंबर गेम में माहिर हैं। दिग्विजय सिंह एक बेहतर वक्ता भी हैं और कमलनाथ की तुलना में लंबे भाषण दे सकते हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कमलनाथ एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे। जबकि दिग्विजय कई बार बहुत आक्रामक हो जाते हैं और प्रतिद्वंद्वियों को भड़काने के लिए काफी आगे तक बढ़ जाते हैं। कमलनाथ अपने शब्दों को मापते हैं। कमलनाथ के पूरे करियर में कोई विवादित बयान नहीं मिलता। हालांकि, एक पुराने कांग्रेसी नेता, जो अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वह कहते हैं कि कमलनाथ तुनकमिजाज नेता हैं। उनके साथ विश्वास वाली परेशानी भी है। दिग्विजय सिंह के पास संबंध बनाए रखने की कला है। वह छोटी सभाओं में भी चले जाते हैं, लेकिन कमलनाथ को बड़ा दर्शक वर्ग चाहिए होता है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच यहीं अंतर है।

● अरविंद नारद

### 2018 से पहले तक विधानसभा में नहीं रखा था कदम

2018 से पहले उन्हें ना जानने वाला बयान उनकी स्वीकारोक्ति में सच्चाई का अंश है। तब तक वह शायद ही कभी राज्य में रहे। पांच साल पहले जब उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रमुख बनाया गया, तब वह पीसीसी के अपने पिछले दौरे को याद नहीं कर सके। विधायक बनने से पहले उन्होंने कभी मप्र के विधानसभा परिसर में पैर तक हमेशा कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री सेक्टर के दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। कमलनाथ खुद एक बिजनेस टाइकून हैं। एक समय पर वह देश के सबसे अमीर सांसदों में से एक थे। कमलनाथ का अतीत देखा जाए तो पहले उनके चुनाव प्रचार भी हाई क्लास ही रहे हैं। वह अक्सर हेलीकॉप्टर से यात्रा करते थे। वे शाम से पहले घर लौट आते थे। वहीं, दूसरे नेता इसके विपरीत अपने दिन की शुरुआत काफी पहले कर देते थे और देर रात तक प्रचार में लगे रहते थे।

म प्र में आपको अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी होगी, क्योंकि यहां अपराध करने के बाद 8 हजार से अधिक अपराधी फरार हैं। ये अपराधी गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उप्र के हैं।

हालांकि चुनाव को देखते हुए पुलिस सर्वत्र हुई है। वर्हीं पुलिस मुख्यालय ने उपरोक्त राज्यों को पुलिस को इन अपराधियों की रिपोर्ट भेजी है। इन अपराधियों के अलावा इस समय मप्र में 39,893 अपराधी बेल पर जेल से बाहर हैं। इनमें से कई अपराधियों की बेल निरस्त हो चुकी है, लेकिन 52 जिलों की पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है। या तो ये अपराधी राज्य में ही कहाँ छिपकर बैठे हुए हैं या फिर राज्य से फरार हो गए हैं। वर्हीं पैरोल पर जेल से निकले 143 कैदी भी फरार हैं।

दरअसल, चुनाव का समय आते ही पुलिस ने अपराधियों की धर-पकड़ तेज कर दी है। लेकिन प्रदेश में अपराध करने के बाद 8401 बदमाश अपने राज्यों में शरण ले चुके हैं। मप्र पुलिस को लंबे समय से दूसरे राज्यों में बैठे अपराधियों की तलाश है। हालांकि गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिश कर चुकी है लेकिन वे हाथ में नहीं आए। ऐसे अपराधियों की पीएचक्यू ने सूची तैयार की है। जिन्हें मप्र पुलिस ने फरार या फिर नियमित वारंटी घोषित कर दिया है। सभी आरोपी मप्र से सटे हुए राज्यों के हैं। जिन्होंने मप्र में दाखिल होकर अपराध किया। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग निकले।

पुलिस ने अपराधियों की सूची तैयार कर गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उप्र पुलिस को भेजी दी है। सबसे ज्यादा अपराधी उप्र के हैं। जो मप्र से सटे जिलों में अपराध कर फरार हो चुके हैं। पीएचक्यू द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार फरार अपराधियों में छत्तीसगढ़ के 400, गुजरात के 292, महाराष्ट्र के 1111, राजस्थान के 2198 और उप्र के 4400 हैं। पीएचक्यू के अधिकारियों का कहना है कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पड़ोसी राज्य की पुलिस से कई बार संपर्क किया है। उन्हें अपराधियों की जानकारी भी दी जा चुकी है लेकिन गिरफ्तारी के लिए सहयोग नहीं मिलने से सफलता नहीं मिली है। खास बात है कि फरार आरोपियों में नक्सली भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को 46 नक्सलियों की सूची दी गई है। इन पर बालाघात पुलिस ने इनमें भी घोषित किया है। सभी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। मप्र में नक्सली घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं।

फरार अपराधियों के अंकड़े इस बात का संकेत हैं कि मप्र को अपने पड़ोसी राज्यों से समन्वय नहीं है। राज्यों में कानून व्यवस्था के साथ दूसरे राज्यों में अपराध और बदमाशों पर कार्रवाई के लिए हर साल डीजी स्तर के अधिकारियों की कॉर्डिनेशन बैठक होती है। इस

# आपकी सुरक्षा आपके हाथ!



## आतंकी गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं आरोपी

मप्र के पूर्व डीजीपी अरुण गुटरु ने कहा कि ये तो पुलिस की नाकामयाबी है। ये प्रदेश के लिए बड़ा खतरा है। ये आतंकी गतिविधि से लेकर हर तरह का अपराध कर सकते हैं। हो सकता है पुलिस ने इस मामले में भ्रष्टाचार किया हो। ज्यादा दोस्ताना संबंध में आरोपियों को नहीं पकड़ रहे हों। कह देते हों कि आरोपी नहीं मिला। वर्हीं इसके अलावा पुलिस बल भी कम है। वीआईपी सुरक्षा से लेकर कोर्ट के काम भी पुलिस कर रही है। केंद्रीय जेल इंदौर के उप जेल अधीक्षक एसके खरे ने कहा कि संबंधित थानों को कोर्ट के द्वारा जेल के माध्यम से सूचना दी जाती है। उसके बाद पुलिस उसकी तलाश शुरू करती है। वर्हीं एसके खरे का कहना है कि फिलहाल इंदौर केंद्रीय जेल से दो कैदी पैरोल पर बाहर गए थे। उनकी सूचना पुलिस को दी गई है। वर्हीं बात अगर जमानत पर छूटे अपराधियों की करें तो जमानत पर सबसे ज्यादा गवालियर, रायसेन और उज्जैन के आरोपी हैं। इन तीन जिले के आठ हजार से अधिक आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस अब तक इनको पकड़ नहीं पाई है। वर्हीं भिंड, मुरैना, इंदौर, रतलाम, जबलपुर और सागर में भी जमानत पर छूटे आरोपी फरार चल रहे हैं। ये सब मर्डर, नाबालिंग के अपहरण जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधी हैं।

बैठक में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों के सुझाव लिए जाते हैं। खास तौर से सीमा क्षेत्र में पुलिस के बीच में समन्वय पर चर्चा होती है। सवाल यह है कि मप्र के पड़ोसी राज्यों में पुलिस के बीच समन्वय नहीं है। जिसका नतीजा है कि मप्र पुलिस को दूसरे राज्यों को अपराधियों की सूची देने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

वर्हीं प्रदेश में 39,000 से ज्यादा खूंखार अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। मप्र के स्पेशल डीजी ने स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को भेजे आंकड़े में इसकी जानकारी दी है। इस आंकड़े को देख लोग मप्र पुलिस पर तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं। पिछले दिनों डीजी जीपी सिंह ने पुलिस की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट जारी कर दी थी। सिंह ने मप्र के 39 हजार से अधिक बेल जंपर और स्थाई वारंटियों की सूची जारी कर दी। इस सूची के बाद पुलिस अफसरों की कार्रवाई पर सवाल उठे। मामले से राजनीतिक तूल पकड़ा तो सभी जिलों में वारंटियों की धरपकड़ तेज हो गई। नाइट गश्त और कांबिंग

अभियान चलाते हुए अपराधियों को पकड़ा गया। साथ ही पुलिस के सामने कई और चुनौतियां भी हैं।

इस सबके अलावा प्रदेश में जेल से पैरोल पर निकले 143 कैदी भी फरार हैं। फरार कैदियों में भोपाल और उज्जैन में सबसे ज्यादा कैदी हैं। पुलिस अब तक इन्हें पकड़ नहीं पाई है, जबकि कोर्ट में इन्हें पेश करने के लिए ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं। वर्हीं पैरोल पर भी सबसे ज्यादा फरार कैदी भोपाल और उज्जैन की जेलों से हैं। लोगों का कहना है कि अब जब राजधानी भोपाल की पुलिस का यह हाल है तो अन्य जिलों की बात ही छोड़ दीजिए। वर्हीं बात अगर जमानत पर छूटे अपराधियों की करें तो जमानत पर सबसे ज्यादा गवालियर, रायसेन और उज्जैन के आरोपी हैं। इन तीन जिले के आठ हजार से अधिक आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस अब तक इनको पकड़ नहीं पाई है। वर्हीं भिंड, मुरैना, इंदौर, रतलाम, जबलपुर और सागर में भी जमानत पर छूटे आरोपी फरार चल रहे हैं।

● राकेश ग्रोवर

ए

जस्थान के कोटा से शुरू होकर चंबल नदी के किनारे बनने वाला 420 किलोमीटर लंबा अटल प्रोग्रेस-वे फिलहाल अधर में लटका हुआ है। दरअसल, मप्र के किसान अटल प्रोग्रेस-वे के लिए जमीन देने को तैयार नहीं हैं।

इस कारण अटल प्रोग्रेस-वे चंबल के बीहड़े में भटक गया है। ऐसे में अटल प्रोग्रेस-वे का निर्माण पांच वर्ष और पिछड़ सकता है। दरअसल किसानों के विरोध के चलते अब नए सिरे से सर्वे कराकर, डीपीआर तैयार की जा रही है। एक्सप्रेस-वे की जद में कम किसानों की जमीन आए, इसको देखते हुए सर्वे और डीपीआर तैयार की जाती है। इसके चलते 12 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर 17 हजार करोड़ रुपए तक हो सकती है और प्रोजेक्ट कास्ट भी बढ़गी।

उप्र को मप्र के तीन जिलों भिंडि, मुरैना और श्योपुर के रास्ते राजस्थान के कोटा से जोड़ने वाली प्रदेश और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अटल प्रोग्रेस-वे परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई है। पहले तो चंबल के बीहड़ों में बनने वाले प्रोग्रेस-वे को पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली। सरकार ने इसमें बदलाव कर प्रोग्रेस-वे का सर्वे कराया तो किसानों ने जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। इसे देखते हुए मार्च 2023 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्वे निरस्त कर पुनः सर्वे के अदेश दिए पर शासन की ओर से अब तक आगे के लिए कोई प्रक्रिया शुरू न होने से परियोजना ठप पड़ी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार प्रोग्रेस-वे को लेकर गंभीर थी। केंद्र सरकार इसे भारतमाला परियोजना में शामिल कर चुकी है। चुनाव से पहले कोई रास्ता नहीं निकला तो विपक्ष के लिए यह चंबल में बड़ा मुद्दा बनेगा, यह भी तय है। वर्ष 2017 में सरकार ने बीहड़ों से होकर एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा की थी।

गौरतलब है कि एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर भी जारी कर दिया था। हालांकि एनएचएआई ने इस प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया है। शिवराज सरकार ने ग्वालियर-चंबल संभाग में औद्योगिक कॉरिडोर बनाने और इस क्षेत्र को राजस्थान और उप्र से सीधे जोड़ने के लिए अटल प्रोग्रेस-वे की घोषणा वर्ष 2017 में की थी। सर्वे एमपीआरडीसी ने किया। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को भारत माला प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, जिसमें राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण करना था और केंद्र सरकार को इस जमीन पर हाईवे बनाना था। किसान प्रशांत गुर्जर का कहना है कि अगर हम हट जाएंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। जितना मुआवजा मिल रहा है, उतने में यहां जमीन मिलना मुश्किल है। एक्सप्रेस-वे में मप्र की कुल 2700 हेक्टेयर जमीन आ रही है। इसमें मुरैना, श्योपुर और भिंडि जिले के 100 से अधिक



# अधर में अटल प्रोग्रेस-वे

## 404 किलोमीटर लंबा होगा अटल प्रोग्रेस-वे

प्रस्तावित अटल प्रोग्रेस-वे चंबल नदी के किनारे बनाया जाएगा। यह एक्सप्रेस-वे राजस्थान के मशहूर शहर कोटा और उप्र के इटावा को मप्र से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेस-वे की लंबाई 404 किलोमीटर होगी, जिसमें 309 किलोमीटर का हिस्सा मप्र में, 78 किमी राजस्थान और 17 किमी हिस्सा उप्र में होगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 10,000 करोड़ रुपए है। अटल प्रोग्रेस-वे उप्र के शहर इटावा से शुरू होकर मप्र के भिंडि और मुरैना होते हुए कोटा जिले के खातोली से राजस्थान में आएगा। इस एक्सप्रेस-वे के बनने के बाद मप्र में भिंडि, मुरैना, श्योपुर जिले के साथ-साथ आसपास के इलाकों की तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि एक्सप्रेस-वे के दोनों छोर पर लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल सेंटर, कृषि उत्पादन केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, स्मार्ट सिटी, शिक्षा केंद्र, रिजर्ट और कई अन्य संसाधन विकसित किए जाएंगे। इस वजह से इन इलाकों में रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। इस परियोजना से तीनों राज्यों के 200 से अधिक गांवों को बड़ा लाभ मिलेगा। अटल प्रोग्रेस-वे पहले फोरलेन बनाया जाएगा। बढ़ते यातायात को देखते हुए इसे 6 लेन किया जा सकेगा। इसे जंक्शन के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां इस हाईवे को ग्रामीण और स्टेट हाईवे क्रॉस करेंगे और वहां अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे।

किसानों की 2200 हेक्टेयर जमीन और 500 हेक्टेयर जमीन सरकारी हैं। किसानों को जमीन के बदले जमीन देने का सरकार ने वादा किया, लेकिन उसके लिए भी किसान तैयार नहीं हो रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को न तो अभी तक निरस्त किया गया है और न ही पुरानी डीपीआर निरस्त की है।

तीनों जिलों के कलेक्टर को इस नए रूट पर सर्वे करना है। एक्सप्रेस-वे से मप्र, उप्र और राजस्थान को आपस में जोड़ा जाएगा। इसे 306 किलोमीटर मप्र, 72 किमी राजस्थान और 35 किमी उप्र में बनाया जाना है। जब तक नए प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनती है तब तक इसे होल्ड कर दिया गया है। एनएचएआई, (आरओ) मप्र के एसके सिंह का कहना है कि अटल प्रोग्रेस-वे का प्रस्ताव होल्ड कर लिया गया है। नए रूट के संबंध में विचार किया जा रहा है। नए सर्वे रूट में कम से कम भिंडि अधिग्रहण किया जाएगा।

पूर्व में इसका नाम चंबल प्रोग्रेस-वे रखा गया। इसका नाम कई बार बदला गया और अंत में अटल प्रोग्रेस-वे हुआ। 2021 तक इसके अलाइनमेंट का सर्वे हुआ और केंद्र ने इसे भारतमाला परियोजना में शामिल कर लिया, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बीहड़ों में एक्सप्रेस-वे बनाने पर यह कहकर रोक लगा दी कि इससे चंबल नदी के जलीय जीवों व बीहड़ के पर्यावरण को खतरा होगा। इसके बाद सरकार ने बीहड़ से दूर इस एक्सप्रेस-वे को बनाने की योजना बनाई। पहले अलाइनमेंट में 162 गांवों से होकर गुजरने वाला यह एक्सप्रेस-वे नए अलाइनमेंट में चंबल अंचल के 214 गांवों से गुजरता। इसके लिए मुरैना के 110, श्योपुर के 63 और भिंडि के 41 गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण के लिए सर्वे भी हो गया। इसी बीच किसानों का जोरदार विरोध होने लगा और इसका असर यह हुआ कि चार माह पहले मुख्यमंत्री ने सर्वे को निरस्त कर नया सर्वे करने के आदेश दिए। अटल प्रोग्रेस-वे के दूसरे सर्वे में सरकारी क्षेत्र की 140.36 हेक्टेयर, जबकि निजी क्षेत्र की 1778.299 हेक्टेयर जमीन आ रही थी। इससे 3000 से ज्यादा किसान प्रभावित हो रहे थे।

● डॉ. जय सिंह संघर्ष

**य**ह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि मप्र के 50 फीसदी से ज्यादा सरकारी हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट अवैध हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन सरकारी प्रोजेक्टों में बिक्री भी नियमों-प्रावधानों को ताक पर रख की जा रही है।

यह मामला रेरा कानून से जुड़ा है। राजधानी का हाल यह है कि भोपाल नगर निगम के 16 प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है। इनकी लागत भी डेढ़ हजार करोड़ से

ज्यादा है। इसके अलावा अलग-अलग नगरीय निकायों में करीब साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए लागत के सरकारी प्रोजेक्ट भी अवैध हैं।

दरअसल, इसका खुलासा भी रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के हाउसिंग प्रोजेक्ट की संख्या के आधार पर हुआ। रेरा में नगरीय प्रशासन के तहत आने वाले 50 फीसदी प्रोजेक्ट का पंजीयन ही नहीं है। मामले पर रेरा भी एक्शन की तैयारी में है। रेरा में सरकारी एजेंसियों की मनमानी को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। सूत्रों की मानें तो रेरा ने भी नगरीय विकास एवं आवास विभाग से हाउसिंग प्रोजेक्ट का खाका मांगा है। बता दें कि रेरा कानून के तहत बिना पंजीयन सरकारी या निजी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अवैध की श्रेणी में आता है।

बीते माह रेरा ने भोपाल के जोन नंबर 21 के वार्ड क्रमांक 26 में आने वाले नीलबड़ क्षेत्र में 104 दुकान निर्माण मामले को लेकर 1 लाख रुपए का जुर्माना नगर निगम पर लगाया था। यहां नगर निगम ने सरकारी दुकानों का निर्माण बिना रेरा पंजीयन के किया था। साथ ही निगम के सभी व्यवसायिक और आवासीय प्रोजेक्ट पर प्रतिबंध लगाया है। यह शर्त भी रखी है कि जब तक जुर्माने की राशि जमा नहीं कराई जाएगी। तब तक बुकिंग समेत बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। रेरा में आरटीआई एक्टिविस्ट नितिन सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था कि रेरा पंजीयन के बिना नगर निगम अवैध निर्माण कर गैरकानूनी तरीके से बुकिंग कर रहा है। लिहाजा बीते 28 जून को रेरा ने जुर्माना ठोका और बुकिंग समेत बिक्री पर रोक लगाई। शिकायत में यह भी बताया गया था कि जब भोपाल नगर निगम का यह हाल है तो प्रदेश की अन्य नगर पालिका और परिषदों का क्या होगा।

रेरा कानून खरीदारों समेत निर्माण एजेंसियों के हितों की रक्षा के लिए लागू किया गया। रेरा पंजीयन के बिना प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर में कारोबार संभव नहीं है। कारण यह है कि रेरा पंजीयन के बाद प्रोजेक्ट की समय सीमा पर पूरा करने के साथ जारी लेआउट पर ही निर्माण किया जा सकता है। समय पर निर्माण पूरा हो सके,

## कई सरकारी प्रोजेक्ट अवैध



### यहाँ उड़ाई जा रहीं धज्जियाँ

जिन निकायों में रेरा कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उनमें भोपाल नगर निगम, इंदौर नगर निगम, उज्जैन नगर निगम, जबलपुर नगर निगम, सिंगराली नगर निगम, मुरैना नगर निगम, कटनी नगर निगम, रीता नगर निगम, सागर नगर निगम, ग्वालियर नगर निगम, देवास नगर निगम आदि शामिल हैं। वहीं भोपाल नगर निगम के जिन प्रोजेक्ट में रेरा पंजीयन नहीं है, उनमें नीलबड़ प्रोजेक्ट, कलखेड़ी प्रोजेक्ट, रासलाखेड़ी प्रोजेक्ट, समर्धा प्रोजेक्ट, आलम नगर प्रोजेक्ट आदि शामिल हैं। भोपाल नगर निगम के नीलबड़ मामले में रेरा ने आदेश दिया था कि जब तक जुर्माना जमा नहीं कराया जाएगा, तब तक किसी भी प्रोजेक्ट में बुकिंग और बिक्री नहीं की जा सकेगी। इसके बाद भी एक दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट में बिक्री जारी है। अब याचिकाकर्ता ने रेरा आदेश की अवामानना की शिकायत दर्ज कराई है।

इसके लिए रेरा कानून के तहत अलग से अकाउंट खोला जाता है। प्रोजेक्ट में निर्माण के लिए राशि आहरण के लिए रेरा को जानकारी देनी होती है। हर तीन माह में प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जमा करनी होती है, ताकि समय पर और ब्रोशर में दिखाए लेआउट के आधार पर ही निर्माण हो सके। रेरा कानून के तहत रियल एस्टेट सेक्टर की निजी और सरकारी दोनों ही एजेंसियों के प्रोजेक्ट का पंजीयन अनिवार्य है।

राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां नगर निगम जिन प्रोजेक्टों में नियम विरुद्ध बुकिंग कर रहा है, उनमें ईडब्ल्यूएस व 1 बीएच के श्रेणी के कलखेड़ी प्रोजेक्ट में आवास बुकिंग संख्या-260, क्षेत्रफल-430 वर्ग फीट, कीमत-5 लाख 50 हजार रुपए, मालीखेड़ी प्रोजेक्ट में आवास बुकिंग संख्या-60, क्षेत्रफल-430 वर्ग फीट,

कीमत-5 लाख 25 हजार रुपए, भौंरी प्रोजेक्ट-आवास बुकिंग संख्या-500, क्षेत्रफल-430, कीमत-6 लाख रुपए है। वर्ही स्वतंत्र आवास श्रेणी में भौंरी प्रोजेक्ट (3बीएचके)-आवास बुकिंग संख्या-330, क्षेत्रफल-1700 वर्ग फीट, कीमत-35 लाख रुपए, कलखेड़ी प्रोजेक्ट (1बीएचके)-आवास बुकिंग संख्या-80, क्षेत्रफल-1000 वर्ग फीट, कीमत-21 लाख रुपए, रासलाखेड़ी प्रोजेक्ट (एलआईजी, 1 बीएचके)-आवास बुकिंग संख्या-3, क्षेत्रफल-1 हजार वर्ग फीट, 48 लाख रुपए, रासलाखेड़ी प्रोजेक्ट (एमआईजी, 3 बीएचके)-आवास बुकिंग संख्या-40, क्षेत्रफल-1440, कीमत-55 लाख रुपए। इसी प्रकार भूखंड श्रेणी में कलखेड़ी प्रोजेक्ट-प्लाट बुकिंग संख्या-100, क्षेत्रफल-1250 वर्ग फीट, कीमत-16 लाख रुपए है।

वर्ही एमआईजी (3बीएचके) श्रेणी में बागमुगालिया प्रोजेक्ट-आवास बुकिंग संख्या-144, क्षेत्रफल-865 वर्ग फीट, कीमत-25 लाख रुपए, कोकता प्रोजेक्ट-आवास बुकिंग संख्या-330, क्षेत्रफल-868 वर्गफीट, कीमत-18 लाख 50 हजार रुपए है। इसी तरह एलआईजी (2 बीएचके) श्रेणी में नीलबड़ प्रोजेक्ट-आवास बुकिंग संख्या-60, क्षेत्रफल-748 से 875 वर्ग फीट, कीमत-22 लाख 50 हजार से 26 लाख रुपए, बागमुगालिया प्रोजेक्ट-आवास बुकिंग संख्या-200, क्षेत्रफल-704 वर्ग फीट, कीमत-20 लाख रुपए, भानपुर प्रोजेक्ट-आवास बुकिंग संख्या-260, क्षेत्रफल-703 वर्ग फीट, कीमत-16 लाख रुपए, कोकता प्रोजेक्ट-आवास बुकिंग संख्या-200, क्षेत्रफल-704 वर्ग फीट, कीमत-14 लाख 50 हजार, आलम नगर प्रोजेक्ट-आवास बुकिंग संख्या-64, क्षेत्रफल-704 वर्ग फीट, कीमत-22 लाख रुपए, समर्धा प्रोजेक्ट-आवास बुकिंग संख्या-45, क्षेत्रफल-1165 वर्ग फीट, कीमत-32 लाख 50 हजार रुपए है।

● श्याम सिंह सिक्करवार

**ज** इंदिल्ली में आयोजित जी-20 सम्मेलन में विभिन्न देशों के बीच भारत-मध्य पूर्व-यूरोप अर्थिक गलियारा (आईएमईसी) पर बनी सहमति एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। स्वेज नहर के बाद यह पहला अवसर है जब अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के क्षेत्र में एक ऐसी परियोजना पर सहमति बनी है, जो वैश्विक व्यापार के अर्थशास्त्र को क्रांतिकारी रूप से बदल देगी। आर्थिक तौर पर इस परियोजना के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भारत, सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने हस्ताक्षर किया है। भविष्य में मध्य पूर्व, यूरोप के अन्य देशों की भी इसमें भागीदारी की पूरी संभावना है।

आठ हजार किलोमीटर से अधिक लंबे इस परिवहन रूट में दो गलियारे होंगे। पूर्वी गलियारा भारत के मुंबई बंदरगाह से शुरू होकर दुबई तक समुद्री परिवहन के माध्यम से कनेक्ट होगा। दूसरा हिस्सा उत्तरी गलियारा होगा जो रेल मार्ग के माध्यम से पश्चिम एशिया के अरब देशों को सुदूर उत्तरी यूरोप से जोड़ेगा। डिजिटल कनेक्टिविटी और हाइड्रोजन ऊर्जा पाइपलाइन की व्यवस्था भी इसके साथ-साथ सामान्तर रूप में विकसित करने की योजना है। इस परिवहन मार्ग के विकसित होने से भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोप के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। इससे विभिन्न देशों के बीच व्यापार लागत में कमी होने के साथ ही अर्थिक सञ्जोतारों के नए द्वारा खुलने की उम्मीद है। योजना से विभिन्न देशों में रोजगार के अवसर बनेंगे, साथ ही ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की मात्रा में काफी कमी होगी जो कि वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में सहायक होगा। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इसे चीन की बेलं एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआईसी) का जवाब मान रहे हैं। एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली प्रतिक्रिया थी, यह सही अर्थ में बड़ा समझौता है। यह परिदृश्य को बदल देने वाला क्षेत्रीय निवेश होगा। वहीं इंजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो स्वयं अपने देश के नागरिकों को यह खबर सुनाई। नागरिकों को संबोधित अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, इंजरायल के नागरिकों, यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बड़ी खबर सुना रहा हूँ। एशिया-यूरोप के बीच एक अभूतपूर्व सहमति बनी है। इंडिया-मध्य पूर्व-यूरोप परिवहन लिंक एक दीर्घकालीन विकास दृष्टि को साकार करेगा। यह इंजरायल समेत समूचे मध्य पूर्व के परिदृश्य को बदल देगा, साथ ही पूरी दुनिया को भी प्रभावित करेगा।

यह तो सतही आंकलन से ही सिद्ध हो जाता है कि आईएमईसी व्यापारिक दृष्टि से भारत के लिए अत्यंत लाभदायक है। गौरतलब है कि भारत बड़ी मात्रा में अरब देश से पेट्रोलियम का आयात करता



## भारत-अरब-यूरोप व्यापार कॉरिडोर का महत्व

### आईएमईसी परियोजना का महत्व

यह परियोजना भारत (भारतीय उपमहाद्वीप), मध्य पूर्व (इंजरायल समेत करीब दो-तिहाई अरब देश), यूरोप (लगभग समूचा यूरोप) और अफ्रीका (आशिक) क्षेत्र के करीब दो दर्जन देशों को प्रत्यक्ष अर्थिक लाभ प्रदान करेगा। वहीं अमेरिका समेत दुनिया के ऑर्ब से अधिक देशों के लिए भी यह अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक-सामरिक दृष्टिकोण से हितकर सिद्ध होगा। परियोजना के रूट पर सीधे तौर पर नहीं आने के बावजूद इंजरायल द्वारा इस परियोजना में अत्यधिक गंभीरता प्रकट करना और लिंक से सर्वथा दूर होने के बावजूद अमेरिका की इस परियोजना में सक्रिय सहभागिता, इस बात का संकेत है कि इसका बहुआयामी वैश्विक महत्व है, जिनमें वैश्विक राजनीति, शक्ति का संतुलन, सामरिक समीकरण आदि शामिल हैं।

रहा है। आयात के जो वर्तमान मार्ग हैं वे काफी खर्ची हैं, इस मार्ग के विकसित होने पर भारत के लिए अरब देशों से पेट्रोलियम (गैस समेत) और यूरोप से मशीनरी, वाहन, रसायनों के आयात सस्ते होंगे। गौरतलब है कि भारत फिलहाल यूरोप से करीब 1200 बिलियन रुपए का आयात करता है। वहीं लागत खर्च कम होने से अरब और यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, जो कि फिलहाल परिवहन लागत के कारण उम्मीद से कम है। इस तरह भारत के लिए यह दोहरे लाभ की स्थिति होगी। लेकिन व्यापारिक लाभ के अतिरिक्त यह परियोजना भारत के लिए रणनीतिक महत्व का भी है। आज से 10 साल पूर्व चीन ने एक अप्रत्याशित अंतर्राष्ट्रीय परिवहन रूट के तहत अति चर्चित बीआरआई की शुरुआत की थी, जिसके एक भाग का नक्शा आईएमईसी की तरह ही है। प्रस्तावित बीआरआई को आसान नहीं होगी। एमओयू के अनुसार, हस्ताक्षरकर्ता देश अगले दो महीने में परियोजना को धारातल पर उतारने के लिए बैठक करेंगे। इन बैठकों की सफलता ही परियोजना का भविष्य तय करेगी।

● राजेश बोरकर

है, इसलिए भारत हमेशा से इसका विरोध करता रहा है।

भारत के तीखे विरोध के बावजूद चीन इस पर 2018 से लगातार निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं। यह बात अलग है कि कई कारणों से इसकी प्रगति अपेक्षा से अत्यंत धीमी है। लेकिन बीआरआई के कार्यरत होने से जहां चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की सामरिक चुनौतियों में वृद्धि होगी, वहीं भारत के आयात-निर्यात भी इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। लेकिन बीते वर्षों में चीन ने बीआरआई के पक्ष में दुनिया के 100 से अधिक देशों को अपने साथ लाने में सफलता प्राप्त कर, अमेरिका, भारत, इंजरायल, जापान आदि देशों को चिंता में डाल रखा है। लंबे समय से बीआरआई की काट खोजी जा रही थी। असल में आईएमईसी की अवधारणा में बीआरआई की सर्वाधिक असरदार काट छिपी हुई है। यही कारण है कि बातचीत के जरिए जिन देशों को अमेरिका बीआरआई से बीते 10 वर्षों में अलग नहीं कर सका, वह काम आईएमईसी के एमओयू पर दस्तखत होते ही आरंभ हो गया है। इंटर्ली बीआरआई का सदस्य देश है, लेकिन उसने चीन की परवाह किए बिना आईएमईसी पर हस्ताक्षर कर दिया है। वैश्विक राजनीति के जानकारों का मानना है कि आईएमईसी जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाएगा, बीआरआई के कई सदस्य देश उससे बाहर निकलते जाएंगे। उल्लेखनीय है कि समय-समय पर दुनिया के कई रणनीतिक विश्लेषकों ने चीन द्वारा बीआरआई के सामरिक उपयोग की आशंका व्यक्त की है। बहरहाल, आईएमईसी को लेकर भारत समेत कई देशों में भारी उत्साह है, लेकिन इसके धरातल पर उतारने की प्रक्रिया आसान नहीं होगी। एमओयू के अनुसार, हस्ताक्षरकर्ता देश अगले दो महीने में परियोजना को धारातल पर उतारने के लिए बैठक करेंगे।

जं

गलों की तरफ बढ़ते विकास कार्यों से वनों और वन्य जीवों का दायरा घट रहा है। पिछले 10 वर्ष में 31 हजार हेक्टेयर

से ज्यादा वन भूमि विकास कार्यों की चपेट में आ चुकी है।

वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार इन वर्षों में सिंचाई, विद्युत, खनिज और रोड सहित अन्य 371 बड़ी परियोजनाएं लॉन्च की गईं। केन-बेतवा लिंक परियोजना, बंदर हीरा

खदान सहित करीब छह बांध परियोजनाएं वन भूमि में शुरू होनी हैं। इसमें लगभग 10 हजार हेक्टेयर वन भूमि जाएगी।

वनों की वैध-अवैध कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। वन्य जीवों को विचरण में भी परेशानी आ रही है। उनका दायरा सिमट रहा है। नवीजतन टेरिटोरियल फाइट से प्रतिवर्ष औसतन करीब 12 बाघ जान गंवा रहे हैं।

शाकाहारी, अन्य वन्य जीव पर्याप्त जगह और चारागाह की समस्या के चलते गांव की तरफ भागते हैं। खेत की फेंसिंग में फंस जाते हैं या शिकार हो जाता है या फिर कुएं में गिर जाते हैं।

पिछले 10 से 15 सालों के अंदर वन अधिकार पट्टे के तहत वनवासियों को 3 लाख 14 हजार भूमि दे दी गई। फिलहाल 50 हजार वनवासियों को वन अधिकार पट्टे देने की कार्रवाई फिर से की जा रही है। देखा जाए तो वन अधिकार पट्टों के अलावा 1980 से अब तक विभिन्न कार्यों के लिए करीब 2 लाख 90 हजार हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।

साल दर साल इंदौर जिले का वन्य क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है और जंगल घटते जा रहे हैं। वन विभाग की जमीन पर जंगल की जगह, सरकारी परियोजनाओं से संबंधित विकास कार्य लगातार जारी हैं। वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 5 सालों में लगभग 1200 हेक्टेयर से ज्यादा वन्य क्षेत्र में जंगल घट चुके हैं और यह सिलसिला आज भी जारी है। वन विभाग के पास यह रिकॉर्ड तो है कि किस विभाग को कितनी जमीन दी, मगर हर साल लकड़ी माफिया ने पेड़ काटकर कितना जंगल साफ कर दिया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है।

जहां नेशनल हाइवे, रेलवे, उद्योग, एयरपोर्ट आईआईटी कॉलेज, मेट्रो ट्रेन डिपो चोरल बेरछा फायरिंग रेंज, पीडब्ल्यूडी, विद्युत वितरण कंपनी की पावर ग्रिड, नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना, इंडस्ट्री क्लस्टर संबंधित सरकारी विकास कार्यों के चलते जंगल लगातार घटे हैं तो वहाँ वन्य क्षेत्र में अवैध कब्जों और लकड़ी माफियाओं के कारण भी जंगलों का नुकसान जारी है। वैसे तो वन विभाग कई विभागों को वन्य भूमि आवंटित कर चुका है। कुछ विभागों के लिए भूमि आवंटन

## जंगलों को निगल रहे विकास कार्य



### हर साल 3 आग से 2 लाख हेक्टेयर जंगल हो जाता है नष्ट

मप्र में 94,689 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। इसमें 61,886 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन, 31,098 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन और 1705 वर्ग किलोमीटर अन्य वन क्षेत्र है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जंगलों में आग लगने की घटनाओं के मामले में ओडिशा के बाद मप्र दूसरे नंबर पर है। हर साल आगजनी की घटनाओं के कारण जंगल में चारे का संकट खड़ा हो जाता है। इससे पेड़-पौधों के साथ जीव-जंतुओं को भी नुकसान होता है। वन्य प्राणियों को भोजन की तलाश में दूर तक प्रवास करना पड़ता है। 2019 में केंद्र ने जंगल की आग की घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। राष्ट्रीय आपदा मिशन के अनुसार 95 प्रतिशत घटनाएं मानवजनित होती हैं। ट्राइबल बेल्ट में अब भी आस्था के नाम पर मन्त्र पूरी होने पर जंगलों में आग लगा दी जाती है। इससे भी हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल नष्ट हो जाता है। विदिशा, दमोह, डिडोरी और देवास में सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। वन विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से दो सैटेलाइट से आगजनी की घटनाओं की लगातार जानकारी हासिल करता है। अधिकारियों का कहना है कि हर दो घंटे में जंगल का डाटा मिलता रहता है। इसके बाद सैटेलाइट इमेज की मदद से संबंधित क्षेत्र में आग को फैलने से रोकने और बुझाने का काम होता है। प्रदेश में जंगलों के आसपास रहने वाले 35 हजार लोगों को जोड़ा गया है। जिन्हें मैसेज भेजकर आग लगने की सूचना दी जाती है। हालांकि, कई मामलों में मैसेज पहुंचने में 6 से 12 घंटे तक का समय लग जाता है। जब तक आग बड़े वन क्षेत्र को नष्ट कर चुकी होती है। हालांकि, अफसरों का दावा है कि इस बार तैयारियां पूरी हैं।

के प्रस्ताव लंबित हैं। जिसमें जिला उद्योग व्यापार केंद्र और एमपीआईडीसी शामिल है।

इंदौर वन विभाग के अनुसार उन्होंने भारत सरकार, मप्र सरकार जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर वन्य क्षेत्र की जितनी भूमि आवंटित की है इसके बदले में वन विभाग को काटे गए पेड़ों की मुआवजा राशि के अलावा दूसरी जगहों पर जंगल बनाने के लिए बंजर और पथरीली जमीनें मिली हैं। यहां पर जंगल बनाने में लगभग 10 से 15 साल लगेंगे। इंदौर वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार इंदौर जिले का कुल क्षेत्रफल 3898 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 710 वर्ग किलोमीटर में वन्य भूमि और जंगल है। इसी में से लगभग 1200 हेक्टेयर जमीन सरकारी विभागों को दी गई है।

लगभग 1200 हेक्टेयर जमीन वन विभाग ने जहां सरकारी प्रोजेक्ट के लिए दी है तो वहाँ जंगल में सैकड़ों जगह अवैध कब्जे भी हैं।

लकड़ी माफिया के साथ मिलकर पेड़ों का सफाया कर जंगल की जमीन पर खेती की जा रही है। वन विभाग के अनुसार पिछले 5 सालों में 679,880 हेक्टेयर जमीन पर 850 से ज्यादा अवैध कब्जे हो चुके हैं। वन विभाग की तामाम कोशिशों के बाद कब्जे हटाने वन विभाग नाकाम रहा है। उधर कब्जे करने वालों को भरोसा है कि आज नहीं तो कल सरकार बोट बैंक के लिए कब्जे की जमीन पर उन्हें सरकारी पट्टे दे देंगी। इसलिए हर साल अवैध कब्जों की संख्या बढ़ती जा रही है। वन विभाग इंदौर के डीएफओ नंदेंद्र पंडवा का कहना है कि विगत सालों में सरकारी परियोजनाओं से संबंधित विकास कार्यों के लिए सरकार और प्रशासन की अनुसंसा पर लगभग 1200 हेक्टेयर जमीन देने की वजह से वन्य भूमि पर मौजूद जंगल घटे हैं। दूसरी जगह इतना बड़ा जंगल तैयार करने में 10 से 15 साल लगेंगे।

● विकास दुबे

**बुंदेलखंड** जनपद विशेषकर दक्षिणी-पूर्वी बुंदेलखंड की भूमि पहाड़ी, पठारी, ढालू, ऊंची-नीची, पथरीली, ककरीली रांकड़, शुष्क वनों से भरपूर है। इस भूभाग की जमीन पर बरसाती जल ठहरता ही नहीं है,

जिसके कारण बुंदेलखंड में पानी की कमी सदैव बनी रहती थी। करीब सबा करोड़ की आबादी वाले बुंदेलखंड में पीने का पानी जुटाना बहुत से लोगों के लिए रोजाना का संघर्ष है। जनपद के महोबा जिले की रहने वाली धनवंतरी ये कहते हुए भावुक हो जाती हैं और वो बताती हैं कि घर के पास लगा हैंडपंप काम नहीं करता था उसमें काफी मेहनत के बाद पानी आता थी तो गंदा आता था। इसलिए वो घर से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर जाकर पानी लाती थी। पुराने समय में चंदेलों-बुंदेलों, गाँड़ राजाओं और मराठाओं, समेत अंग्रेजों ने इस जल अभाव ग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल मिलाकर 4000 से अधिक तालाबों का निर्माण कराया था। जिसमें से अधिकांश तालाब सूख चुके हैं, लेकिन बचे हुए जल स्रोत आज इस इलाके के लिए वरदान साबित हो रहे हैं व्योंगीक उप्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। जो आज बुंदेलखंड इलाके में बड़ी योजना साबित हो रही है।

पथरीली जमीनों पर पीने के पानी के लिए पाइप लाइन बिछाने, गांव-गांव पानी की टंकियों को बनाने, बाटर ट्राईटर्मेंट प्लांट बनाने, जल स्त्रोतों को बढ़ाने और घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का काम तेजी से किया गया। भारत सरकार की हर घर जल योजना को योगी सरकार ने राज्य के उन जिलों में प्राथमिकता से लागू किया जहां पानी की समस्या कई सालों से चिंता का कारण थी। जल जीवन मिशन का उद्देश्य उप्र में वर्ष 2024 तक 2,62,29,815 परिवारों तक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है, हर घर जल योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण को प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की जानी है। ऐसा देखा जा रहा है कि जल जीवन मिशन योजना से 14 सितंबर 2023 तक 1,60,20,616 परिवारों को नल से जल की सुविधा पहुंचाई जा चुकी है। ऐसे में कुल 9,61,23,696 लोग इस योजना से लाभांश्वत हो रहे हैं। घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचने से बुंदेलखंडी महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। खासकर बुंदेलखंड और विंध्य में महिलाओं को मीलों दूर से पानी भरकर लाना पड़ता था, लेकिन जल जीवन मिशन की योजना के शुरू होने के बाद से अब वो घर का कामकाज करने के साथ बच्चों की पढ़ाई में भी समय दे रही हैं। खुद का रोजगार स्थापित कर स्वावलंबी बन रही हैं। एक समय था जब बुंदेलखंड के महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, झांसी में हजारों ऐसे गांव थे जहां जल संकट की वजह से लोग अपनी



## सूखे बुंदेलखंड में बह रही जल धारा

### दुनिया का पहला जल वित्त बुंदेलखंड में प्रसारित

बुंदेलखंड क्षेत्र पानी की कमी और सूखे की समस्या के लिए जाना जाता है। लेकिन जल्द ही देश और दुनियाभर के बच्चे जल संरक्षण का पाठ पढ़ने बुंदेलखंड पहुंचेंगे। दरअसल पद्मश्री से सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडेय और यूनिवर्सिटी ॲफ गोथेनबर्ग, स्वीडन में जलवायु परिवर्तन के प्रोफेसर डॉ. रविकांत पाठक ने हमीरपुर के रिस्रईपारा गांव में जल विश्वविद्यालय खोलने का बड़ा उदाया है। हमीरपुर जिले में जल विश्वविद्यालय बनाने की भर्ती की जा चुकी है। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में उप्र में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ ही स्वच्छ पेयजल के लिए हर गांव से 5 महिलाओं को जल जांच (बाटर टेस्ट किट) का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ऐसे में महिलाएं गांव में फोल्ड टेस्ट किट से पानी की जांच कर रही हैं और स्थानीय प्रशासन को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में अब तक 4,87,955 से अधिक महिलाओं को पानी की जांच की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और गांव-गांव में महिलाएं पानी की शुद्धता की 11 तरह की जांच कर रही हैं। जिससे नल, कुएं, हैंडपम्प और ट्यूबवेल के पानी की गुणवत्ता भी परखी जा रही है। जल जीवन मिशन ने वर्षों से बूंद-बूंद पानी को तड़पने वाले बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। आज यहां हर घर में शुद्ध पेयजल का सपना पूरा हो रहा है। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की हर घर नल से जल योजना बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की नई कहानी बन गई है। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना ने प्रदेश के बड़े क्षेत्रों को पेयजल के बड़े संकट से निजात दिला दी है। हजारों गांवों में नल से घर-घर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू हो जाना इसका जीता जागता प्रमाण है।

लड़कियों की शादी नहीं करते थे।

जल जीवन मिशन योजना पहुंचने के बाद स्थितियां बदलीं और स्वच्छ पेयजल पहुंचने लगा। ऐसे गांवों के लिए जल जीवन मिशन योजना रिश्तों की लाइफ लाइन बनी। उप्र सरकार में प्रधान सचिव अनुराग श्रीवास्तव का मानना है कि जल जीवन मिशन न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में नल से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करा रहा है

बल्कि होनहार एवं जरूरतमंद लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहा है। ऐसे में एक ग्राम पंचायत में 13 युवकों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए पूरे उप्र में 1,16,366 युवाओं को प्लॉबिंग, 1,16,366 इलेक्ट्रीशियन, 1,16,366 मोटर मैकेनिक, 1,16,366 फिटर, 1,74,549 राजमिस्ट्री, 1,16,366 पम्प और परोरेट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे पहले बड़ी संख्या में जल जीवन मिशन के तहत जूनियर इंजीनियरों की भर्ती की जा चुकी है। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में उप्र में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ ही स्वच्छ पेयजल के लिए हर गांव से 5 महिलाओं को जल जांच (वाटर टेस्ट किट) का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ऐसे में महिलाएं गांव में फोल्ड टेस्ट किट से पानी की जांच कर रही हैं और स्थानीय प्रशासन को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में अब तक 4,87,955 से अधिक महिलाओं को पानी की जांच की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और गांव-गांव में महिलाएं पानी की शुद्धता की 11 तरह की जांच कर रही हैं। जिससे नल, कुएं, हैंडपम्प और ट्यूबवेल के पानी की गुणवत्ता भी परखी जा रही है। जल जीवन मिशन ने वर्षों से बूंद-बूंद पानी को तड़पने वाले बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। आज यहां हर घर में शुद्ध पेयजल का सपना पूरा हो रहा है। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की हर घर नल से जल योजना बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की नई कहानी बन गई है। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना ने प्रदेश के बड़े क्षेत्रों को पेयजल के बड़े संकट से निजात दिला दी है। हजारों गांवों में नल से घर-घर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू हो जाना इसका जीता जागता प्रमाण है।

● सिद्धार्थ पांडे



# आधी आबादी को पूरा हक कब तक?

2026 के बाद के चुनावों में ही  
लागू हो पाएगा नया कानून देश में महिलाओं को पुरुषों के बराबर  
आने में 149 साल लगेंगे

देश की लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के बिल को राष्ट्रपति दौपटी मुर्मी ने मंजूरी दे दी। इसी के साथ यह कानून बन गया। नारी शक्ति वंदन कानून 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा से पारित हुआ था। यह कानून बनने के बाद भी देश की महिलाओं को पुरुषों के बराबर आने में अभी 149 साल लगेंगे। जबकि, दुनिया में लैंगिक समानता में 131 साल लगेंगे। ऐसे में क्या नारी शक्ति वंदन कानून भारत की महिलाओं को सशक्त बना पाएगा?

**● राजेंद्र आगाल**

सितंबर को जब संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया, तो इसको लेकर तरह-तरह के कथास लगाए जा रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार ने विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल लाकर देश की आधी आबादी को पूरा हक देने का बड़ा कदम उठाया।

लेकिन महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण कब से मिलेगा, यह तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर श्रेय लेने की राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा अपने आपको महिला हितैषी साबित करने का कोई भी मौका नहीं चूक रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि

महिला आरक्षण बिल लाने का पहला प्रयास हमारी पार्टी कर चुकी है। श्रेय लेने की राजनीति के बीच असली सवाल यह है कि अगर महिला आरक्षण का लाभ तत्काल नहीं मिलना था तो सरकार ने विशेष सत्र क्यों बुलाया? विपक्ष इसे चुनावी फायदा बताकर भाजपा को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में ये अनुमान लगाया गया है कि 2006 से 2023 के बीच लैंगिक समानता सिर्फ 4 प्रतिशत सुधरकर 68 प्रतिशत पर पहुंची है। इसी रफ्तार से बढ़े तो साल 2154 से पहले 100 प्रतिशत तक पहुंचना मुश्किल है। चूंकि भारत में यह 64 प्रतिशत पर है, ऐसे में यहां 18 साल ज्यादा लगेंगे। ऐसे में सबल उठता है कि आखिरकार अधी आबादी (महिलाओं) को पूरा हक कब तक मिल पाएगा? महिला आरक्षण बिल पर संसद ने अपना काम कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद विशेष सत्र में करीब-करीब सर्व सम्मति से ये बिल पास भी हो चुका है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर राष्ट्रपति भवन से मुहर भी लग गई है। हालांकि, लागू कब से हो पाएगा ये कहना अभी मुश्किल हो रहा है क्योंकि अभी कई प्रक्रियाओं से गुजरना बाकी ही है।

## चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा

चुनावों में महिला आरक्षण का मुद्दा क्या असर दिखाएगा ये तो अभी नहीं मालूम, लेकिन भाजपा की तरफ से श्रेय लेने के साथ ही आने वाले 2024 के आम चुनाव के लिए वोट मांगने का काम भी शुरू हो चुका है और ये बीड़ा भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ही उठाया है। भाजपा मुख्यालय से देश की महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को तो धेरा ही, साथ ही ये भी समझा दिया कि कैसे ये सब भाजपा के तीन दशकों के प्रयासों का प्रतिफल है। पीएम ने कहा- ये लोग जो बिल फाड़ा करते थे, उन्हें आगे बढ़कर महिला बिल का सपोर्ट करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने ये तो बताया ही कि कैसे ये सब देश में एक मजबूत सरकार होने की बजह से ही मुमकिन हुआ है, और लगे हाथ उन्होंने अगली पारी के लिए वोट भी मांग लिया। उन्होंने कहा- देश को आगे ले जाने के लिए पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और निर्णायक सरकार बहुत ही जरूरी है।

आगे के अनिश्चित इंतजार के बावजूद बिल पास होने के बाद महिलाओं के मन में जो उम्मीद बढ़ी है, खुश होने का मौका तो है ही। निश्चित तौर पर महिला नेताओं को आरक्षण के तहत प्रतिनिधित्व मिलने के लिए अभी काफी इंतजार करना होगा, लेकिन ये भी तो है कि अभी का इंतजार अनंतकाल के लिए नहीं है। महिला आरक्षण लागू होने के लिए जनगणना और परिसीमन जैसी जरूरी चीजें होनी हैं। जो भी होगा उसके बाद ही हो सकेगा। संसद की बहस तो पूरी हो चुकी है, अभी सड़क पर बहस बाकी है। और ऐसी बहस तो चुनावों में ही होगी। विपक्ष के नेताओं के बयानों को मानकर चलें तो हो सकता है कि बहस 2024 के आम चुनाव के बाद भी चले। शायद 2029 वाले के बाद भी। ये ठीक है कि देश की महिलाओं को राजनीति



## क्या मोदी ने सेट कर दिया चुनाव का एजेंडा?

इस साल के अंत में मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। विधानसभा चुनाव में लगभग दो महीने का समय बचा है। मप्र से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक यात्राओं की सियासत चल रही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा राज्य सरकार की लोक लुभावन घोषणाओं के सहारे सत्ता छीनने की काशिश में है तो वहीं कांग्रेस परिवर्तन यात्राओं के जरिए सत्ता में वापसी की। मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वद यात्रा पर निकले हैं तो कांग्रेस भी जनाक्षोश यात्रा निकाल रही है। यात्राओं की सियासत और महिला वोट की लड़ाई के बीच भाजपा ने अब बड़ा दांव चल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण से संबोधित नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया। लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद ये विधेयक पारित हो गया है। विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े जबकि इसके विरोध में केवल दो वोट पड़े। विपक्षी कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने कुछ आपत्तियों, कुछ सुझावों के साथ बिल के समर्थन में मतदान किया, ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी देखने को मिला। मोदी सरकार के इस कदम को 2024 चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। वहीं, जानकार इसे पांच राज्यों के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में अभी करीब छह महीने का समय बचा है और शीतकालीन सत्र में करीब दो महीने का। सरकार का फोकस अगर बस लोकसभा चुनाव ही होता तो ये बिल शीतकालीन सत्र में लाया जाता। तब तक समय चढ़ की चाल चुनाव और तारीख की दूरी थोड़ी और कम कर युकी होती। लेकिन सरकार ये बिल विशेष सत्र में लेकर आई जो बताता है कि निगाहें भले ही 2024 पर हों, निशाना पांच राज्यों के चुनाव हैं।

में हक के साथ हिस्सेदारी के लिए कोई तारीख तो नहीं मिली है, लेकिन एक निश्चित अवधि तो मुकर्रर हो ही गई है। जैसे 27 साल पहले महिलाओं के लिए आरक्षण की पहल हुई थी, एक दिन वो भी आएगा जब महिला आरक्षण भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तरह वास्तविकता में होगा।

## वोट लेने की भी कोशिश

जब भी कुछ खास होता है तो भाजपा नेता पार्टी मुख्यालय पहुंचकर जश्न मनाते हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भाजपा मुख्यालय में चुनावों में जीत जैसा ही माहौल देखने को मिला। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा की महिला कार्यकर्ता नारे लगा रही थीं... मोदी है तो मुमकिन है! लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद क्रेडिट न लेकर महिला आरक्षण बिल पास होने का श्रेय भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के जरिए देश की महिलाओं को देखा, ये कैसे संभव हो पाया... ये आपने किया है... ये कैसे किया... देश की जनता ने... महिलाओं ने... वोट देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई... आपने जो सरकार का मजबूती दी... उसी की ताकत है कि आज ये सरकार फैसले भी ले पा रही है... और तीन दशक से लटके काम को भी पूरा कर रही है। फिर मोदी ने महिलाओं को मजबूत सरकार का महत्व भी समझाया, पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है तो देश ऐसे ही फैसले ले पाता है... हमने महिला हित में फैसले लिए... किसी के राजनीतिक स्वार्थ को आड़े नहीं आने दिया... और फिर विपक्ष के श्रेय लेने की कोशिशों को भी नकार दिया। मोदी ने कहा, पूरी निष्ठा से प्रयास नहीं हुआ... पहले बिल के नाम पर लीपापोती की गई। विपक्ष को कठघरे में खड़ा करने की भी कोशिश की, नारी का अपमान करने का भी प्रयास किया गया... वंदना पर आपत्ति क्यों है... क्या नारी शक्ति की वंदना नहीं



### महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण के पीछे क्या है तर्क?

जब भी महिला आरक्षण पर बहस शुरू होती है, तो एक आम सवाल जरूर पूछा जाता है। वो है महिलाओं के लिए केवल 33 प्रतिशत आरक्षण क्यों, जबकि उनकी आबादी 50 प्रतिशत है। इस सवाल का जवाब तीन अनुमानों पर आधारित है। पहला - सरकारी संस्थानों में महिलाओं की मौजूदगी विभिन्न मानदंड और मूल्य लाता है जो संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। उदाहरण के लिए, पुलिस जैसे संस्थानों में महिलाओं की बढ़ती संख्या भ्रष्टाचार और पुलिस हिंसा को कम कर सकती है, और इससे महिलाओं और अन्य हाशिये पर रहने वाले समुदायों का पुलिस में विश्वास बढ़ सकता है। हालांकि यहां एक और सवाल उठता है कि आखिर कितनी संख्या में महिलाएं किसी संस्थानों में प्रभाव डालना शुरू करती हैं। कई रिसर्च से पता चला है कि जब संस्था की कुल संख्या में महिलाओं की उपस्थिति एक तिहाई से अधिक बढ़ने लगती है तो इसका प्रभाव पढ़ने लगता है। यही कारण है कि महिलाओं की जनसंख्या 50 प्रतिशत होने के बावजूद केवल 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव किया गया है। दूसरा - राजनीति हो या फिर सरकारी संस्थान, इनमें कुछ ही गिनी-चुनी महिला नेता देखने को मिलती हैं जो किसी बड़े पद पर होती हैं। फिर वही महिला नेता लंबे समय तक राजनीति में नजर आती है। लेकिन महिला आरक्षण उस बैरियर को भी खत्म करने का काम करेगा।

करनी चाहिए... नारी शक्ति को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? क्या राजनीतिक अहंकार इतना आ जाए कि नारी शक्ति के वंदन की बात करें तो लोगों के पेट में चूहे कूदने लगें। प्रधानमंत्री बिल पास होने को लेकर बोले- नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई सामान्य कानून नहीं है... ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है... ये अमृतकाल में सबके प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बढ़ा कदम है। महिलाओं के लिए भाजपा सरकार की तरफ से किए कामों को उपलब्धियों के रूप में गिनाते हुए बातें-बातें में ही मोदी ने तीन तलाक कानून का भी जोर देकर जिक्र किया। ऐसा लगा जैसे वो विपक्ष के उस मांग को काउंटर करना चाहते हैं, जिसमें अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग हो रही है।

### विपक्ष को मिला ओबीसी

सदन में ये देखने को मिला कि कैसे महिला बिल के रास्ते की बाधा बनने के तोहमत से बचने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन दिया। लालू यादव की पार्टी आरजेडी का कोई सांसद न होने के बावजूद कांग्रेस नेताओं ने ओबीसी की शर्त जोड़कर उनकी बात को आगे बढ़ाया। असदुद्दीन ओबैसी ने संमित भूमिका में ही सही विरोध भी जता दिया और भाजपा को सत्ता में होने के नाते संचालक की भूमिका में तो

रहना ही था। देखा जाए तो महिला बिल पास करने में सभी ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। देश की महिलाओं ने भाजपा की मजबूत सरकार बनाकर, भाजपा सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर और विपक्षी दलों ने बिल को समर्थन देकर सभी के हिस्से में कुछ न कुछ तो आया ही है। किसी के हिस्से में थोड़ा कम, और किसी को थोड़ा ज्यादा। भाजपा भले ही महफिल लूट लेने में सफल रहे, लेकिन विपक्ष को भी कोई ज्यादा घाटा हो रहा हो ऐसा नहीं लगता और कुछ न सही, महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण के बहाने विपक्षी इंडिया गठबंधन मजबूत तो हो ही रहा है।

### 55 प्रतिशत वंशवादी महिला सांसद

वर्तमान लोकसभा में आधे से अधिक महिला सदस्य लगभग 55 प्रतिशत हैं, जो कि वंशवादी हैं या फिर किसी राजनीतिक परिवारों से आती हैं। यह दर्शाता है कि गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि की महिलाओं की राजनीतिक शक्ति में कम हिस्सेदारी होती है। हालांकि, इसमें बदलाव की उमोद है जब महिला आरक्षण विधेयक, जो संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण (लगभग 33 प्रतिशत) प्रदान करता है, लागू हो जाएगा। विधेयक को पिछले सप्ताह संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन यह

### महिलाओं को टिकट बांटने में भी राजनीतिक दल नहीं दिखाते रुचि

लोकसभा और राज्यसभा से नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने के बाद से ही राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने को लेकर देश में बहस छिड़ गई है। अब महिलाओं को आरक्षण संबंधी कानून बनाने के बाद उन्हें लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। वर्तमान स्थिति की बात करें तो कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है, जो 15 प्रतिशत टिकट भी महिलाओं को देता हो। मप्र में बीते 15 वर्ष में गठित तीन विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या का विश्लेषण किया जाए तो वर्ष 2013 में गठित 14वीं विधानसभा ही ऐसी थी, जिसमें कुल 230 सदस्यों में महिला विधायकों की संख्या 32 यानी लगभग 14 प्रतिशत थी। यह संख्या 15वीं विधानसभा (वर्ष 2018) में घटकर 9 प्रतिशत यानी महिला विधायकों की संख्या घटकर 21 हो गई थी। 2008 में 24 महिला विधायक थीं। महिलाओं को प्रत्याशी बनाने के मामले में कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस आगे रही है। वर्ष 2008 में कांग्रेस ने 37 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था, जिनमें 8 ने चुनाव जीता। जबकि, भाजपा ने 25 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया। इनमें से 14 ने जीत दर्ज की। वर्ष 2013 में भाजपा ने 28 महिलाओं को प्रत्याशी बनाकर उतारा और 22 पार्टी के भरोसे पर खरी उतरी। जबकि, कांग्रेस ने 23 महिलाओं को टिकट दिया लेकिन केवल 7ही जीत सकीं। 2018 के चुनाव में फिर कांग्रेस ने 27 महिलाओं पर दांव लगाया और 9 चुनी गईं। जबकि, भाजपा ने 24 महिलाओं को टिकट दिए और उनमें से 11 जीतकर विधानसभा पहुंचीं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल मात्र जिताऊ प्रत्याशी को ही टिकट देना चाहते हैं। महिलाओं की क्षमता पर वे आसानी से भरोसा नहीं कर पाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक सर्वसम्मति से दोनों सदनों में पारित किया गया है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। आधी आबादी को न्याय मिला है। भाजपा भी नारी सशक्तिकरण की पक्षधर है। भाजपा का प्रयास रहा है कि हमारे पदाधिकारियों में भी 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं का हो। यह काम पहले से हो रहा है। मप्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दी है। पहली महिला राष्ट्रपति भी कांग्रेस पार्टी ने बनाई। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई। महिला आरक्षण का बिल भी कांग्रेस ही संसद में लाई थी। मप्र में भी महिलाओं को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी ही देगी।

अगली जनगणना और उस जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद लागू होगा। आरक्षण के कार्यान्वयन के साथ, संभवतः 2029 या उसके बाद, 545 सदस्यीय लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाने की उम्मीद है। मौजूदा 82 महिला लोकसभा सांसदों में से 45 वंशवादी हैं। राजवंशों में वे लोग शामिल हैं जिनके परिवार के सदस्य संसद या राज्य विधानसभा में किसी भी सदन के सदस्य थे या हैं। इन परिवार के सदस्यों में पति-पत्नी, ससुराल वाले या ब्लड रिलेशन्स शामिल हैं।

विश्लेषण से पता चलता है कि जब जीवनसाथी के रूप में निर्वाचित प्रतिनिधि की बात आती है, तो इन 45 महिला लोकसभा सांसदों में से 23 के पति वर्तमान में सांसद या विधायक हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरक्षण विधेयक लागू होने के बाद शुरुआत में राजनीतिक राजवंशों से महिला सांसदों का रुझान जारी रहेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिक महिला नेताओं के उभरने से चीजें बदल सकती हैं।

वंशवादी पृष्ठभूमि से आने वाली महिला सांसदों के बारे में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के प्रोफेसर संजय कुमार का कहना है कि यह मामला शुरू में चिंता का विषय होगा। हम अचानक यह उम्मीद नहीं कर सकते कि एक तिहाई या 181 महिला सांसद (चुनाव लड़ने के लिए आगे) आएंगी। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि 181 महिलाएं नहीं मिलेंगी जिन्हें टिकट दिया जा सके। चिंता की बात यह होगी कि सभी पार्टीयां ऐसी महिलाओं को टिकट देने की कोशिश करेंगी जो जीत सकती हैं। संभावना है कि प्रॉफेसर उम्मीदवार बड़े पैमाने पर राजनीतिक परिवारों से आएंगे जो (सत्ता के पदों पर बैठे पुरुषों की) पत्नियां, बहनें, माँ और बेटियां होंगी। उन्होंने कहा कि वंशवादी प्रवृत्ति शुरू में जारी रहेगी लेकिन आने वाले समय में इसमें बदलाव भी हो सकता है। कुमार ने आगे दावा किया कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होने का कारण पार्टीयां द्वारा उन्हें टिकट नहीं देना हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्टीयां केवल उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देती हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे चुनाव जीत सकते हैं। पार्टीयों का मानना है कि जीतने की संभावना तब अधिक होती है जब कोई महिला नेता राजनीतिक पृष्ठभूमि से हो। इसीलिए, अतीत में निर्वाचित होने वाली ज्यादातर महिलाएं किसी राजनीतिक परिवार से आती हैं। तथ्य यह है कि गैर-वंशवादी पृष्ठभूमि की महिला उम्मीदवारों को शायद ही कभी टिकट दिया जाता है।



### किस राज्य में कितनी महिला आरक्षित लोकसभा सीटें?

केंद्रीय कैबिनेट से महिला आरक्षण विल को मंजूरी मिलने के बाद विशेष सत्र के दौरान पहले लोकसभा और बाद में राज्यसभा में इसे पास कर दिया गया। 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक लाने के लिए विपक्ष लगातार जोर दे रहा था। अब विशेष सत्र में विधेयक पर सदन की मुहर भी लग चुकी है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 में लोकसभा का नजारा बदल सकता है, ऐसा हो सकता है कि इतिहास में पहली बार सदन में 33 प्रतिशत महिलाएं नजर आएं। वर्तमान में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15 फीसदी से कम है। हरानी की बात ये है कि राज्य विधानसभाओं में ये आंकड़ा दस फीसदी से भी निचले स्तर पर है। ऐसे में लगातार लोकसभा और विधानसभा में महिला सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए आरक्षण की मांग की जा रही है। अखिरी बार 2010 में ये विधेयक राज्यसभा में पेश हुआ था, तब हांगमे के बीच इसे पास भी कर दिया गया था, लेकिन लोकसभा से ये पास नहीं हो सका था। अब संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर मुहर लग चुकी है, तो 33 प्रतिशत के हिसाब से लोकसभा की 545 सीटों में से तकरीबन 180 सीटों पर प्रतिनिधित्व महिलाओं का होगा। इस लिहाज से आंध्रप्रदेश में 25 लोकसभा सीटों में से 8 पर महिलाओं का कब्जा होगा। असम में 14 सीटों पर 5, बिहार में 40 में से 14, छत्तीसगढ़ में 11 में 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 33 प्रतिशत के हिसाब से यहां 9 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वहीं हरियाणा में 10 सीटों के लिहाज से 4, और हिमाचल में 4 सीटों के हिसाब से तकरीबन 1 सीट महिला आरक्षित हो सकती है। जम्मू में 5 लोकसभा सीटें हैं इनमें से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं, 16 सीटों वाले झारखंड में यह आंकड़ा 5 तक पहुंच सकता है, कर्नाटक में 28 सीटों के मुताबिक 9 और केरल में 20 सीटों में से 7 महिला आरक्षित हो सकती हैं।

### राजनीतिक पृष्ठभूमि का दबदबा

भाजपा के पास वर्तमान में लोकसभा में 42 महिला सांसद हैं, जिनमें से 19 राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं। लोकसभा में कांग्रेस की सात महिला सांसद हैं, जिनमें से पांच राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं। निचले सदन में तृणमूल कांग्रेस की नौ महिला सांसद हैं, जिनमें से तीन राजनीतिक परिवारों से हैं, जबकि बीजू जनता दल के पास पांच हैं, जिनमें से दो राजनीतिक परिवारों से हैं। शिवसेना और द्रविड़ मुनेत्र कड़ागम में दो-दो महिला लोकसभा सांसद हैं, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं, और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में चार हैं, जिनमें से एक वंशवादी पृष्ठभूमि से है। मौजूदा संख्या में नौ अन्य महिला लोकसभा सांसद हैं जो वंशवादी पृष्ठभूमि से आती हैं। वे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अपना दल (सोनेलाल), शिरोमणि अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी, भारत राष्ट्र समिति, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों से संबंधित हैं। सभी के पास ऐसी महिला सांसद हैं जो राजनीतिक परिवारों से आती हैं।

राजनीतिक परिवारों से कुछ प्रमुख वर्तमान महिला लोकसभा सांसदों में राकांपा प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा की बेटी अगाथा संगमा और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर शामिल हैं। इस लोकसभा में 82 महिला सांसदों में से 80 ने विभिन्न राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ा है, जबकि दो निर्दलीय हैं- मांड्या से सुमलता अंबरीश और अमरावती से नवनीत कौर राणा, दोनों के राजनीतिक संबंध हैं। राणा के पति रवि राणा तीन बार विधायक रहे हैं, वर्ही सुमलता के पति अंबरीश एक प्रसिद्ध अभिनेता और मान्या से सांसद थे। 2019 के लोकसभा चुनावों में कम से कम 78 महिला सांसद चुनी गईं, उपचुनावों में सफलतापूर्वक लड़ने वाली चार महिलाओं को

शामिल करने के साथ यह संख्या बढ़कर 82 हो गई। उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने मैनपुरी की सीट जीती, यह सीट पिछले साल उनके सम्मुख मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण खाली हुई थी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी और कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने पिछले साल हिमाचल प्रदेश के मंडी से उपचुनाव जीता था।

दादरा और नगर हवेली की सीट मोहन डेलकर की पत्नी कलाबेन डेलकर ने जीती थी, जो इस निर्वाचन क्षेत्र से सात बार सांसद रहे, जिनकी 2021 में मृत्यु के कारण उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी की पत्नी मंगला अंगड़ी ने अपने पति के निधन के बाद 2021 में हुए उपचुनाव में कर्नाटक की बेलगाम सीट से जीत हासिल की थी। राजनीतिक परिवारों से महिला लोकसभा सांसदों का प्रतिनिधित्व विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में होता है। तमिलनाडु से, कनिमोझी करुणानिधि और थमिज्ञाची थंगापांडियन क्रमशः पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि और दिवंगत डीएमके नेता वी थंगापांडियन की बेटियां हैं। इसी तरह, महाराष्ट्र में कलाबेन डेलकर के अलावा, शिवसेना की दूसरी महिला सांसद भावना गवली हैं, जो पूर्व सांसद पुंडलिकराव गवली की बेटी हैं।

भाजपा, जो अक्सर विपक्षी दलों पर वंशवादी राजनीति का आरोप लगाती है, उसमें भी राजनीतिक परिवारों से आने वाली कुछ उल्लेखनीय महिला सांसद भी हैं। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री ईंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री एचएन बहुगुणा की बेटी रीता बहुगुणा जोशी और और माला राज्य लक्ष्मी, टिहरी गढ़वाल से आठ बार के पूर्व सांसद मनबेंद्र शाह की बहू शामिल हैं।

### मातृशक्ति की महिमा गाई जा रही

यह देश के लिए अतुलनीय है। मातृ शक्ति के लिए वर्णनीय है। हम सब के लिए अविस्मरणीय है। कहा जाता है— महिला कितने



ही काम कर रहे, कितनी ही उपलब्धियां हासिल कर रहे, असल में उसकी प्रशंसा बहुत कम की जाती है। घरों में, परिवारों में तो और भी कम। क्योंकि परिवार वाले और घर वाले अक्सर उनके काम को काम ही नहीं समझते। ज्यादातर मौकों पर तो ये कह दिया जाता है कि ये तो उनका काम है। कर दिया तो क्या हुआ? दरअसल, घर में रहकर भी वे ऑफिस जाने वाले, या अन्य किसी काम के लिए जाने वाले पुरुषों से बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। यह सब को दिखाता भी है लेकिन कोई उनके काम को महत्व नहीं देता। कोई ऑफिस या बाजार या फैक्ट्री से आकर ये नहीं कहता कि तुम बैठो! थक गई होगी। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। या चाय बनाता हूँ। वही अकेली, फिरकी की तरह थकी-मांदी हो तब भी सब के आगे-पीछे ढोलती-फिरती है। तुम्हें चाय चाहिए या जूस? भूख लगी होगी? कुछ खाया था या नहीं? थके हुए लग रहे हो? थोड़ा आराम कर लो! सब कुछ सभी से वही पूछे! उससे कोई नहीं पूछता! क्योंकि वो तो दिनभर घर में ही थी! उसे करना ही क्या होता है? कोई उसके भीतर के घाव नहीं देखना चाहता! देखना तो दूर, कोई पूछना भी नहीं चाहता।

महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद देश की संसद में पीड़ियों से चली आ रही महिला

शक्ति की पीड़ि को पहचाना जा रहा है। उनके महत्व को बताया जा रहा है। यह अच्छी, बहुत अच्छी शुरुआत है। राजनीति और दलीय जरूरतें और नेतागिरी को एक पल के लिए भूल जाइए! वजह जो भी हो, महिलाओं का मान बढ़ाया जा रहा है। उन्हें पूज्य और वंदनीय कहा जा रहा है। इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। राज्यसभा में एक विपक्षी सांसद ने कहा— सरकार बार-बार महिलाओं को वंदनीय क्यों कह रही है? उन्हें अपनी वंदना नहीं करवानी है। उन्हें समानता चाहिए। पुरुषों से समानता। सबाल यह है कि समानता देने से इनकार किसने किया है? दीजाए, समानता! लेकिन किसी की वंदना करने में हर्ज क्या है? वैसे भी नारी नर से कई रूपों में, कई गुणों में महान है। उसकी इस महानता के ही नाते अगर वंदन किया जाए तो दिक्कत क्या है? पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दलीय राजनीति से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। लोकसभा में उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए सभी दलों के सभी सांसदों को धन्यवाद दिया। उनका आभार माना। यह व्यवहार अनुकरणीय है। ऐसा व्यवहार, ऐसी भावना, विपक्ष को भी रखनी चाहिए, ताकि नए संसद भवन में राजनीति की एक अलग छाप रहे। लोकतंत्र को अलग और ज्यादा सम्मान मिल सके।

### जाति बनाम महिला आरक्षण

बढ़ते बाहरी दबाव के कारण भारतीय राजनीति में महिला आरक्षण का मुद्दा उठा। संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं पर चार विश्व सम्मेलन आयोजित किए जो 1975 में मैक्सिको में, 1980 में कोपेनहेंगन में, 1985 में नैरेबी में और 1995 में बीजिंग में हुए। अतिम सम्मेलन में बीजिंग घोषणापत्र और कार्वाई के लिए मंच तैयार किया गया जिसे 189 देशों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया। इसमें महिलाओं के लिए कोटा का प्रावधान था और भारत ने भी बीजिंग घोषणा पर काम किया। हालांकि, जब भी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को पास करने की कोशिश की, तो उसे पिछड़ी जाति के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने इसे संसद में अपने उत्थान को उलटने के लिए एक उच्च जाति की साजिश के रूप में देखा। ये मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के कारण 1990 के दशक में शुरू हुआ था। लेकिन यह डर बिल्कुल से इनकार करना और उनकी जगह महिलाओं को टिकट देना आसान हो जाता है। फ्रांसेस्का आर जेन्सेनियस ने ऐसा ही मामला ऑडिशा में पाया। यहां बीजू जनता दल ने आरक्षित सीटों के लिए ज्यादातर महिला उम्मीदवारों को नामित किया था। बीजेड़ी की महिलाओं के आरक्षण की राजनीति ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों को उनके उच्च जाति के समकक्षों की तुलना में अधिक नुकसान पहुँचाया। ऑडिशा में बीजेड़ी के उम्मीदवार नामांकन के मामले के रिसर्च से पता चलता है कि यह अनुमान लगाना गलत नहीं है कि महिलाओं के कोटे में पिछड़ी जाति के पुरुषों को नुकसान पहुँचाने की प्रबल क्षमता है।

छ तीसगढ़ में चुनावी पारा चढ़ चुका है। दिलचस्प है, सियासी माहौल को गरमाने का काम केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी विनोद वर्मा के यहां छापेमारी की थी। इस पर प्रतिक्रियाओं की आंच ठंडी भी नहीं हुई थी कि ईडी ने सिंतंबर के पहले सप्ताह में वर्मा के बेटों और पत्नी

तक को समन भेज दिया। इसके बाद से भूपेश बघेल लगातार केंद्र और भाजपा पर हमलावर हैं। राजनांदगांव में 8 सिंतंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में भरोसे का सम्मेलन आयोजित कर बघेल ने चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत कर दी है।

राज्य में विधानसभा की कुल 90 सीटों पर मुख्यतः कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला होता रहा है। राज्य के गठन के बाद 15 साल तक राज्य में भाजपा की सरकार रही। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को पहली बार राज्य में मात दी और काफी विवादों और चर्चाओं के बाद भूपेश बघेल सर्वसम्मति से लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर उभेरे। डेढ़ दशक तक सत्ता में रही भाजपा राज्य में 15 विधायक ही बनवा सकी। चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के 68 विधायक थे। 2022 में संपन्न हुए खैरागढ़ उपचुनाव के बाद सदन में कांग्रेस विधायकों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है।

पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2023 में कुल मतदाताओं की संख्या में 9 लाख 49 हजार 866 की बढ़ोतारी दर्ज की गई है। इनमें महिलाएं पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं। इनमें ही नहीं, 14 जिले ऐसे हैं जहां पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर हैं। महिला वोटरों को साधने में जुटी कांग्रेस विधानसभावार महिला प्रभारियों की नियुक्ति अप्रैल में ही कर चुकी है। उधर, मिशन-2023 की तैयारी में जुटी भाजपा जीती हुई सीटें बरकरार रखने के साथ हारी हुई सीटों पर फोकस कर रही है। कोई तीन महीने बाद होने वाले विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में पार्टी के 14 विधायकों और 11 सांसदों की कड़ी परीक्षा होनी है। भाजपा के साथ एक लाभ यह है कि केंद्र में भी उसी की सरकार है और ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां कथित रूप से केंद्र के इशारे पर अब खुलेआम राज्य सरकारों के खिलाफ काम कर रही हैं। पिछले महीने राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल और झारखण्ड में पड़े विपक्षी नेताओं के यहां छापे इसकी तसदीक करते हैं। आरोप है कि एजेंसियों के सहारे भाजपा राज्य सरकारों को उखाड़ने और असंवैधानिक



## राम के नाम पर गोट

भूपेश बघेल को राम के नाम का भी आसरा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने कई राज्यों की भाजपाई सरकारों को भी मात दे दी है। बघेल सरकार ने सबसे पहले राम वनपथगमन योजना की घोषणा की, वह भी उस समय जब केंद्र सरकार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के प्रचार में लगी हुई थी। राज्य सरकार ने चंद्रखुरी रिस्थित माता कौशल्या मंदिर से यह काम प्रारंभ किया। देखते ही देखते सरकार ने 51 स्थलों को चिह्नित कर राम वनगमन पर्यटन परियथ के रूप में विकसित करने की शुरुआत की। सरकार की इस पहल का दोहरा असर हुआ। एक ओर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद ने भूपेश सरकार की योजनाओं की तारीफ की और छत्तीसगढ़ प्रवास में परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने भूपेश सरकार को सराहा, तो दूसरी ओर राज्य में सांप्रदायिक दंगे भी हुए। छिट्ठुत सांप्रदायिक तनावों के बीच 2021 में कवर्धा में हुआ सांप्रदायिक दंगा सबसे अहम रहा, जिसके आरोप में भाजपा के एक वर्तमान और एक पूर्व सांसद के खिलाफ एक आईआर दर्ज की गई। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कवर्धा के रहने वाले हैं।

रूप से कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

बीते दिनों जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रायपुर का दौरा किया था, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ 104 पन्नों का एक आरोपपत्र जारी किया। रायपुर के दोनों विधायक सभागार में आरोपपत्र जारी करते हुए शाह ने कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को गांधी धरातल का एटीएम बना दिया है और राज्य को विकास के रास्ते से भटका दिया है। अब केवल भाजपा ही छत्तीसगढ़ को कांग्रेस की लूट, अत्याचार और कुशासन से बचा सकती है। इस बीच 17 अगस्त को भाजपा ने अपने 21 उम्मीदवारों को

भी मैदान में उतार दिया है। पांच पूर्व विधायक, एक सांसद के अलावा 16 नए चेहरों वाली इस सूची में पार्टी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा सीट पाटन से पूर्व विधायक और दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद विजय बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। विजय बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे हैं। विजय को चुनावी मैदान में उतारकर भाजपा ने यहां की लड़ाई बघेल बनाम बघेल की कर दी है। बताया जाता है कि भाजपा की पहली सूची खुद अमित शाह की मंजूरी से तैयार हुई है, लेकिन दूसरी सूची को लेकर अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की पहली सूची का भाजपा को इंतजार है। कांग्रेस की पहली सूची में कई कारणों से देरी हो रही है। पहले बताया गया था कि कांग्रेस 7 सिंतंबर तक अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें टलते रहने के कारण अब तक ऐसा नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि 8 सिंतंबर को राजनांदगांव पहुंचे खड़गे की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी थी, जिसके बाद शायद कुछ दिनों के भीतर कांग्रेसी उम्मीदवारों की सूची आ जाए। संभव है इस सूची के आने के बाद ही भाजपा दूसरी सूची पर हाथ लगाए।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की उपस्थिति में राजनांदगांव के टेकवां विकास प्रखंड में 8 सिंतंबर को मुख्यमंत्री बघेल ने 355 करोड़ 23 लाख रुपए को लागत के कुल 1867 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इसमें 177 करोड़ 86 लाख रुपए के 1691 कार्यों का भूमिपूजन एवं 177 करोड़ 36 लाख रुपए के 176 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। बघेल बीते पांच साल में अपने किए ऐसे ही विकास कार्यों, शिलान्यासों और लोकार्पणों पर भरोसा जाता रहे हैं। खासकर, राज्य सरकार की ग्रामीण विकास योजनाओं से सार्थक महिलाओं की बड़ी आबादी की आर्थिक गतिविधियों में संलग्नता बढ़ी है।

● रायपुर से टीपी सिंह

जब कांग्रेस नेता  
राहुल गांधी ने  
4,000  
किलोमीटर पैदल  
चलने वाली भारत  
जोड़ी यात्रा शुरू  
की थी, तो किसी  
को आभास तक  
नहीं था कि  
सालभर में भारत  
शब्द राजनीति का  
बड़ा अखाड़ा बन  
जाएगा। संयोग  
ही है कि इस यात्रा  
के एक साल के  
भीतर ही विपक्ष ने  
सत्तारुद्ध भाजपा  
और एनडीए के  
खिलाफ अपना  
गठबंधन भी रखा  
कर लिया,

जिसका नाम  
इंडिया (सर्विधान  
के मुताबिक भारत  
का अन्य नाम)  
रख लिया।  
लेकिन कांग्रेस की  
विडंबना यह है  
कि वह राहुल  
गांधी से बाहर  
नहीं निकल पा  
रही है।



## कांग्रेस के केंद्र में सिर्फ राहुल ही

**का**

ग्रेस के इतिहास में पहली बार दिल्ली से बाहर हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में यह भी पहली बार हुआ कि बैठक का केंद्र बिंदु पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, बल्कि सोनिया, राहुल

और प्रियंका गांधी बने

रहे। ये तीनों ही नई

कार्यसमिति के सदस्य हैं। बैठक में पहला मुख्य मुददा भी राहुल गांधी की पार्टी-टू और पार्टी-श्री भारत जोड़े यात्रा रहा। कार्यसमिति में कांग्रेस अधिवेशन की तरह तीन प्रस्ताव भी पास किए गए। प्रस्तावों का एक हिस्सा देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़ा है, दूसरा देश की आर्थिक स्थिति पर और तीसरा देश की राजनीतिक दशा और दिशा पर। जहां तक राजनीतिक प्रस्ताव का सवाल है, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण के संबंध में नीतीश, लालू और अखिलेश यादव की लाइन अपनाई गई है।

कांग्रेस ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की है, ताकि दिल्लिं, आदिवासियों और पिछड़ों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जा सके। प्रस्ताव में याद दिलाया गया है कि राहुल गांधी ने इसी साल कोलार में कहा था कि जिसकी जितनी संख्या उतना आरक्षण। प्रस्ताव में राहुल गांधी का जिक्र इस बात की

ओर संकेत करता है कि कांग्रेस राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन का केंद्र बिंदु बनाने की रणनीति को सामने रखकर ही आगे बढ़ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में ईंदिरा साहनी केस में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तय की हुई है।

कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना का भी समर्थन किया है। लालू यादव और नीतीश कुमार ने इंडी एलायंस की मुंबई बैठक में यह मांग उठाई थी, लेकिन ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे ने जाति आधारित जनगणना का विरोध किया था, इस कारण यह मांग एजेंडे में शामिल नहीं हुई थी। जबकि 13 सितंबर को दिल्ली में हुई को-आर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इस मांग को एजेंडे में शामिल कर लिया गया, इस बैठक में ममता बनर्जी का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। खबर आई थी कि ममता इस फैसले से नाराज हैं। मोदी सरकार बनने के बाद से कांग्रेस का आरोप रहा है कि सर्विधान और देश का संघीय ढांचा खतरे में है। उसे भी राजनीतिक प्रस्ताव में दोहराया गया है कि मोदी सरकार ने सिलसिलेवार राज्य सरकारों को कमज़ोर किया है, राज्य सरकारों को राजस्व का हिस्सा देने में आनाकानी की गई है, या उन्हें घटा दिया गया है। इस तरह राज्य सरकारों को उनका कर्तव्य निभाने में रुकावटें खड़ी

### इस बार जोरदार मुकाबला

आम चुनाव 2024 नजदीक आ रहा है, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि इस बार सत्तारुद्ध एनडीए की सीधी भिड़ंत साझा विपक्ष के नए-नवेले गठबंधन इंडिया से होगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या विपक्ष यह लड़ाई देश स्तर पर एकजुट होकर लड़ेगा या पहले की तरह उनके बीच का आपसी टकराव और नेताओं की व्यक्तिगत आकांक्षाओं की वजह से यह संभव न हो पाएगा। विगत में कई बार सत्तारुद्ध दल या गठबंधन के खिलाफ चुनावों में प्रतिपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश हुई, लेकिन वैसे गठबंधन लंबे समय तक नहीं टिक पाए। कुछ तो सीट बंटवारे के सवाल पर चुनाव-पूर्व ही बिखर गए तो कुछ चुनाव के बाद, भले ही सत्ता उनके हाथ लगी हो। इस बार भी यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर उन राज्यों में जहां इंडिया के दो प्रमुख घटक दल एक-दूसरे के आमने-सामने हैं। बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में क्या होगा जहां कांग्रेस, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की निकटतम प्रतिद्वंद्वी है? क्या संसदीय चुनाव के लिए ममता और केजरीवाल कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के सवाल पर दरियादिली दिखा सकते हैं, या कांग्रेस उन राज्यों में अपने सहयोगी दलों के लिए मैदान छोड़ सकती है जहां वह कमज़ोर स्थिति में है?

की गई हैं।

मोदी सरकार की ओर से एक देश, एक चुनाव की मुहिम को भी कांग्रेस ने संविधान के संघीय स्वरूप पर प्रहर के रूप में प्रदर्शित किया है। कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव का विरोध पहली बार नहीं किया है, इससे पहले संसदीय समिति में भी कांग्रेस और अन्य कई क्षेत्रीय दल विरोध कर चुके हैं। यह सबको पता है कि एक देश एक चुनाव के लिए कम से कम पांच संविधान संशोधनों की ज़रूरत पड़ेगी, और मोदी सरकार भी अच्छी तरह जानती है कि उसके पास संविधान संशोधनों के लिए दो तिहाई बहुमत नहीं है। इसलिए कांग्रेस का मानना है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनावों से पहले सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की काशिश कर रही है कि वह एक देश एक चुनाव करवाना चाहती है, लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है।

हैरानी वाली बात यह है कि सनातन धर्म पर उठे विवाद के कारण भोपाल की रैली रद्द कर दी गई। दरअसल, मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने रैली करवाने से इंकार कर दिया था। लेकिन सनातन धर्म पर बैठक में कोई आधिकारिक चर्चा नहीं होने दी गई, क्योंकि बात बाहर लीक होती और इंडी एलायंस में फूट का संदेश जाता। इसलिए कांग्रेस ने चुपके से भोपाल की रैली रद्द होने का ऐलान कर दिया।

भोपाल रैली का फैसला राहुल गांधी की सिफारिश पर ही 13 सितंबर को इंडी एलायंस की को-आर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लिया गया था। लेकिन उसी दिन शाम को कमलनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गों को फोन करके कहा कि रैली मप्र में न रखी जाए। उन्होंने इसका कारण सनातन धर्म पर हुई उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी से मप्र में हवा खराब होना बताया था। मल्लिकार्जुन खड़गों ने 15 सितंबर को ही एक इंटरव्यू में संकेत दे दिया था कि भोपाल की रैली रद्द हो सकती है। अगले दिन हैदराबाद में कमलनाथ रैली नहीं करवाने पर अड़ गए, तो रैली रद्द कर दी गई। कमलनाथ खुद पक्के सनातनी हिंदू हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र के समर्थक बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को हाल ही में अपने निर्वाचन क्षेत्र में बुलाकर उनकी कथा करवाई थी। जब धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प पर कमलनाथ से सवाल पूछा गया था तो कमलनाथ ने कहा था कि जिस देश की 80 फीसदी जनता हिंदू है, वह हिंदू राष्ट्र ही है। अब वह उस इंडी एलायंस की रैली बहां कैसे करवा सकते हैं, जिसका एक घटक सनातन धर्म का समूल नाश करने की बात कह रहा हो, और यह भी कह रहा हो कि इंडी एलायंस सनातन धर्म विरोध के आधार पर ही बना है।

कांग्रेस से जब सनातन धर्म पर उसका स्टैंड पूछा गया तो कांग्रेस ने टालते हुए कहा कि यह असली मुद्दे से ध्यान हटाने की भाजपाई चाल



### भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट-3 भी होगा

राहुल गांधी संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त हो कांग्रेस को जमीन पर खड़ा करने की कोशिशों में लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट-3 भी करेंगे, जो उपर पर ज्यादा केंद्रित हो सकती है। पहले फैज में उन्होंने उपर के सिर्फ तीन जिलों गणियाबाद, बुलेंशहर और शामली का 130 किलोमीटर तक का सफर करव किया था। राहुल गांधी ने अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू करके श्रीनगर में उसका समापन किया था, लेकिन असल समापन उसी दिन 30 जनवरी को महात्मा गांधी की समाधि पर दिल्ली लौट कर हुआ, क्योंकि उस दिन गांधीजी की पुण्यतिथि थी। अगस्त के पहले हफ्ते में लगभग यह तय हो गया था कि राहुल गांधी की पार्ट-टू भारत जोड़ो यात्रा 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी के जन्मदिन पर उनकी जन्मस्थली पोरबंदर से शुरू होगी और समापन तिपुरा, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड पर होगा। लेकिन कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में इसे उलटा करके पूर्व से पश्चिम की दिशा में करने की रणनीति बनी है, इसका मतलब यह है कि करीब 100 दिन की यह यात्रा अरुणाचल प्रदेश से शुरू होकर पोरबंदर तक हो सकती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, मप्र और छत्तीसगढ़ कवर होगा।

है। साफ है कि कांग्रेस डीएमके को किसी भी हालत में अपने साथ रखने के लिए इस मुद्दे से बचना चाहती है। डीएमके की वजह से तमिलनाडु में कांग्रेस का कुछ आधार बचा हुआ है। 2019 में कांग्रेस को देशभर से मिली 53 लोकसभा सीटों में आठ डीएमके से गठबंधन की वजह से तमिलनाडु से मिली थीं। जातीय जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की तरह कांग्रेस का दूसरा मुद्दा भी राहुल गांधी ने तय किया है। कांग्रेस ने अपना दूसरा मुद्दा लद्दाख में चीनी कब्जे को चुना है। सरकार और सेना की तरफ से बार-बार के खंडन के बावजूद कांग्रेस ने कहा है कि गलवान की घटना भारत की धरती पर हुई थी, इसलिए नंदेंद्र मोदी यह कहकर देश को गुपराह कर रहे हैं कि भारत की एक इंच जमीन पर भी चीन का कब्जा नहीं हुआ है।

कांग्रेस का मुख्य तर्क यह है कि पुलिस अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस में लद्दाख के पुलिस अधिकारी ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि भारतीय सेना पहले जहां तक पेट्रोलिंग करती थी, अब वहां चीन का कब्जा है। राहुल गांधी ने अपनी ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप यात्राओं में भी लद्दाख में चीन के कब्जे की बात कही थी, और इस बीच अपनी लद्दाख यात्रा के

दौरान भी स्थानीय चरवाहों के हवाले से कहा था कि जहां वे 2020 तक अपनी भेड़ बकरियां चराने जाया करते थे, अब उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया है और अब वहां चीन की सेना बैठी है।

कांग्रेस ने राहुल के इस चीन एंजेंडे को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने के भी संकेत दिए हैं। राहुल गांधी की अगली भारत जोड़ो यात्राओं का मुख्य मुद्दा भी चीन ही रहने वाला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट-टू करने का फैसला अगस्त में ही हो चुका था। अगस्त के पहले हफ्ते में दिविजय सिंह को यात्रा का संयोजक बनाकर रुट तय करने की कमेटी भी बना दी गई थी। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी की पार्ट-टू भारत यात्रा के लिए बाकायदा प्रस्ताव पास कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता ने यात्रा शुरू होने और उसके मार्ग के बारे में अभी कुछ भी बताने से इंकार किया है। लेकिन इस बार राहुल गांधी की यात्रा के समय देशभर के कांग्रेसी भी अपने-अपने राज्य में पदयात्राएं निकालेंगे। इस संबंध में सभी राज्यों को संदेश भेजा जा चुका है और राज्यों में तैयारियां शुरू हो गई हैं, जैसे महाराष्ट्र में चार बड़े नेता अलग-अलग दिशाओं से यात्रा निकालेंगे।

● विपिन कंधारी



# हारे तो बड़ी लड़ाई क्षुशिकल

मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। इस चुनाव में सबकी नज़र मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर है। इसकी वजह यह है कि इन चुनावों से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तर्कीर सामने आएगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर इन चुनावों में जो भी पार्टी हारेगी, बड़ी लड़ाई में उसके सामने मुश्किलों का पहाड़ रख़ा हो जाएगा। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस इस चुनाव को लेकर काफी सर्वेदनशील और सतर्क हैं।

**क**र्तव्य दो राय नहीं कि ऐसे राज्य चुनाव कम ही हुए, जिनसे केंद्र को कुर्सी भी तय होने की संभावनाएं-आशंकाएं जुड़ी हों। दरअसल पांच राज्यों के चुनाव बस ड्यूटी पर खड़े हैं। उनमें मिजोरम और तेलंगाना भी सियासी रंगत और फिजा बदस्तुर बदलेंगे, लेकिन असली लड़ाई के मैदान तो हिंदी पट्टी के मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हैं, जो संसदीय चुनाव के बस अगले ही मोर्चे पर गंभीर असर डाल सकते हैं, या कहें इसके आसार हैं। वजह यह कि उत्तर और पश्चिम भारत की इसी पट्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा को 2014 से भी ज्यादा 2019 के संसदीय चुनावों में बोट हासिल हुए थे और यहां पार्टी कुछ भी सीटें गंवाने का जोखिम उठाने की हालत में नहीं है। ये वही राज्य हैं, जहां उसका मुकाबला मोटे तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ़ कांग्रेस से है। इन्हीं मैदानों में दोनों पार्टियों के सियासी रंगों-आब का इम्प्रियान होना है। इसलिए इन राज्यों के सिपहसालारों पर दोहरी जिम्मेदारी है। पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनावों में इन तीनों राज्यों में जीत के बावजूद कांग्रेस संसदीय चुनावों में सूपड़ा सफ़ करवा चुकी थी, लेकिन आज, 2019 के बाद से नदियों में काफी पानी बह चुका है, हवा का रुख बदला है। ऐसे में दोनों पार्टियों और उनके सेनापतियों के आगे चुनौती यह है कि राज्य चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करके संघीय चुनावों के लिए पुख्ता जमीन तैयार करें।

दरअसल महंगाई, बेरोजगारी, छोटे उद्योगों के

बढ़ होने और काम-धंधों में मंदी की वजह से केंद्र के खिलाफ सत्ता-विरोधी लहर का ताप शायद राज्यों से ज्यादा है। हाल के कई जनमत सर्वेक्षणों में न सिर्फ़ इन मुददों पर लोगों की चिंताओं में भारी इजाफा दिखा है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के आंकड़े भी पहले के मुकाबले घटे हैं। उसके बरक्स कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता में (खासकर भारत जाड़ो यात्रा के बाद) न सिर्फ़ छलांग दिखी है (अलबत्ता मोदी से तकरीबन आधे पर दिखाए गए हैं), बल्कि इंडिया गर्भबंधन के जरिए मजबूत दावेदारी भी दिखाने की कोशिश की गई है, ताकि मोदी बनाम कौन का सवाल भी कुछ मंदा पड़ जाए। यही नहीं, कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन अब खुलकर भ्रष्टाचार, क्रोनी कैपटलिज्म (याराना पूँजीवाद) और बढ़ती गैर-बराबरी का मुददा उठाकर नैरेटिव भी

तैयार करने की कोशिश कर रहा है। भाजपा इसकी काट के लिए इंडिया बनाम भारत, राम मंदिर निर्माण, एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे अपने किस्म के राष्ट्रवाद का नैरेटिव तैयार करने की कोशिश में दिखती है। भाजपा की कोशिश ऐसे कुछ और मुददे तथा सोशल इंजीनियरिंग की भी पहली दिखती है।

इसी मायने में हिंदी पट्टी के इन राज्यों में दाव बढ़े हैं। इन राज्यों की कुल 65 संसदीय सीटों (राजस्थान 25, मप्र 29 और छत्तीसगढ़ 11) में 2019 में भाजपा को 61 और उसके सहयोगी हनुमान बेनीवाल को 1 सीट हासिल हुई थी, हालांकि राजस्थान की नागौर सीट से सांसद बेनीवाल तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान एनडीए से अलग हो गए। अब भाजपा नागौर से 2014 और 2019 में हारीं कांग्रेस की ज्योति मिर्धा को अपने पाले में लाई

## भाजपा को धेरने की पूरी कोशिश

उधर, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की तर्ज पर मप्र में भी 'पे-सीएम' कैपेन चलाकर शिवराज और भाजपा को धेरने की तैयारी में है। आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की रणनीति 2018 के मुकाबले एकदम भिन्न है। 2018 के चुनाव में पार्टी ने राहुल गांधी को ज्यादा तवज्ज्ञी दी थी। इस बार कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड़ा के चेहरे पर दाव लगा रही है। इसकी झलक भी मिल चुकी है। इस बार के चुनावी अभियान का शंखनाद जबलपुर से किया गया जिसका चेहरा प्रियंका गांधी रही, राहुल नहीं। प्रियंका गांधी ने सभा में भाजपा सरकार पर जो आरोप लगाए उन पर भाजपा चुप्पी लगा गई है। भ्रष्टाचार, घोटाले और महंगाई के साथ-साथ लोगों से किए ज्ञाने वाले के आरोपों पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से अभी कोई जवाब नहीं आया है। फिलहाल, शिवराज सिंह चौहान अभी केवल विपक्षियों के आरोपों को देख-सुन रहे हैं क्योंकि अपना कुनबा बचाने की जद्दोजहद ने उन्हें परेशान कर रखा है। इसके बावजूद कांग्रेस को धेरने के लिए भाजपा ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है।

है, ताकि जाटों की कुछ नाराजगी दूर की जा सके। इसलिए भाजपा की चुनौती संसदीय चुनावों में अपना प्रदर्शन दोहराने या कम से कम नुकसान होने देने की है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि तकरीबन 45 सीटों पर भाजपा दो लाख से अधिक वोटों से जीती थी, लेकिन बाकी सीटों पर उसकी जीत का अंतर एक लाख या पचास हजार से भी कम रहा था। जाहिर है, राज्य चुनावों के प्रदर्शन से हवा बदली तो मुश्किल पेश आ सकती है। इसके बरक्स राज्य चुनावों में बेहतर प्रदर्शन से उसे संसदीय चुनावों के लिए फिजा तैयार करने में मदद ही नहीं मिल सकती, बल्कि यह भी साबित करने की कोशिश हो सकती है कि मोदी की लोकप्रियता बरकरार है।

उधर, कांग्रेस की चुनौती यह तो है ही कि उसे इन आधी या उसके आसपास संसदीय सीटें हासिल करनी हैं, लेकिन इसके लिए उसे राज्य चुनाव जीतना भी बेहद जरूरी है। अगर वह राज्य चुनावों में छत्तीसगढ़, राजस्थान की अपनी सरकारें बचा लेती है और मप्र जीत लेती है तो उसकी संभावनाएं कई गुना छलांग लगा सकती हैं और इंडिया गढ़ोड़ के नेतृत्व पर उसकी दावेदारी मजबूत हो सकती है। वैसे, इनमें दो राज्यों में भी कांग्रेस जीत जीती है, तब भी उसकी फिजा को बल मिल सकता है। अभी तक की संभावनाएं यही बताती हैं कि छत्तीसगढ़ और मप्र में वह बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार फिलहाल न सिर्फ मजबूत स्थिति में दिख रही है, बल्कि भाजपा का चेहराविहिन होना भी उसे लाभ दे सकता है। मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने है क्योंकि सत्ता-विरोधी माहौल के अलावा लंबे समय से मतदाता एक ही चेहरा देख-देख कर थक चुके हैं। इसी से मतदाताओं को उत्तराने के लिए शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश का तूफानी दौरा कर रहे हैं। वे हर जिले में कोई बड़ी परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं और खास तौर पर अपने भाषणों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का भरपूर जिक्र करने से नहीं चूक रहे हैं। इस योजना में प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को सरकार हर महीने 1000 रुपए दे रही है। और हो भी क्यों न, जब प्रदेश में कुल 5.39 करोड़ मतदाताओं में से 48.20 प्रतिशत मतदाता महिलाएं हैं और चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पिछले दो चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है, तो जाहिर है चुनाव प्रचार के केंद्र में महिलाएं ही रहेंगी। यही नहीं, मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्रवाई में प्रदेश के 53 में से 41 जिले ऐसे पाए गए जहां महिला वोटरों के नाम ज्यादा जुड़े हैं। कम से कम 50 विधानसभा सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। इनमें अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षित 18 सीटें भी शामिल हैं।

इसके बरक्स कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी में कम से कम ऊपर

मतभेद नहीं दिख रहा है। फिर कांग्रेस मप्र में भी कर्नाटक की तरह शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार के मुददों को हवा दे रही है। राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ सत्ता-विरोधी रुझान भी हो सकता है और राज्य की परंपरा भी है कि हर चुनाव में सरकार बदल जाती है, लेकिन कांग्रेस को राहत भाजपा में स्पष्ट नेतृत्व के अभाव से मिल सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब भी कुछ अलग-अलग दिख रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक

गहलोत भी लगातार कल्याणकारी योजनाओं की बारिश किए जा रहे हैं। तीनों राज्यों की सियासी फिजा पर मौके से रिपोर्ट अगले पन्नों पर हैं।

गौरतलब यह भी है कि तीनों मुख्यमंत्री गहलोत, बघेल और शिवराज सिंह चौहान ओबीसी जातियों से हैं। तीनों ही अपने-अपने तौर पर बड़े मतदाता वर्ग पर डारे डाल रहे हैं और कई योजनाएं उनके लिए ले आए हैं। गहलोत ने हाल ही में राज्य में मूल ओबीसी जातियों के

लिए आरक्षण का ऐलान किया। मूल ओबीसी वहां वे कहलाते हैं, जो जाटों को ओबीसी की फेहरिस्त में शामिल करने के पहले से इस श्रेणी में हैं। कांग्रेस जाति जनगणना का मुद्रदा पहले से ही उठा रही है। अब भाजपा का फोकस भी ओबीसी पर है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से दो हप्ते तक केंद्र के सभी 70 मंत्रियों ने अलग-अलग राज्यों में विश्वकर्मा योजना का आरंभ किया। ध्यान यह भी दें कि हाल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी जाति भेदभाव का मुद्रदा उठाया, जो संघ के पहले के रुख से कुछ अलग है।

ये सब संकेत हैं कि दांव कितना ऊंचा लगा हुआ है। अब देखना है कि इन तीनों राज्यों में ऊंट किस करवट बैठता है और किसकी राहें आसान करता है। मानसून जा चुका है लेकिन मप्र में घोषणाओं और बादों की झड़ी लगी हुई है। लगभग दो महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मददेनजर सत्ताधारी भाजपा एक के बाद एक नई योजनाएं लेकर आ रही है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस उतनी ही तेज रफ्तार से घोटालों का पर्दाफाश कर भाजपा सरकार को चुनौती दे रहा है। सियासी मौसम को देखते हुए कह सकते हैं कि आगामी चुनाव में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर है। दूसरे चुनावी राज्यों के मुकाबले मप्र के चुनावी गणित को समझना सरल है। यहां विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। राज्य में हमेशा कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला होता रहा है। प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में 2018 का चुनाव संभवतः पहला मौका था जब परिणाम फोटो फिनिश जैसा रहा। इस बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री कर ली है। मुकाबला अब परंपरागत रूप से भाजपा-कांग्रेस के बीच होने के बजाय बहुकोणीय होता दिख रहा है।

● इन्द्र कुमार



## दांव पर कांग्रेस की सार

चुनाव में सबकी नजर कांग्रेस समेत अन्य दलों पर टिकी है। इस कांटे की टक्कर में सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने है क्योंकि सत्ता-विरोधी माहौल के अलावा लंबे समय से मतदाता एक ही चेहरा देख-देख कर थक चुके हैं। इसी से मतदाताओं को उत्तराने के लिए शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश का तूफानी दौरा कर रहे हैं। वे हर जिले में कोई बड़ी परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं और खास तौर पर अपने भाषणों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का भरपूर जिक्र करने से नहीं चूक रहे हैं। इस योजना में प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को सरकार हर महीने 1000 रुपए दे रही है। और हो भी क्यों न, जब प्रदेश में कुल 5.39 करोड़ मतदाताओं में से 48.20 प्रतिशत मतदाता महिलाएं हैं और चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पिछले दो चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है, तो जाहिर है चुनाव प्रचार के केंद्र में महिलाएं ही रहेंगी। यही नहीं, मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्रवाई में प्रदेश के 53 में से 41 जिले ऐसे पाए गए जहां महिला वोटरों के नाम ज्यादा जुड़े हैं। कम से कम 50 विधानसभा सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। इनमें अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षित 18 सीटें भी शामिल हैं।

**म**हाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने गौतम अडाणी

से मुलाकात की और फिर राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। दोनों घटनाक्रमों के बाद अटकलें लगने लगे कि शरद पवार विपक्षी गठबंधन से और अजित पवार भाजपा से इतर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत बीते कुछ समय से पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले शिवसेना में शिंदे गुट की बगावत हुई और फिर शरद पवार की एनसीपी में अजित पवार गुट ने बगावत करके भाजपा-शिवसेना के साथ सरकार बना ली। हालांकि, इसके बाद भी राज्य में राजनीतिक तूफान शांत नहीं हो रहा है। कई बार सभी गुट के नेता अपनी-अपनी पार्टी के लीडर को आगामी मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे हैं। अब ऐसे ही एक दावे पर एनसीपी नेता अजित पवार ने प्रतिक्रिया दी है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार से पूछे में पूछा गया कि क्या वे राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे? अजित पवार ने अपने मुख्यमंत्री बनने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री बनने के बारे में पूछे जाने पर अजित पवार ने कहा कि इस खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है। अजित ने कहा कि मैं केवल विकास के बारे में सोचता हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिह्न के मामले में चुनाव आयोग की सुनवाई पर अजित पवार ने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग ही अंतिम निर्णय देगा। उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से तारीख मिलने के बाद दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व चुनाव आयोग के समक्ष किया जाएगा। अजित ने कहा कि चुनाव आयोग का जो भी अंतिम फैसला आएगा उसे वह स्वीकार करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर हक की लड़ाई भारतीय निर्वाचन आयोग के पास भी पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग ने बताया है कि एनसीपी विभाजित है। आयोग ने शरद पवार और अजित पवार दोनों ही गुटों को 6 अक्टूबर को पेश होने और आयोग के सम्मने अपना-अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। दोनों ही गुट भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के समक्ष अपना-अपना पक्ष

## महाराष्ट्र में फिर पक रही खिचड़ी



रखने की तैयारियों में जुटे हैं। महाराष्ट्र में 2019 में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासत तेजी से बदलती रही है। पहले देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर 48 घण्टे के बाद उनका इस्तीफा हुआ और शिवसेना+एनसीपी+कांग्रेस के समर्थन से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने, उनकी सरकार में भी अजित पवार फिर उपमुख्यमंत्री बने थे। बाद में उद्धव सरकार गिरी और शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री बने, जबकि अब इस सरकार को अजित पवार ने भी समर्थन दिया और वह उपमुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा का सियासी गणित जाना भी जरूरी हो जाता है।

साल 2019 का विधानसभा चुनाव भाजपा और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था। दोनों ने मिलकर 161 सीटें हासिल की थीं। जिसमें भाजपा को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थीं। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों का गठबंधन टूट गया। इसके बाद भाजपा और एनसीपी ने मिलकर महाराष्ट्र की सरकार बनाई थी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और अजित पवार उपमुख्यमंत्री बने थे। तब भाजपा के 105 और एनसीपी के विधायकों के समर्थन का दावा राज्यपाल के सामने किया गया था। लेकिन विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद शिवसेना+एनसीपी+कांग्रेस ने गठबंधन किया और महाविकास अधारी गठबंधन के नाम से सरकार बनाई। तब शिवसेना के 56, एनसीपी के 54, कांग्रेस के 44 विधायकों कुछ और दलों व निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनी और

शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और एनसीपी के अजित पवार उपमुख्यमंत्री बने। जबकि कांग्रेस के कुछ विधायक भी सरकार में मंत्री बने थे।

2022 में महाराष्ट्र में सबसे बड़ी सियासी हलचल हुई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बगावत हुई और सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ सरकार से बाहर हो गए। जिससे उद्धव सरकार अल्पमत में आ गई और उद्धव ठाकरे ने बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद एकनाथ शिंदे समर्थक 40 विधायक और भाजपा के 105 विधायकों के अलावा कुछ निर्दलीय और अन्य पार्टियों के समर्थन से सरकार बनी। जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री बने। इस तरह राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनसीपी विपक्ष में बैठी थी, अजित पवार नेता प्रतिपक्ष बने थे। लेकिन 2022 के बाद अब ठीक एक साल बाद 2023 में अजित पवार शिंदे सरकार में उपमुख्यमंत्री बन गए। यानि अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट+भाजपा+अजित पवार की सरकार महाराष्ट्र में है। वहाँ बात अगर एनसीपी की जाए तो राज्य में फिलहाल एनसीपी के 53 विधायक हैं। जिसमें अजित पवार का दावा है कि उनके साथ सभी विधायक हैं। उनका पार्टी पर भी दावा है। जबकि शरद पवार ने जनता के बीच जाने की बात कही है। यानि उन्होंने भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके साथ कितने विधायक हैं। ऐसे में अब विधानसभा के सत्र में यह स्थिति कलीयर होने की स्थिति है कि कितने विधायक अजित पवार के साथ हैं और कितने शरद पवार के साथ हैं।

● बिन्दु माथुर

## अजित पवार के मन में तथा चल रहा है?

महाराष्ट्र सरकार में शामिल गठबंधन के दलों के बीच कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। एनसीपी नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की ओर से ऐसे बयान दिए जा

रहे हैं, जिससे यही संकेत मिल रहे हैं। उनका ताजा बयान उनके वित्त विभाग को लेकर है। महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि यह विभाग अपने चाचा से बगावत करके एनसीपी के ज्यादा विधायकों को तोड़कर भाजपा-शिवसेना सरकार में शामिल होने वाले अजित पवार के लिए कितना महत्वपूर्ण

रहा है। पवार के पास उपमुख्यमंत्री के अलावा एक महत्वपूर्ण विभाग भी है। उन्होंने कहा, आज वित्त मंत्रालय मेरे पास है, इसलिए आपको ज्यादा फायदा (योजनाएं देने में) मिलता है...हालांकि, आगे यह पोर्टफोलियो मेरे पास रहेगा। पवार का यह बयान सत्ताधारी गठबंधन को लेकर पहले से चल रही अटकलावजियों को और बढ़ा रहा है। इसके मुताबिक भाजपा, शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी सरकार के भीतर सबकुछ सही नहीं चल रहा है।

**व** सुंधरा राजे और सचिन पायलट। दो अलग-अलग नेता, अलग-अलग पार्टीयां और अलग-अलग ताकत। लेकिन राज्य एक और लक्ष्य भी एक - मुख्यमंत्री बनना। मगर दोनों दिग्गज अपनी-अपनी पार्टीयों में दरकिनार। दोनों से पार्टी नेतृत्व नाखुश और दोनों की चुनाव में मुख्य भूमिका से बराबर की दूरी। सचिन पायलट तो खँय बीते 5 साल से उनकी अपनी ही पार्टी में किसी गैर की तरह जी रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के बारे में माना जा रहा था कि चुनाव आते-आते वे फिर से मुख्यधारा में आ ही जाएंगी और अपने तेवर भी दिखाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। चुनाव आयोग आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव घोषित करने की तैयारी में है और पार्टीयां भी तैयार हैं, लेकिन न तो कांग्रेस में पायलट की बाजी पलटती नजर आ रही और न ही भाजपा में वसुंधरा को अपनी धरा पर किसी तरह की कोई खास भूमिका मिलने के आसार हैं। लग रहा है कि कांग्रेस की कमान तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ ही रहेगी और भाजपा में अब चेहरे के नाम पर केवल नरेंद्र मोदी ही होंगे। वसुंधरा इसीलिए विकट संकट में हैं क्योंकि कुछ सूझ नहीं रहा, और पायलट इसीलिए पस्त हैं कि करें तो क्या करें!

वसुंधरा राजे और सचिन पायलट दोनों राजस्थान में अपनी-अपनी पार्टीयों में ताकतवर नेता हैं। दोनों एक-दूसरे से कम नहीं। अल्पायु पायलट भले ही कम अनुभवी हैं, लेकिन कांग्रेस में उनका जनाधार मजबूत, तो भाजपा में वसुंधरा की बराबरी का अनुभवी कोई नहीं। दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश राज्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के साथ-साथ कुल 5 बार संसद, 5 बार विधायक, विपक्ष की नेता और जाने कितने पदों पर रही वसुंधरा राजे इन दिनों असाधारण रूप से केवल दर्शक की भूमिका में हैं। कारण केवल यही है कि पार्टी आलाकमान अब उनको किसी भी तरह की बड़ी भूमिका देना नहीं चाहता। पार्टी की परिवर्तन यात्राओं में वसुंधरा राजे की उपस्थिति जरूर दिख रही है और कहीं राजनाथ सिंह, तो कही अमित शाह और कहीं नितिन



## वसुंधरा और पायलट करें तो क्या करें?

गड़करी और जेपी नड़डा अपने भाषणों में वसुंधरा की सरकार में हुए कार्यों की प्रशंसा करके उन्हें खुश भी कर देते हैं। लेकिन कई प्रकार से सक्रियता व ताकत दिखाने के बावजूद वसुंधरा को भाजपा ने अपनी चार में से एक परिवर्तन यात्रा का भी नेतृत्व नहीं सौंपा।

वजह यह कि भाजपा अब राजस्थान में हर जगह नई उम्र का नया नेतृत्व उभारना चाहती है और उस नई पौधे के साथ-साथ कई अन्य नेताओं को एक साथ बड़ा बनाना चाहती है। भाजपा का मकसद यह है कि आने वाले 25-30 साल तक पार्टी में नई पीढ़ी आगे बढ़ती रहे व अपने दम पर सरकारें बनाती रहे। पुरानों को पालकर अब नयापन नहीं लाया जा सकता। इसलिए, राजनीति के कुछ अल्पज्ञानी भले ही यह मान रहे हों कि वसुंधरा राजे केंद्र को आखिर दिखाती रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह उन्हें कम पसंद करते हैं, इसलिए वे उन्हें आगे नहीं आने देना चाहते। मगर, इस तरह के बच्चानों तक देने वाले वसुंधरा की आभा से अभिभूत लोग यह भूल जाते हैं कि दिल्ली में बैठे जो नेता इस चुनाव में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहते, वे राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर हैं।

उधर, कांग्रेस में पायलट के पलटवार थम गए

हैं। दो महीने से शांति है और इस शांति ने अब स्थापित शांति का रूप धर लिया है। कुछ दिन पहले तक पायलट के उददेश्य आक्रामक थे और तेवर तीखे। फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने पार्टी में पायलट अपने पांव जमा ही नहीं पाए। अपनी ताकत दिखाने का आखिरी शक्तिशाली प्रयास किया अजमेर से जयपुर की पदयात्रा करके, मगर उनके इस पदयात्रा से ज्यादा चर्चा रही उनके पांव के छालों की। वे मौन प्रदर्शन पर भी बैठे और नई दिल्ली में आलाकमान के सामने अपनी बात भी रख आए, जिसे राजनीतिक हलकों में अपना दुखड़ा रोने की संज्ञा मिलने से ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ।

कांग्रेस आलाकमान के समक्ष पायलट ने जो तीन मांगें रखीं, वे मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा पलभर में ही जब स्वीकार कर ली गई तो उसी पल यह मान लिया गया था कि होना-जाना कुछ भी नहीं है। हुआ भी वही, पायलट की मांगों पर न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही विमर्श। पायलट फिर भी चुप हैं। कुछ भी नहीं बोल रहे और किसी भी तरह की कोई राजनीतिक हलचल नहीं। बस, इतना जरूर है कि उन्हें कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में सदस्य ले लिया गया है, और राजनीतिक हलकों में इसे उनके मुंह पर चिप्पी चिपकाना कहा जा रहा है। बाद में तो खँय, राजस्थान कांग्रेस में चुनाव के लिए बनी 8 समितियों में किसी भी समिति में उनको न तो अध्यक्ष बनाया गया और न ही कोई प्रभावी जिम्मेदारी मिली।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

## जूनियरों को जिम्मेदारी, पायलट दरकिनार

खास बात यह भी है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद कांग्रेस में सबसे लोकप्रिय नेता होने के बावजूद पायलट के जूनियरों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मगर पायलट पार्टी में लगभग दरकिनार ही रखे गए हैं। हर साल 6 सितंबर को हजारों की भीड़ जमा करके जन्मदिन पर जोरदार जलसा करने वाले पायलट इस बार विधानसभा चुनाव के ऐन पहले भी, बिना कोई जलसा किए पहले ही विदेश चले गए। प्रियंका गांधी राजस्थान आई, तो वे मंग पर जरूर दिखे, लेकिन भूमिका कोई नहीं थी। राजस्थान की राजनीति में, वसुंधरा और पायलट, दोनों सक्रियता दिखाने को बेताब हैं, मगर अपनी-अपनी पार्टीयों में कहीं भी कोई हलचल पैदा न कर पाने के कारण दोनों के समर्थक हैरान हैं। राजस्थान में निश्चित तौर पर वसुंधरा एक बहुत बड़े वर्ग की पहली पसंद हैं, खासकर महिलाओं में। उन्हीं की तरह प्रदेश के कई जिलों में पायलट को पसंद करने वालों की भी बड़ी संख्या है। लेकिन दोनों को उनकी पार्टी ही भाव नहीं दे रही। भले ही कुछ लोग कहें कि दोनों पार्टीयों को इसके नुकसान भी उठाने होंगे, मगर सच यह है कि दोनों ही पार्टीयों का आलाकमान अपने-अपने इन दोनों नेताओं की ताकत को तैलैने के बाद ही उनको दरकिनार किए हुए हैं।

# घो

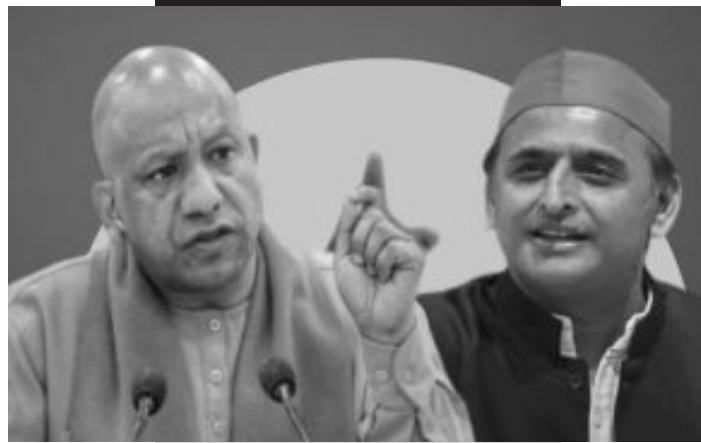
सी उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की करारी हार के बाद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उप्र को लेकर असहज हो गया है। नीति ही नहीं

नेताओं की समीक्षा भी शुरू हो गई है। ओबीसी और जाट को एक साथ साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल की भी समीक्षा हो रही है। भाजपा के भीतरी सूत्रों का कहना है कि चौधरी दोनों ही मोर्चों पर फेल हुए हैं। जाट बहुल खतौली में हार के बाद पिछड़ा बाहुल्य घोसी में भी करारी पराजय ने भाजपा नेतृत्व को अपने फैसले पर सोचने को विवश कर दिया है। फिलहाल, नेतृत्व कोई कठोर कदम उठाने की बजाय डैमेज कंट्रोल में जुट गया है।

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी पर भूपेंद्र चौधरी की नियुक्ति को एक वर्ष से ज्यादा हो चुका है, लेकिन वह संगठन पर अपना मजबूत प्रभाव छोड़ पाने में नाकाम रहे हैं। हालात यह है कि एक साल बाद भी उनकी क्षेत्रीय टीम तैयार नहीं हो पाई है। नए जिलाध्यक्ष तक नियुक्त नहीं हो पाए हैं। बहुत मुश्किल और उत्तरापटक के बाद भूपेंद्र चौधरी ने प्रदेश संगठन में खाली हुए स्थानों को भरा था, उसके बाद क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति की थी लेकिन क्षेत्रीय अध्यक्ष अब तक अपनी टीम नहीं बना पाए हैं। उनकी भेजी हुई सूची प्रदेश स्तर पर लटकी हुई है। दूसरी तरफ, जिलाध्यक्ष बदले जाने का इंतजार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। खबर थी कि पचास फीसदी जिलाध्यक्षों को बदलकर नए चेहरे लाए जाएंगे, लेकिन एक भी अध्यक्ष नहीं बदला जा सका है। प्रदेश स्तर पर त्वरित फैसले नहीं लिए जाने से कार्यकर्ताओं में निराशा है। जिलाध्यक्ष बनने के आकांक्षी एवं अपनी कुर्सी बचाने के लिए परेशान नेता लखनऊ से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, जिससे पार्टी की चुनावी तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। ऐसा ही हाल प्रदेश मीडिया विभाग का है। मीडिया टीम को संतुलित किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष एक वर्ष बाद भी इस विभाग में हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा सके हैं। मीडिया की गुटबंदी का आलम यह है कि आधी से ज्यादा टीम भूपेंद्र चौधरी के बजाय पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह पटेल से नजदीकी दिखाने के लिए उनके निर्देश पर काम कर रही है।

प्रदेश अध्यक्ष को लग रहा है कि मीडिया टीम उनके हिसाब से काम कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि मीडिया टीम प्रदेश अध्यक्ष को अपने हिसाब से चला रही है। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ

# घोसी की हार का घाव



## भगवा पार्टी को न माया मिली ना राम

भाजपा की जयंत चौधरी से अंदरखाने बातचीत चलती रही। डील फाइल होने के बाद मामला बागपत और मुजफ्फरनगर सीट पर आकर अटक गया। रालोद ने इन दो सीटों समेत कुल सात सीटों पर दावेदारी की, लेकिन भाजपा नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं हुआ। दोनों सीटें भाजपा की जीती हुई सीटें थीं। भाजपा नेतृत्व का मानना था कि जब जाट बाहुल्य सभी सीटों पर रालोद ही लड़ेगी तो फिर इस गठबंधन का उसे क्या फायदा मिलेगा? पश्चिम में झटका मिलने के बाद ही नेतृत्व ने पूरब में खुद को मजबूत करने के लिए पिछड़े वर्ग के वोटरों पर फोकस किया। पिछड़े नेताओं को कई स्तर पर प्रमुखता दी गई। एमएलसी सीट पर भी पिछड़ा को प्रमुखता देकर उच्च सदन भेजा गया। पूरब में खुद को मजबूत करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने ओमप्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा से गठबंधन किया, लेकिन घोसी के परिणाम ने भाजपा को परेशान कर दिया है। इस हार को भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान से ज्यादायी स्तर पर नारजीगी की बात कहकर प्रवारित किया जा रहा है, लेकिन परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है कि भावा पार्टी के साथ माया मिली ना राम वाली कहावत चरितार्थ हुई है। जाट ओबीसी की राजनीति साधते-साधते उसका परापरागत सर्वण वोटर उससे दूर छिकता जा रहा है। घोसी में यही हुआ है जिस लेकर भाजपा के भीतरखाने भूयाल आया हुआ है।

खबरें भी मीडिया में लीक की जा रही हैं। उप्र भाजपा का आईटी सेल भी सपा एवं कांग्रेस के हमलों का जबाब देने में नाकाम साबित हो रहा है। राजनीतिक दलों में सबसे मजबूत माना जाने

वाले भाजपा के उप्र आईटी सेल का पिछड़ना भगवा दल के लिए चिंता का सबब बन गया है। यह स्थिति इसलिए बनी हुई है कि प्रदेश अध्यक्ष खुद अपनी कुर्सी को लेकर अश्वस्त नहीं हैं। 2024 की तैयारियों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

दरअसल, स्वतंत्रदेव सिंह पटेल के योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी को उप्र की कमान सौंपी गई थी। नेतृत्व को उम्मीद थी कि भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से पश्चिमी उप्र के जाट बेल्ट में भाजपा को इसका लाभ मिलेगा। ओबीसी वोटरों के साथ सीमावर्ती हरियाणा के जाट भाजपा से जुड़ेंगे। रालोद एवं

जयंत चौधरी के असर को भी इससे कम किया जा सकेगा, जिसका प्रभाव किसान अंदोलन के बाद से बढ़ा है, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी अपने पहले ही इमित्हान में फेल हो गए। चौधरी के नेतृत्व में पश्चिमी उप्र के जाट बहुल खतौली विधानसभा उपचुनाव में भाजपा अपनी ही जीती हुई सीट हार गई। भाजपा के विक्रम सिंह सैनी खतौली सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन दोगे के मामले में कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी चली गई। भाजपा ने विक्रम के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उनकी विधायकी चली गई। भाजपा ने विक्रम के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उनकी विधायकी चली गई। भाजपा ने भाजपा की इस सिटिंग सीट पर गुरुर राजनीति से आने वाले मदन धैया को अपना प्रत्याशी बनाया। चुनाव परिणाम आया तो भाजपा अपनी जीती हुई सीट हार गई। भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाए जाने के बावजूद जाट वोटर भाजपा की बजाय रालोद और जयंत चौधरी की तरफ चला गया। जाट वोटरों को लेकर भाजपा का दांव फेल होने से शीर्ष नेतृत्व परेशान हो गया।

खतौली उपचुनाव में हार के बाद ही भूपेंद्र की नियुक्ति को लेकर दिल्ली टीम असमंजस में पड़ गई तथा 2024 को ध्यान में रखते हुए, जयंत चौधरी को अपने खेमे में लाने की कोशिश में जुट गई। जयंत के एनडीए गठबंधन में शामिल किए जाने की खबरों से भूपेंद्र परेशान हो गए। उन्हें जयंत को खुद से बड़ा जाट नेता मानने में असहजता होने लगी। उन्होंने बयान दिया कि गठबंधन के बाजाय रालोद अगर भाजपा में विलय करता है तो उसका स्वागत है। भूपेंद्र के इस बयान से जयंत को अपने खेमे में लाने के प्रयास में जुटे शीर्ष नेतृत्व को झटका लगा। दिल्ली से भूपेंद्र चौधरी को फटकार लगाते हुए इस मुद्दे पर संयम बरतने का निर्देश दिया गया।

- लखनऊ से मधु आलोक निगम

इंडिया अलायंस के सूत्रधार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बैलैंसिंग फैक्टर वाली राजनीति के लिए जाने जाते हैं। यानी जिस ओर वह होते हैं सत्ता उसी ओर होती है। लेकिन हाल के दिनों में उनकी राजनीति कुछ और संतुलित होती दिख रही है।

हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में न जाना हो, या अचानक ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल हो जाना हो, नीतीश कुमार एक के बाद एक कन्प्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ, बिहार की राजनीति में नए ट्रिव्स्ट के संकेत को लेकर सरगमी बढ़ गई है।

ऐसे में इंडिया एलायंस की मजबूती के दावों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की खबरें भी समान रूप से चर्चा में हैं। इस क्रम में कभी भाजपा पर उनका नरम रूप तो भाजपा का भी उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिख जाता है। फिर अचानक ही वह भाजपा या एनडीए के साथ जाने के किसी भी विचार का खंडन करते हैं और भाजपा भी दूसरी ओर से थोड़ी और अधिक तल्खी से आक्रामक हो जाती है। जाहिर है औवरअॉल कन्प्यूजन की स्थिति दिखती है। इन सबके बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव का रुख भी बड़ा दिलचस्प है। लालू, नीतीश से दूर दिखते हैं और तेजस्वी नीतीश के साथ की तरह नजर आते हैं। ऐसे में आम जनता से लेकर सियासी गलियारों में दिन-रात बिताने वाले लोग भी बेहद कन्प्यूज हैं। दरअसल, ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक इतिहास को लेकर है, क्योंकि इससे पहले 2013 में नरेंद्र मोदी की भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ नीतीश एनडीए से अलग हो गए थे और 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था।

इसके बाद 2015 में उन्होंने पुराने सहयोगी लालू यादव के साथ गठबंधन किया, लेकिन ये सरकार भी 20 महीने ही चल पाई और वर्ष 2017 के जुलाई महीने में आरजेडी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए का दामन थाम लिया और भाजपा के साथ बिहार में सरकार बना ली थी। इसके बाद फिर नीतीश कुमार का मूड चेंज हुआ और 2022 के अगस्त में फिर एनडीए का साथ छोड़ दिया और महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। नीतीश कुमार की शुरुआती राजनीति भी कुछ इसी तरह की रही है। वर्ष 1994 में नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी लालू यादव का साथ छोड़कर लोगों को चौंका दिया था। तब जनता दल से किनारा करते हुए नीतीश ने जार्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया था और 1995 के बिहार विधानसभा चुनावों में लालू के विरोध में उतरे, लेकिन चुनाव में बुरी तरह से उनकी हार हुई। इसके बाद वर्ष 1996 में बिहार में कमज़ोर मानी जाने वाली पार्टी भाजपा से हाथ

# बिहार में फिर कन्प्यूजन !



## नीतीश असहज हों तो राजनीति लेती है नई करवट

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहचान कभी बहुत अधिक बोलने वाले नेताओं की नहीं रही है। उनकी छवि यह है कि वे जो कुछ बोलेंगे, नाप-तौल कर बोलेंगे। अपवाद को छोड़ दें तो अपने वचन पर कायम भी रहेंगे। हाल का अवलोकन यह बता रहा है कि नीतीश बोल ही नहीं रहे हैं। इंटरनेट मीडिया और जन चर्चाओं में उनकी असहज अवस्था पर बहस छिड़ी हुई है। शर्त भी लग रही है कि वाहे कितना भी नुकसान उठाना पड़े, नीतीश फिर से भाजपा के पाले में नहीं जाएंगे। न मिलने की संभावना को भाजपा के लोग यह कहकर और मजबूती प्रदान कर रहे हैं कि उनके लिए भाजपा का दरवाजा बंद हो चुका है, जिसके खुलने की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ यह कहने वालों की कमी नहीं है कि महागठबंधन के अन्य घटक दलों की न पसंद आने वाली गतिविधियां नीतीश कुमार को निर्णय पर पुनर्विचार के लिए मजबूर कर देंगी।

मिला लिया। भाजपा और समता पार्टी का ये गठबंधन अगले 17 सालों तक चला। हालांकि, इस बीच साल 2003 में समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) बन गई। जेडीयू ने भाजपा का दामन थामे रखा और साल 2005 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की। इसके बाद साल 2013 तक दोनों ने साथ में सरकार चलाई।

जाहिर है नीतीश कुमार का सियासी मूड चेंज होता रहता है और इसी के अनुसार, वह पाला बदलने के माहिर माने जाते हैं। अब इसको लेकर लोजपा (रामविलास) के सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। वहाँ, प्रशांत किशोर ने तो नीतीश कुमार की भविष्य की राजनीति को लेकर बड़ी भविष्यवाणी तक कर दी है। चिराग पासवान ने तो इसे मुख्यमंत्री नीतीश को लेकर क्रेडिबिलिटी क्राइसिस तक करार दे दिया है। वहाँ, प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में फिर नीतीश कुमार के पाला बदल लेने की भविष्यवाणी तक कर दी है।

दिल्ली की सत्ता का रास्ता अगर उप्र से होकर जाता है तो, सत्ता परिवर्तन का रास्ता बिहार दिखाता रहा है। जेपी आंदोलन से लेकर कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें बिहार ने सत्ता बदलाव की

कहानी गढ़ी और वह अपने मुकाम तक भी पहुंचा। इस बार फिर बिहार के नीतीश कुमार ने जब केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और विपक्षी गोलबंदी सफल होती दिखने लगी तो लोग कि एक बार फिर बिहार पुरानी कहानी दोहरा सकता है। लेकिन, अब इसमें ब्रेक लगने के क्यास हैं और सत्ता परिवर्तन की जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मूड बदलने की खबरें आम हैं। प्रशांत किशोर उर्फ़ पीके ने इसको लेकर भविष्यवाणी की है (नीतीश कुमार के पलटने का आगामी क्रम) कि बिहार की राजनीति में आगे क्या होने वाला है। प्रशांत किशोर ने कहा, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सहूलियत के हिसाब से नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक दिशा तय करेंगे। पीके ने बताया कि बीते मार्च महीने में दिल्ली में नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग के दौरान नए गठबंधन बनाने पर चर्चा भी हुई थी। मीटिंग की चर्चा करते हुए पीके ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति का अपना अलग तरीका है। वह अपने साथ रहने वाली पार्टियों और लोगों को डराते रहते हैं। नीतीश कुमार यह कहकर ब्लैकमेल करते रहते हैं कि बात नहीं मानी तो पलटी मारकर उधर भी जा सकते हैं।

● विनोद बक्सरी

**16** सितंबर को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस  
उमर अता बांदियाल रिटायर हो गए,  
लेकिन जाते-जाते भी पाकिस्तान की  
राजनीति में खेल  
कर गए। वैसे तो  
अपने पूरे कार्यकाल  
में वो इमरान खान के समर्थन  
में दिए गए फैसलों के लिए  
ही जाने जाते रहे, लेकिन

जाते-जाते 15 सितंबर को तीन जग्हों की बैंच में उन्होंने जो फैसला दिया उसके कारण पाकिस्तानी राजनीति के धुरंधरों की नींद उड़ गई है। जाते-जाते उमर अंता बांदियाल ने फैसला दे दिया कि जनसेवा (राजनीति) में जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्स रहे हैं उनकी फाइलों को नेशनल अकाउंटेंटिलिटी ब्यूरो (नैब) द्वारा दोबारा से खोला जाए। अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और राणा सनाउल्लाह जैसे नेताओं के आपराधिक मुकदमों की फाइलें फिर से खुलेंगी। पहले ही बांदियाल ने इशारा किया था कि वह नैब के मामले में जल्द ही शॉर्ट एंड स्वीट फैसले करेंगे। लेकिन उनका यह शॉर्ट एंड स्वीट फैसला पाकिस्तान के कई नेताओं के लिए बहुत कड़वा साबित होगा।

दरअसल پاکستان के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तानी नेशनल असेम्बली के नैब कानून में उस संशोधन के खिलाफ अपील दायर की थी जिसमें इन बड़े नेताओं के खिलाफ नैब के केस बंद करने का प्रावधान किया गया था। अब यह बांदियाल का इमरान प्रेम है या फिर उनके खिलाफ रहे पीड़ीएम नेताओं के प्रति उनकी खुन्स, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पाकिस्तानी की राजनीति में बहुत असर होने वाला है। इस फैसले में नैब को यह अदेश दिया गया है कि एजेंसी एक ससाह के अंदर सभी नेताओं के भ्रष्टाचार के मामलों की फाइलें संबंधित विभाग या कोर्ट तक पहुंचाए। पाकिस्तान में नैब का पूरा नाम नेशनल अकाउंटेंबिलिटी ब्यूरो है, जो हमारी सीबीआई की तरह ही वहां काम करती है।

पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने पीडीम द्वारा नैब के कानून में संशोधन कर सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे लोगों को नैब की जांच परिधि से बाहर करने के विधेयक पास होने को चुनौती दी थी। इमरान की अपील पर सुनवाई तो पहले ही हो गई थी, लेकिन जस्टिस बांदियाल ने इस फैसले को सुनाने का समय अपने कार्यकाल के अंतिम दिन के लिए रखा था। तीन जांचों की बेंच में जस्टिस बांदियाल के अलावा जस्टिस एजाजुल अहसान और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह शामिल थे। जस्टिस शाह ने इस फैसले में अपनी असहमति नोट कराई है। उन्होंने अपनी असहमति में लिखा है कि यदि पार्लियांगेंट

# जाते-जाते खेल कर गए बादियाल



नए चीफ जस्टिस की इमरान से कोई सहानुभूति नहीं

अब शरीफ परिवार को उम्मीद नए चीफ जस्टिस से है। जस्टिस काजी फैंज ईसा नए चीफ जस्टिस बन रहे हैं। उनकी ना तो बादियाल से बनती थी और ना ही इमरान खान से ही उनकी कोई सहानुभूति है। पीडीएम की पूर्ण सरकार ने जस्टिस ईसा को संसद में बुलाकर सम्मानित किया था। लेकिन उनकी बैच बनने और मामले को दायर होते-होते समय लग जाएग। फिर उनके पास तीन जजों की बैच के इस फैसले के एकदम से उलट निर्णय देना आसान नहीं होगा। क्योंकि इस फैसले से लगभग 2000 बंद केस खुल जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में दायर केसों का निपटारा आसान नहीं होगा। बादियाल के फैसले के बाद अब यह कहना मुश्किल होगा कि नवाज शरीफ की अब वतन वापसी होगी कि नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही नवाज के 21 अक्टूबर को वतन लौटने की तारीख तय की गई थी। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इमरान खान के कहने पर राष्ट्रपति फिर संविधान तोड़ेंगे? पाकिस्तान में चुनाव एक दम सिर पर खड़े हैं। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी पूरे दम से इस प्रयास में लगे थे कि 2023 के नवंबर में ही चुनाव हो जाएं, लेकिन अब 2024 के जनवरी के अंत में चुनाव होंगे। पाकिस्तान चुनाव आयोग भी ज्यादा लंबे समय तक चुनाव टालने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालात खराब होती जा रही है। देश में एक स्थाई सरकार नहीं होने के कारण फैसलों में काफी दिक्कतें आ रही हैं। जनता भी हर रोज जदोजहद कर रही है। मुस्लिम लीग को उम्मीद थी कि नवाज शरीफ यदि समय से वतन वापस आकर चुनाव को संभाल ले तो सरकार बन सकती है। फिलहाल तो बादियाल ने उस पर ग्रहण लगा दिया है।

नैब के कानून बना सकता है तो उसमें संशोधन भी कर सकता है, जबकि जस्टिस बांदियाल एवं जस्टिस अहसान ने इस तर्क को आगे बढ़ाया है कि गंभीर मामलों में किसी को कानून से बाहर रखने का फैसला पाकिस्तानी संविधान के विपरीत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट संशोधन को खारिज करता है।

सुप्रीम कोर्ट की इस बैंच ने 55 पृष्ठ के अपने फैसले में सभी नेताओं के खिलाफ पूर्व में नैब में दर्ज सभी मामलों की जांच फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंटेंटिलिटी कोर्ट को भी मामले की सुनवाई कर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है। नैब को सभी फाइलें भी तुरंत जमा कराने को कहा है। बांदियाल और उनके साथी जज ने अपने फैसले में यह भी कहा कि पार्लियामेंट द्वारा किए गए संशोधन से संविधान की धारा 14, 24 और 25 का उल्लंघन हआ था।

जस्टिस बांदियाल की इस बेंच के फैसले ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, फरयाल ताजपुर, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, जावेद लतीफ और आसिफ अली जरदारी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। यदि

जल्दी ही इस फैसले पर रोक नहीं लगी तो आने वाले चुनावों में इन सभी नेताओं के भाग लेने की संभावना कम हो जाएगी। नवाज शरीफ को पहले से ही चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया गया है। दरअसल नैब के कानून में संशोधन ही इसलिए किया गया था ताकि नवाज शरीफ पर से आजीवन चुनाव न लड़ने वाले प्रतिबंध को हटाने का रास्ता निकल जाए। इस मामले में पीडीएम में शामिल सभी नेताओं की भी सहमति नवाज को प्राप्त थी।

अब पाकिस्तान की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि राजनीति में सक्रिय सभी प्रमुख नेताओं पर किसी न किसी मामले में केस चल रहा है। इमरान खान को राजनीति से बाहर करने का उपक्रम पहले से ही चल रहा है। 9 मई के हांगामे के बाद इमरान को चुनाव लड़ने से ही अयोग्य ठहराए जाने की संभावना है। उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा भी चलने वाला है। अब जस्टिस बांदियाल की इस बैंच के फैसले ने इमरान के साथ-साथ उनके विरोधियों को भी अदालत के चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया है।

## ● ऋतेन्द्र माथुर

**ज** स्टिन टूडो 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और वह आगे भी रहना चाहते हैं। उनके पिता पियरे टूडो 15 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे। पर कनाडा की जनता नहीं चाहती कि जस्टिन अब और प्रधानमंत्री पद पर रहे। इसी साल 18 से 23 अगस्त के बीच में अबैक्स डाया ने एक नेशनल सर्वे किया था जिसमें 2,189 युवाओं ने भाग लिया था। सर्वे में भाग लेने वाले 56 प्रतिशत युवकों का सीधा कहना था कि अब जस्टिन को अपने पद से उतर जाना चाहिए। जस्टिन को भी मालूम है कि मुद्रा स्फीति बढ़ने, मकान बहुत महंगे होने और कंजरवेटिव पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ने के कारण उन पर पद छोड़ने का दबाव है और एक हफ्ता पहले जब पत्रकारों ने उनसे पूछा भी कि क्या वे पद छोड़ रहे हैं? तब टूडो ने ना में जवाब दिया था और कहा था कि उनके पास बहुत से महत्वपूर्ण काम करने को हैं। भारत पर सनसनीखेज इल्जाम लगाकर अपनी कुर्सी बचाने की जुगत ही संभवतः उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था जो उन्होंने किया है।

कनाडा में अभी आम चुनाव होने में दो साल का समय है। इन हालातों में टूडो के लिए इतने दिन बने रहना संभव नहीं था, क्योंकि टूडो लगातार विफल हो रहे हैं। एक ऊर्जावान नेता की बजाय वे उलझे हुए नेता लग रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी पत्नी को तलाक देने की घोषणा भी की है, जिसका कनाडा के कंजरवेटिव नेताओं ने खूब मजाक भी उड़ाया था। भारत पर आरोप लगाकर कनाडाई जनता का समर्थन प्राप्त करने के जोखिम भरे कदम को उठाने से पहले वह राजनीतिक कलाबाजी को आजमा चुके हैं। इसी साल 26 जुलाई को उन्होंने अपनी कैबिनेट में एक बड़ा बदलाव कर सात लोगों को शामिल किया था। पर यह बदलाव भी काम नहीं आया और कनाडा की जनता का गुस्सा उनके प्रति कम नहीं हुआ, जिसका सबूत कैबिनेट में बदलाव के बाद आया नेशनल सर्वे रहा।

टूडो परिवार एवं खालिस्तानी आतंकवादियों का संबंध लगभग 40 साल पुराना है। 23 जून 1985 को एयर इंडिया का विमान एआई 182 मार्टियाल से लंदन होते हुए बंबई आ रहा था। उसमें 329 लोग सवार थे। बीच आसमान में इस जहाज में विस्फोट हुआ और सभी लोग मारे गए। इतिहास में इसे कनिष्ठ एयर इंडिया बॉम्बिंग के नाम से दर्ज किया गया। इस बम कांड में खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा के लीडर तलविंदर सिंह परमार का नाम आया। यह आतंकवादी भारत में 1981 में दो पुलिसवालों की हत्या कर कनाडा फरार हो गया था।

1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तब जस्टिन टूडो के पिता और कनाडा के प्रधानमंत्री पियरे से अनुरोध किया था कि वह वांछित परमार को भारत को सौंप दे, लेकिन तब

# अपने ही जाल में फंस गए जस्टिन टूडो



## सरकार बचाने की चिंता

टूडो के लिए समस्या सिर्फ अपनी लोकप्रियता बचाने की नहीं है, बल्कि सरकार बचाने की भी है। इस समय उनकी पार्टी को सदन में बहुमत नहीं है। उनको समर्थन दे रही है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके अध्यक्ष हैं जगमीत सिंह। जगमीत सिंह पेशे से वकील रहे हैं, लेकिन कनाडा में वह खुलेआम खालिस्तान का समर्थन करते हैं। जगमीत ने भारत में किसान आंदोलन का खुला समर्थन किया था और प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर आलोचना। जगमीत की पार्टी के पास इस समय 24 सीटें हैं जो जस्टिन टूडो का समर्थन कर रहे हैं। इसी जगमीत ने पंजाब में सक्रिय खालिस्तानी अमृतपाल को पंजाब पुलिस से बचाने के लिए कनाडा सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए टूडो से कहा था। जाहिर है जस्टिन टूडो अपनी सरकार बचाने के चक्रकर में भारी गलती कर बैठे हैं। टूडो ने जी-20 के सम्मेलन से लौटते ही सीनेट में भारत के खिलाफ बयान देकर खुद के लिए ही गड़दा खोद लिया है। ना तो कनाडा के अंतरराष्ट्रीय सहयोगी जस्टिन टूडो की बातों को गंभीरता से ले रहे हैं और न उनको कनाडा के अंदर ही कोई सहयोग मिल रहा है। बल्कि उनके इस दावे पर कि कनाडा की खुफिया एजेंसियों के पास इस तरह की सूचना है जिससे खालिस्तान समर्थक सिख नेता हरदीप सिंह निजर की हत्या में भारत सरकार का हाथ हो सकता है, कनाडा में ही कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है।

सीनियर टूडो ने यह कहकर उस आतंकवादी को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया कि उनका देश भारत के साथ प्रत्यार्पण की संधि से नहीं बंधा है इसलिए वह परमार को नहीं भेजेगा। हालांकि परमार बाद में भारत आया और 1992 में पंजाब पुलिस से मुठभेड़ में मारा भी गया लेकिन तब से लेकर टूडो परिवार और खालिस्तानी नेताओं के बीच मधुर संबंध चले आ रहे हैं।

कनाडा की 3.82 करोड़ जनसंख्या में सिख आबादी के हिसाब से 2.1 प्रतिशत हैं पर कुछ जगह इनकी संख्या छह प्रतिशत से भी अधिक है। जैसे ब्रिटिश कोलंबिया जहां टूडो का सबसे अधिक समय बीता है, वहां सिखों की आबादी छह प्रतिशत है। वेंकूवर, टोरंटो और कैलगेरी में बड़े-बड़े गुरुद्वारे हैं। ये गुरुद्वारों कनाडा की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन गुरुद्वारों में कनाडा की लिबरल और कंजरवेटिव दोनों पार्टीयों की पैठ है। कई सिख नेता इन्हीं गुरुद्वारों के प्रभाव से कनाडा की राजनीति में अपनी पकड़ बना के रखते हैं।

2019 में कनाडा में चुनाव प्रचार के दौरान ही जस्टिन के समर्थन के बदले सिखों के स्वेच्छाचार का मुद्दा उठा था। तब कुछ पार्टीयों ने यह नारा दिया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ लगाम लगानी चाहिए। पर टूडो की पार्टी ने सिखों से कुछ और वायदा किया। उस समय वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के कानूनी सलाहकार बलप्रीत सिंह ने कहा था—यह कनाडा के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव का क्षण है। अंततः नस्लों का विषय एक चुनावी मुद्दा बन गया है। एक देश के रूप में इस मसले को राजनीतिक तौर पर लेंगे। अब इस मामले पर आगे और भी कई चीजें आएंगी। और हुआ भी ऐसा ही। सिखों को अपनी पहचान के साथ रहने, अलगवावादियों को खुले में प्रदर्शन करने में कहीं कोई रोक नहीं लगी। जस्टिन टूडो ने खालिस्तानी नेता हरजीत सिंह सज्जन को अपना रक्षा मंत्री बना डाला। फिलहाल सज्जन मिनिस्टर फॉर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और पैसिफिक इकॉनोमिक डेवलपमेंट है। सज्जन को लेकर भारत सरकार कई बार कनाडा सरकार को सचेत कर चुकी है। लेकिन टूडो गर्व से यह कहते हैं कि भारत सरकार में जितने सिख मंत्री नहीं हैं उससे अधिक सिखों को उन्होंने मंत्री बनाया है।

● कुमार विनोद

**गृ** ह मंत्रालय ने संसद में एनसीआरबी की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी है जिसके मुताबिक भारत में साल 2019 से 2021 यानी दो साल के बीच ही 13.13 लाख से गई हैं। ये कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाएं कहां गईं, इनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। हमने स्त्रियों को भले ही देवी के रूप में मर्दिरों में स्थापित कर रखा है या नवरात्रों में कन्या-पूजन का मानक बना रखा है। लेकिन स्त्रियों की वास्तविक स्थिति को हम सिरे से नकार दे रहे हैं। इन लापता लड़कियों में 18 साल से कम और उससे ज्यादा दोनों उम्र की महिलाएं शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार जहां 2,51,430 लापता लड़कियों की उम्र 18 साल से कम है तो वहीं 10,61,648 लापता महिलाओं की उम्र 18 साल से ज्यादा है।

जिस देश में एक नारी छल से अगवा कर ली गई तो त्रिलोक विजयी रावण को काल के गाल में भेज दिया गया, वहां हर रोज इतनी स्त्रियों का गायब हो जाना क्या इतना सहज है? समाज में, सरकार में इसकी स्वीकृति भी सरल लग रही है। ऐसा लगता है हम शनै: शनै: अभ्यस्त हो गए हैं। बेटियों की सुरक्षा हमेशा गंभीर मुद्दा रहा है, पर अफसोस यह सिर्फ मुद्दा ही रहा है। स्त्रियां पहले से ही भ्रूण हत्या, यौन हिंसा, दहेज, मानसिक प्रताड़ना जैसी यातनाओं से एक लंबे समय से जूझ रही हैं। समाज की उनके प्रति ऐसी अनदेखी स्त्री अनादर है। कोई भी समाज, परिवार या देश महिलाओं के मुद्दे को दर्किनार करके सुख शांति और समृद्धि नहीं पा सकता है। जैसा की मनुस्मृति भी कहती है कि जहां स्त्रियों का आदर किया जाता है वहां देवताओं का वास होता है। उस देश में जहां स्त्रियों को लेकर इतने उच्च आदर्श स्थापित किए गए हों वहां इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के गायब होने का क्या अर्थ हो सकता है? गायब स्त्रियों का गंतव्य क्या हो सकता है?

इसके कई सामाजिक और परिस्थितिजनक कारण हो सकते हैं। इसमें से एक मानव तस्करी और देह व्यापार भी है जिसमें जबरन धकेली गई लड़कियों को लेकर भी कई आंकड़े बहुत भयावह हैं। कम उम्र की गायब होती लड़कियों से जुड़े ऐसे मामले भी प्रकाश में आए हैं कि उन्हें किशोरी जैसी शारीरिक बनावट, उभरे वक्ष और सुडौल शरीर में जल्दी बदलने के लिए हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। जैसे मवेशियों को ऑक्सीटेसिन का इंजेक्शन देकर उनके दूध देने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, वैसे ही 7-8 वर्ष की लड़कियों को भी इंजेक्शन देकर उन्हें उम्र से पहले युवा बनाते हैं और उनमें यौन इच्छाएं जागृत करते हैं ताकि देह व्यापार में उनका उपयोग किया जा सके। मेट्रोपॉलिटन शहरों में घरेलू कामकाज के

# लापता वर्षों हो रही हैं लड़कियां?



## कई राज्यों में महिलाओं की कमी चिंताजनक

राजस्थान जैसे राज्यों में जहां महिलाओं की संख्या काफी कम है, वहां से जबरन शादी की घटनाएं अवसर सुनाई देती हैं। बिहार, पूर्वोत्तर राज्य और उपर से लड़कियां कई बार बहला-फुसलाकर लाई जाती हैं और अनजाने परिवार में जबरदस्ती व्याह दी जाती हैं। ध्यान देने योग्य यह भी है कि लड़की के परिवार को पता ही नहीं रहता कि लड़कों की कहां गई या दया हुआ। ऐसे आंकड़े वास्तव में डराते हैं। कई आशंकाओं से मन व्यथित और विचलित होता है। इस समस्या का समाधान राजनीतिक इच्छाशक्ति तक सीमित नहीं है। समाज को लड़कियों के प्रति उदारता का रवैया अपनाना होगा और उसकी पसंद को भी महत्व देना होगा। समाज की प्रतिष्ठा, उन्नति और स्वभाव इस बात से निर्धारित किया जाता है कि उस समाज में नरियों की स्थिति क्या है? गैर सरकारी संस्था क्राई की 2022 की एक रिपोर्ट मानें तो 2021 में सिर्फ राजस्थान और मप्र में लापता लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में पांच गुना अधिक है। कम उम्र की लड़कियों का ऐसे गायब होने का अर्थ बाल अपराध में बढ़ावा भी है। बच्चों से भीख मंगवाने वाला गैंग, उनसे चोरी-डैकेती कराने वाला गिरोह, मासूम बच्चों को चारा बनाकर लोगों को लूटने वाला गैंग हर राज्य में सक्रिय है। ऐसे में लड़कियों की गुमशुदगी हर सर पर अपराध को बढ़ावा देती ही नजर आ रही है। इससे जो सामाजिक ताना-बाना बिगड़ा है और निरंतर बिगड़ता नजर आ रहा है उसका उपाय यही है कि समाज वास्तविक अर्थों में बदलते समय के साथ स्त्रियों के अधिकार और व्यवहार को स्वीकार करे, वर्ना वो दिन दूर नहीं जब बेटियां इस समाज के प्रति इतना बगावती रुख अखिलायां करेंगी कि स्वयं संभलना और उनको संभलना दोनों मुश्किल हो जाएगा।

लिए भी लड़कियों की जरूरत होती है। कई बार ऐसे बहलाई या अगवा की हुई लड़कियां जीवनभर के लिए किसी न किसी परिवार की गुलाम बन जाती हैं।

भावनात्मक और मानसिक स्थिति भी इसके पीछे बड़ी बजह मानी जाती रही है। जब हम नारी सुरक्षा की बात करते हैं तो यह सिर्फ उसकी शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रखी जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं ने सशक्तिकरण के दौर को जीना प्रारंभ किया है। जहां बेटियां लगातार कई वर्षों से दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक आने से लेकर औसत सफलता में भी लड़कों को मात दे रही हैं। इससे जैसी संस्था में महिला की अगुवाई में चंद्रघान जैसे मिशन सफलता को छू रहे हैं, वहां ये सब सिक्के का बोल्डन को पहलू है जो जगमगाता, चमचमाता नजर आता है। दूसरी ओर अभी भी स्कूल-कॉलेज का मुंह देखने को तरसती लड़कियों का हुजूम दिखता

है। मतलब समाज का एक वर्ग है जो लड़कियों को आगे बढ़ते देखना भी चाह रहा है तो अपनी शर्तों पर।

जो लड़कियां भाग्यशाली हैं वो तो पढ़-लिख रही हैं परंतु पूर्व में स्थापित मानकों के परे जाकर स्त्री की पढ़ाई, कैरियर या प्रेम कुछ भी स्वीकार्य नहीं हो पा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप लड़कियां या स्त्रियां चुपचाप भी घर छोड़ दे रही हैं। समान के साथ जीना और अधिकारों को प्राप्त करना एक सामान्य और बुनियादी जरूरत है। इसमें बरती गई कोताही भी क्या घर छोड़ने का सबब बन रही है? कैरियर, प्रेम या घर-परिवार में किसी बात से नाराज होकर भी लड़कियां अपनी मर्जी से घर से चली जा रही हैं। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, और अगर इसमें उनका परिवार और समाज अवरोध नजर आता है तो वो ऐसे समाज या परिवार का त्याग कर रही हैं।

● ज्योत्सना

# **mycem power**

**Trusted German Quality**

**Over 150 Years**



Send 'Hi' 7236955555

**म** हा भारत की रणभूमि में अर्जुन को भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। यह सारा ज्ञान भगवत् गीता में दर्ज है। जिसमें जीवन के बहुत से मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं। जिन्हें जीवन में उतार लिया जाए तो व्यक्ति को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। वह हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाता है।

गीता की बातों को अपनाने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसका अनुसरण करने वाले व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासारिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। आज के समय में बच्चे फोन के गुलाम बनते जा रहे हैं। जिस कारण उनमें स्सकरों की कमी पाई जाती है। ऐसे में उनके परिवारालों को उन्हें गीता के ये श्लोक पढ़ाने और समझाने चाहिए। इन श्लोकों से उनमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा।

**कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।**

**मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥**

बच्चों की आदत होती है कि अगर वह कोई काम करते हैं तो उन्हें उसके परिणाम का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में यह श्लोक उनके बहुत काम आ सकता है। इस श्लोक का अर्थ है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल की इच्छा के लिए मत करो।

**ध्यायते विषयान्पुः सङ्गस्तेषूपजायते ।**

**सङ्गासंज्ञायते कामः कामाल्कोथोऽभिजायते ॥**  
अर्थ- विषय-वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे लगाव हो जाता है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में बाधा आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि किसी चीज के लगाव से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। बच्चे किसी चीज को देखते ही उसकी जिद करने लगते हैं। और न मिलने पर जल्द ही गुस्सा भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह श्लोक उत्तम है।

**क्रोधाद्वृति संमोहः संमोहात्मृतिविभ्रमः ।**

**स्मृतिप्रश्नाद्विद्विनाशशो बुद्धिनाशात्रणश्यति ॥**  
अर्थ- क्रोध से मनुष्य की मति यानी बुद्धि मारी जाती है। बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। कई बच्चों को

## गीता से मिलती है सकारात्मक ऊर्जा



बहुत गुस्सा आता है। ऐसे में यह श्लोक उन्हें गुस्सा करने से होने वाले नुकसानों से अवगत कराता है।

**यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।**

**स यत्प्रमाणं कुरुते लोकसदनुवर्तते ॥**

अर्थ- श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण यानी जो-जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण या कहें कि वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव-समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। यह श्लोक अच्छे आचरण के फायदे बताता है। जो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है।

**श्रद्धावान्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।**

**ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥**

अर्थ- श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम-शांति को प्राप्त होते हैं। धन्दे वाले बच्चों के लिए यह श्लोक बहुत ही उत्तम है। यह उन्हें एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करता है।

गीता एक ऐसा मधुर गीत है, जो जीवन के लक्ष्य की ओर इंगित करता है कि हे मानव, तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब तक हमें इस बात का पता नहीं होगा कि जीवन में क्या प्राप्त करना है, हमें कहां जाना है और क्या पाना है, कौन सा मार्ग लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयुक्त है। मन में उठने

वाले इन सभी प्रश्नों का उत्तर श्रीमद्भगवत् कथा के श्रवण से मिल सकता है। सत्संग के अभाव में निसदेह मानव की मानवता लुप्त होने लग जाएगी। तब मानव अपने मानवीय मूल्यों से गिरने लग जाएगा। इसलिए यह परम आवश्यक

है कि श्रीमद्भगवत् गीता को जीवन का गीत बनाया जाए। गीता का संदेश है कि मानव का लक्ष्य केवल धन अर्जित करना अथवा संसार की प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं है। गीता संकेत करती है कि मानव योनि सब योनियों से श्रेष्ठ है।

जीव को यह मानव शरीर बड़े भाग्य और पुण्यों से मिलता है। इसलिए श्रीमद्भगवत् गीता के संदेशों को धारण करके जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। मानव जीवन का लक्ष्य विषय भोग नहीं बल्कि परम अनांद की प्राप्ति करना है। उन्होंने कहा कि मानवता रूपी धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं तथा मानवता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं।

जीवन में उतार लें भगवान् श्रीकृष्ण की ये बातें- परिवर्तन संसार का नियम है। जिस समाज

में हम रह रहे हैं कुछ वर्षों पहले तक ये ऐसा नहीं था और न ही हमेसा ऐसा रहेगा। शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मरता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। व्यक्ति को कभी भी ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है, न कि अपना लक्ष्य। सभी मनुष्यों का निर्माण उनके अपने विश्वास द्वारा ही होता है। जो व्यक्ति जिस मान्यता पर भरोसा करता है वो वैसा ही बन जाता है। अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। क्योंकि कार्य करना, पूर्ण निष्क्रियता से बेहतर है। अपने मन से सभी प्रकार के भेदभाव जैसे अपना-पराया, छोटा-बड़ा, मेरा-तेरा आदि मिटा दें। फिर आप देखेंगे कि सब कुछ आपका है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनाना पड़े तो इससे पछें नहीं हटना चाहिए। जीवन में हार-जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ता है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच का दूरदर्शी होना बेहद जरूरी है।

## जब कभी बोझिल हो मन



जब कभी भर आएं आँखें,  
जब कभी बोझिल हो मन  
प्रेम से अपने हृदय से  
याद कर लेना मुझे  
जिंदगी गर धूप है,  
तो छांव भी मिल जाएगी  
राह में गर न मिले कोई,  
तब याद मेरी आएगी  
जब कोई बीता हुआ पल,  
तुमको रुलाए कभी  
प्रेम से अपने हृदय से  
याद कर लेना मुझे  
रात जब सूनी कोई,  
तुमको जो तड़पाए तो  
ऐसे मैं जब कभी,  
कोई याद तुमको आए तो  
है बहुत गमगीन जीवन,  
पर न घबराना कभी  
प्रेम से अपने हृदय से  
याद कर लेना मुझे  
तुमको नहीं होगा पता,  
कि मेरी क्या मजबूरियां  
पर कभी दिल से तुम्हारे,  
होंगी नहीं कोई दूरियां  
जब कभी सपने मैं तुम,  
नींद में डर जाओ तो  
प्रेम से अपने हृदय से  
याद कर लेना मुझे  
दुख दर्द सारे जिंदगी के,  
बांट लूंगा मैं तुम्हारे  
प्रेम के दो शब्द दिल से,  
जो सुनोगे तुम हमारे  
जब किसी को सोचकर तुम,  
मुस्कुराओगे कभी  
प्रेम से अपने हृदय से  
याद कर लेना मुझे

- प्रमोद कुमार स्वामी

**व** सुंधरा जी पहली बार अपने बेटे के साथ हैदराबाद तक का सफर, वह भी फ्लाइट में कर रही थीं। विंडो सीट खास कर उन्होंने पसंद किया था। क्या देख रही हैं अम्मा?

उनकी तन्मयता भंग हुई, बेध्यानी में निकल गया-दिल बाग-बाग हो गया, मैं हमेशा से तेरे पिताजी को कहती थी, पूत के पांव पालने मैं ही नजर आते हैं, तेरे जन्म के बाद से ही तुझे आम बच्चों की तरह धूल में खेलना बहुत पसंद था। सच मैं तू मेरा धूल का फूल है।

मां आप क्या-क्या

बोल रही हैं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

बेटा भूल हो गई- सच मैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मैं खिड़की से बाहर बादलों के ऊपर उड़ते हुए अपने कोख-जाये की उपलब्धि पर फूली नहीं समा रही थी। असीम आनंद अनुभव कर रही हूं।

अच्छा ! तभी मैं कहूं मां शून्य में गुम सी क्यों हो गई हैं?

बेटा, आकाश में उड़ना सच मैं तुमने महसूस करा दिया, जब मैं तुम्हें ऊंची शिक्षा के लिए स्वयं से दूर कर



## ममता की मूरत...

बताओ तुमने अपने लिए जीवन-संगिनी ढूँढ़ ली है क्या?

थोड़ा शरमाते हुए हां मां- आपकी बहू चांद सी है।

हाहाहा...बेटा आप भला तो जग भला, तुम तो मेरी आँखों का तारा हो, अंगूठी मैं नगीने सी बहू मिल गई, फिर तो मेरे दोनों हाथों मैं लड्डू हैं।

मां सचमुच आप खुश हैं! फिर तो मुझे जन्नत की चाहत नहीं।

- आरती राय

**ब** त बहुत पुरानी है। रत्नपुर में दो भाई रहते थे। उनका नाम था- दुर्जन और सुजन। दुर्जन जितना दुष्ट था, सुजन उतना ही नेक और सीधा-सादा किंतु वह बहुत ही गरीब था। दुर्जन सुजन की गरीबी पर खूब हसता। वह भले ही दूसरों को रुपया-पैसा आदि उधार में दे देता, किंतु अपने छोटे भाई सुजन को फूटी-कौड़ी भी नहीं देता था।

एक दिन सुजन की पत्नी ने अपने पति से कहा- क्यों जी, हम कब तक इस गांव में भूखों मरंगे। यहां तो ठीक से मजदूरी भी नहीं मिलती।

तो तुम्हीं बताओ ना कि मैं क्या करूं। सुजन ने लम्बी सांस खींचते हुए कहा।

क्यों न हम अपने खेतों की बैंगन को पड़ोसी देश में ले जाकर बेच दें। सुना है वहां के लोग बहुत धनी हैं। अच्छे दाम मिल जाएंगे। पत्नी का जवाब था।

बात सुजन को भी जंच गई। दूसरे ही दिन वह बोरियों में बैंगन भर कर अपने बैलगाड़ी में लादा और पड़ोसी

## सोने के भाव बिके बैंगन



राज्य की ओर चल पड़ा।

पड़ोसी राज्य के लोगों ने पहले कभी बैंगन नहीं खाया था। बैंगन खाकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सब बैंगन खरीद लिए और उसके बजान के बराबर सोना-चांदी तौल दिया।

सुजन बहुत खुश हुआ। धनवान बनकर वह अपने गांव लौट आया।

दुर्जन ने जब अपने छोटे भाई सुजन को अमीर होते देखा, तो वह इसका राज जानने के लिए सुजन के पास आया। सुजन ने सब कुछ सही-सही बता दिया।

दुर्जन भी कुछ दिन बाद अपनी गाड़ी मैं बहुत सारा बैंगन लाद कर पड़ोसी राज्य के लोग अधिक मात्रा में बैंगन खाने से बीमार पड़ने लगे। जब उन्होंने सुजन के हम शक्ल दुर्जन को बैंगन लेकर आते देखा तो उसे सुजन समझकर मार-पीटकर अपने देश से भगा दिया।

दुर्जन यह समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर उसका कसूर क्या है?

- डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा

**पा** किस्तान के खिलाफ खेले गए एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में विराट कोहली ने नाबाद 121 रनों की पारी खेली। कोहली का यह एक दिवसीय क्रिकेट में 47वां शतक था। जबकि टेस्ट क्रिकेट में 29 और टी-20 फॉर्मेट में 1 शतक है। कुल मिलाकर उनके नाम 77 शतक हो चुके हैं। ऐसे में क्रिकेट प्रेमी सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोहली क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के विश्व रिकॉर्ड 100 शतकों की बराबरी या उनसे ज्यादा शतक लगा पाएँगे?

पाकिस्तान की मेजबानी में भारत-श्रीलंका के बीच खेले गए एशिया कप 2023 के खिताबी मुकाबले से पहले बारिश शुरू हो गई थी। इस वजह से मैच शुरू होने में थोड़ी देरी हुई। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाज श्रीलंका पर कहर बनकर टूट पड़े। श्रीलंका ने महज 12 रनों के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद टीम ने कुछ और रन जोड़े और 50 के स्कोर तक टीम ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में भारत ने बिना किसी नुकसान के 6.1 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की जीत में मोहम्मद सिराज की अहम भूमिका रही। सिराज ने 7 ओवरों में 21 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। वहीं हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने उनका भरपूर साथ दिया। पांड्या ने 2.2 ओवरों में 3 रन देकर 3 विकेट लिए तो जसप्रीत बुमराह ने 5 ओवरों में 23 रन देकर 1 विकेट लिया।

भारत की ओर से शुभमन गिल ने 19 गेंदों में नाबाद 27 रन बनाए, तो ईशान किशन ने 18 गेंदों में नाबाद 23 रन बनाए। इस तरह भारत ने श्रीलंका को एशिया कप 2023 के फाइनल में 10 विकेट से शिक्षण देकर आठवीं बार एशिया कप के खिताब पर कब्जा कर इतिहास रच दिया है। एशिया कप में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जहां भारत के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, वहीं फाइनल मुकाबले में मोहम्मद सिराज को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन खेल जगत में सबसे ज्यादा चर्चा भारत और पकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले की हो रही है। दरअसल इस मुकाबले में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार शतक लगाया। यह उनके बनडे करियर का 47वां शतक था। वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से सिर्फ दो कदम दूर हैं। तेंदुलकर ने 463 बनडे मैचों में 49 शतक लगाए हैं। कोहली के 278 मैच में 47 शतक हो गए हैं। कोहली ने 267वीं पारी में ही 47 शतक लगा दिए हैं। वहीं, सचिन ने इसके लिए 435 पारियां खेली थीं। ऐसे में क्रिकेट प्रेमी सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोहली क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के टेस्ट और बनडे



# शतकों के सम्राट् बनेंगे विराट!

## 2026 तक 100 संभव!

खेल विशेषज्ञों का कहना है कि विराट ने साल 2017 और 2018 मिलाकर 99 पारियों में ही 22 शतक जमा दिए थे। यानी हर 4.5 पारी में एक शतक। इस स्पीड से कोहली फिर शतक बनाने लगे तो 108 पारियों में ही वे 24 शतक और जमा देंगे। यानी 3 साल में 2026 तक विराट शतक सम्राट् बन सकते हैं। पिछले 12 महीनों में कोहली जिस नए अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं इससे पूरे संकेत मिलते हैं कि वे 2017-2018 वाली फॉर्म में लौट रहे हैं। इस महीने बनडे विश्व कप भी ही है और कोहली बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म करने का मौका तो कभी चूकते ही नहीं है। वहीं कुछ खेल पंडितों का मानना है कि विराट 100 शतकों का आंकड़ा पार करेंगे या नहीं, यह उनकी फॉर्म और फिटनेस के साथ-साथ इस बात पर भी निर्भर है कि वे ब्रेक कितना लेते हैं। पिछले कुछ सालों में विराट ने जमकर ब्रेक लिया है या ये कहें कि सीनियर होने के नाते उन्हें बहुत रेस्ट दिया गया है।

क्रिकेट में 100 शतकों के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी या उनसे ज्यादा का शतक लगा पाएँगे?

खेल विश्लेषकों का कहना है कि विराट 100 या इससे ज्यादा शतक बना पाएं इसके लिए जरूरी है कि वे अभी कुछ साल खेलना जारी रखें। विराट ने अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है, जिससे यह लगे कि वे क्रिकेट से दूर होने का मन बना रहे हैं। यानी अभी वे खेलना जारी रखेंगे, लेकिन कब तक जारी रखेंगे? फिटनेस के मामले में वे टीम इंडिया के कई यंग स्टार्स से बेहतर स्थिति में हैं। एशिया कप से पहले ही उन्होंने यो-यो टेस्ट में 17.2 स्कोर किया। रूतबा भी ऐसा है कि जब तक खुद रिटायरमेंट का फैसला न करें, उन्हें कोई बाहर नहीं कर सकता। विराट कब तक खेलेंगे, इसका जवाब कुछ दिग्गजों के करियर ग्राफ से लगाने की कोशिश करें तो सचिन तेंदुलकर 40 की उम्र तक भारत के

लिए खेले। राहुल द्रविड़ 39 की उम्र तक खेले। महेंद्र सिंह धोनी 38 साल तक टीम इंडिया का हिस्सा रहे। अगर विराट भी इन दिग्गजों की राह पर जाते हैं तो वे 4 से 5 साल आगे से खेल सकते हैं। अब अगला सवाल यह उत्तरा है कि 4 से 5 साल और खेलने की स्थिति में क्या वे 24 शतक और जमा पाएँगे। अभी उनके नाम 77 शतक हैं। सचिन ने 782 पारियों में 100 शतक लगाए हैं। विराट ने तीनों फॉर्मेट में मिलाकर 561 पारियों में 77 शतक लगाए हैं। वह हर सेंचुरी के लिए औसतन 7.29 पारियां लेते हैं। इस हिसाब से 24 शतक के लिए उन्हें 175 पारियों की जरूरत है। 16 साल के करियर में कोहली ने हर साल औसतन 35 पारियां खेली हैं। यानी 175 पारियों के लिए उन्हें 5 साल और खेलना होगा, जो बिल्कुल मुमुक्षिन है कि वे 5 साल और खेलेंगे और इस स्पीड से 2028 के अंत तक सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे।

विराट कोहली दिसंबर 2019 से अगस्त 2022 तक कोई इंटरनेशनल शतक नहीं लगा सके थे। फिर पिछले साल 8 सिंतंबर को उन्होंने एशिया कप में ही टी-20 सेंचुरी लगाकर अपने शतकों का सूखा खत्म किया था। इसके बाद कोहली ने 11 सिंतंबर 2023 तक तीनों फॉर्मेट में 6 और शतक लगा दिए। पिछले 12 महीनों में कोहली ने 7 इंटरनेशनल शतक लगाए, इसके लिए उन्होंने 40 पारियां लीं। यानी उन्होंने औसतन 5.7 पारी में एक शतक लगाया। इस हिसाब से वह अगली 137 पारियों में 24 शतक लगा देंगे। कोहली हर साल औसतन 35 पारियां खेलना जारी रखें तो अगले 4 साल में 100 शतक लगा देंगे। यानी 2027 के बनडे बल्ड कप से पहले भी कोहली सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। कुछ पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का कहना है कि कोहली अगर अपनी 5 साल पुरानी फॉर्म में आ गए तो अगले 3 साल में ही शतकों की सेंचुरी पूरी कर सकते हैं।

● आशीष नेमा



# जब एक्ट्रेस के सामने गिड़गिड़ाने लगे थे धर्मेंद्र...मांगते रहे माफी

साल 1966 में आई सुचित्रा सेन की फिल्म ममता में शूट के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि धर्मेंद्र शायद ही कभी उस बात को भला पाएं।

हालांकि 57 साल पहले आई इस फिल्म में अपनी इस हरकत के बाद धर्मेंद्र एक्ट्रेस के सामने गिड़गिड़ाने लगे थे। बाद में उन्होंने उनसे माफी भी मांगी। इसके पीछे की वजह काफी हैरान करने वाली है।

**अ**पनी इस फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र ने कुछ ऐसा कर दिया था कि जो स्क्रिप्ट का हिस्सा भी नहीं था। हालांकि धर्मेंद्र की इस हरकत की बजह से उस बक्से पर हीरोइन बुरी तरह झेंप गई थीं। कुछ देर तो उन्हें समझ ही नहीं आया था कि अधिकर ये क्या हुआ। 1966 में आई इस फिल्म में धर्मेंद्र और सुचित्रा सेन की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। इस फिल्म में सुचित्रा ने डबल रोल निभाया था। जबकि धर्मेंद्र ने फिल्म में एक बैरिस्टर का किरदार निभाया था, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है।



**सुपरस्टार ने जब एक्ट्रेस को किया किरा... धर्मेंद्र अपने दौर के जाने माने अपनेता हैं अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने तकरीबन हर एक्ट्रेस संग काम किया है। लेकिन अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जबसे उन्होंने सुचित्रा सेन को देवदास में देखा था, वह चाहते थे कि उनके साथ भी किसी फिल्म में काम करें उनकी ये इच्छा साल 1966 में आई फिल्म ममता में पूरी हुई थी। जब दोनों एक ही फिल्म में काम कर रहे थे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग के दौरान ही धर्मेंद्र ने सुचित्रा की पीठ पर किस कर लिया था। हालांकि ये किस स्क्रिप्ट का हिस्सा भी नहीं था और फिर बाद में एक्ट्रेस के बुरा मानने पर धर्मेंद्र को उनसे माफी मांगनी पड़ी थी।**

**स्ट्रिक्ट की डिमांड भी नहीं थी किस...** ममता में धर्मेंद्र और सुचित्रा सेन का एक रोमांटिक सीन थी था। इस सीन के दौरान ही धर्मेंद्र ने सुचित्रा सेन की पीठ पर उन्हें बिना बताए किस कर लिया था। हालांकि ये सीन फिल्म की स्ट्रिक्ट में भी नहीं था। एक्ट्रेस उस वर्त हैरान रह गई थी। लेकिन ये सीन इतना रीयल था कि बाद में इस सीन को फिल्म का हिस्सा बना लिया गया था। लेकिन एक्ट्रेस धर्मेंद्र की इस हरकत पर बहुत ही शर्मिदा हुई थी। जिसकी वजह से बाद में सुपरस्टार ने एक्ट्रेस से माफी भी मांगी। फिल्म में धर्मेंद्र और सुचित्रा की जोड़ी ने धमाल मचा दिया था।

## राज कपूर ने तीन पीढ़ियों को लेकर बनाई फिल्म, 1951 में साबित हुई कल्ट कलासिक

**ए**क्टर ज कपूर की फिल्में रिलीज से पहले ही सुर्खियों में छा जाती थीं। उनकी फिल्में सामाजिक संदेश और संगीत के लिए भी चर्चा में रहती थी। साल 1951 में वह एक ऐसी फिल्म लेकर आए थे जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। फिल्म का नाम था आवारा। उनकी इस फिल्म में उनकी तीन पीढ़ियों ने एक ही फिल्म में एक साथ काम किया था।



साल 1951 में आई राज कपूर और नरगिस दत्त के अभिनय से सजी इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था। राज कपूर ने अपनी

इस फिल्म में एकिंग भी की थी। फिल्म इंडस्ट्री में भारतीय सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने करियर में कई ऐसी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया जिन्होंने हिंदी सिनेमा को नई दिशा दी थी। उनकी फिल्म आवारा ने भी काफी अच्छी सफलता हासिल की थी। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और गानों को भी काफी पसंद किया गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये राज कपूर की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें राज की तीन पीढ़ियां नजर आई थीं। फिल्म आवारा के जरिए उन्होंने अपने पिता और दादा जी बशेश्वर नाथ कपूर को डायरेक्ट किया था। बशेश्वर नाथ कपूर ने आवारा में जज की भूमिका में काम किया था। हालांकि वह फिल्म में कैमियो करते नजर आए थे। इतना ही नहीं राज कपूर के छोटे भाई शशि कपूर भी इस फिल्म में राज के बचपन की भूमिका में नजर आए थे।

## 17 साल की उम्र में नसीरुद्दीन शाह दे बैठे थे रत्ना पाठक को दिल

**ज**ीसीरुद्दीन शाह एक्टिंग के बादशाह कहे जाते हैं। पैरेश रावल ने अनुभम खेर को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब हम लोग स्ट्रॉगल करते थे तो ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह जैसा बनना चाहते थे। नसीरुद्दीन शाह अपने थिएटर के दिनों में ही एक्टिंग के उस्ताद हुआ करते थे। तब के नए-नवेले एक्टर भी उनकी तरह बनने का सपना देखते थे। आज भी नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग का कोई जवाब नहीं है। नसीरुद्दीन शाह अब एक्टिंग के साथ सामाजिक परिदृश्य पर भी खुलकर बात करते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने अपनी निजी जिंदगी पर चर्चा की।



साथ ही अपनी पत्नी और 41 साल की सफल शादीशुदा और खुशहाल जिंदगी के राज भी बताए। इतना ही नहीं अपनी पत्नी रत्ना पाठक की तारीफ में उन्हें रसमलाई तक कह दिया। नसीरुद्दीन शाह

और रत्ना पाठक की मुलाकात थिएटर में एक प्लै के दौरान हुई थी। उस दौर में रत्ना महज 17 साल की थीं। रत्ना को देखकर नसीरुद्दीन शाह को पहली ही नजर में प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों लंबे समय तक साथ रहे और रिलेशनशिप के 7 साल बाद दोनों ने 12 अप्रैल 1982 को शादी रचा ली। दोनों की शादी को 41 साल हो गए हैं और बेहद खुश हैं। नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरी वाइफ रसमलाई की तरह है। मैं मानता हूं कि वो मुझसे ज्यादा होशियार और समझदार है। मैं शादी के 41 साल बाद भी अपनी पत्नी से खौफ खाता हूं।

**ह** मारी मनुष्य जाति की प्रायः तीन अवस्थाएं प्रचलन में हैं— बैठना, लेटना और खड़े रहना। एक और चौथी अवस्था भी कभी-कभी देखी जाती है; वह है उकड़ू बैठना, जिसे बैठी हुई अवस्था का ही एक उपभेद कहा जा सकता है। प्राइमरी स्कूल में मुशी जी इसका प्रयोग हमें आदमी से मुर्गा बनाने में कर लिया करते थे। यह बैठी और खड़ी हुई अवस्था का एक मिश्रित रूप है। न पूरी तरह बैठे हुए और न पूरी तरह खड़े हुए। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जंतु है, जिसे अपनी सभ्यता को दिखाने का शौक है। जिसे विभिन्न रूपों में वह प्रायः दिखाया करता है।

मानव की सभ्यता एक ऐसा कपड़ा अथवा आवरण है, जिसे वह कभी भी बदल सकता है। उतार कर फेंक सकता है। इसलिए उसका निर्वसन अथवा नंगा होना या होते चले जाना भी उसकी विकासशील सभ्यता का एक रूप है। सभ्यता के इस रूप पर यदि विस्तार से विचार किया जाएगा तो उसकी देह पर सूत का एक धागा भी नहीं बचेगा और वह सभ्यता के एवरेस्ट पर ही बैठा हुआ दिखेगा। फिलहाल हम मानवीय सभ्यता के इतने उच्चतम स्वरूप की समीक्षा करने नहीं जा रहे हैं। पहले उसकी उन्हीं साढ़े तीन अवस्थाओं पर विचार-विमर्श ही समीचीन होगा।

मनुष्य की सभी साढ़े तीन अवस्थाएं उसके जीवनभर काम आने वाली हैं। खाते, पीते, चलते-फिरते, सोते, काम करते हुए इन्हें स्व सुविधानुसार वह काम में लेता रहता है। सामान्यतः बैठने की अवस्था उसके जाग्रत जीवन की ऐसी प्रमुख अवस्था है, जो अधिकांशतः काम आती है। तभी तो किसी के द्वारा कहीं जाने पर लोग उसके स्वागत में यह कहते हुए देखे सुने जाते हैं कि आइ बैठिए, पधारिए, तशरीफ रखिए। इस काम के लिए प्रकृति ने प्रत्येक स्त्री-पुरुष को एक नहीं दो-दो भारी-भरकम विशेष अंग भी पहले से ही उपहार में दे दिए हैं और शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि कोई यह कहकर शिकायत कर सके कि हमारे पास तो थे ही नहीं जो बैठेते या पधार पाते या तशरीफ रख पाते। आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि वह बहुमूल्य दो अदद क्या हैं? जिन्हें हम जैविक विज्ञान की भाषा में निंतंब की संज्ञा से अभिहित करते हैं। अगर प्रकृति ने ये दोनों नहीं दिए होते तो शिकायत का पूरा अवसर होता। पर अब आपको वह अवसर नहीं दिया गया है। इसलिए शांतिपूर्वक ढांग से बैठना सीख लीजिए। पर कहाँ? आपको बैठने की फुरसत ही कहाँ है? आप तो इतनी जल्दी में हैं जनाब कि खाना, पीना क्या; मल-मूत्र विसर्जन तक का समय नहीं हैं आपके पास! सब कुछ खड़े-खड़े ही निबटा लेना चाहते हैं! बैठने तक की फुरसत नहीं। वाह

# सभ्यता खड़ी हो गई है!

आइडिया! यदि मानवनहित  
सरकार भी बन जाएँतो..?  
न धपला.. न अगड़ा.. न बाग़ी..  
न दाग़ी...



मनुष्य की सभी साढ़े तीन अवस्थाएं उसके जीवनभर काम आने वाली हैं। खाते, पीते, चलते-फिरते, सोते, काम करते हुए इन्हें स्व सुविधानुसार वह काम में लेता रहता है। सामान्यतः बैठने की अवस्था उसके जाग्रत जीवन की ऐसी प्रमुख अवस्था है, जो अधिकांशतः काम आती है।

रे इंसान। इंसानों और गधे-घोड़ों, सुअरों, कुत्ते, बिल्लियों में कोई भेद ही नहीं रह गया।

दावतों में शांति से बैठकर भोजन करने के स्थान पर बफेलो सिस्टम ईजाद कर लिया। यहां तक कि मूर्ति विसर्जन के लिए खड़े-खड़े वाला बड़ा-सा प्याला दीवाल पर लटका लिया और शेष काम के लिए कमोड ने उटका लिया। यह भी संभवतः असुविधाजनक होता, अन्यथा इसे भी गाय-भैंस की तरह खड़ासन में ही निबटाया। इस मामले में वह भूल बैठा की उसकी देह-संरचना की मांग बैठासन की है, खड़ासन की नहीं।

लेटकर या बैठकर आप ठहल नहीं सकते। यह ठीक है। किंतु जीवन के बहुत से काम ऐसे हैं, जिन्हें बैठकर किया जाना ही सुविधाजनक है। परंतु कल-कारखानों में जिन मरीनों पर बैठकर काम करना उचित होता, वहां भी खड़ासन में काम करने वाली मरीनें बना डालीं। खड़ी हुई अवस्था में मानव को अपेक्षाकृत अधिक और जल्दी थकान होती है, इस तथ्य को नजरअंदाज

कर दिया गया। आज वैज्ञानिक रूप से भी यह प्रमाणित किया जा चुका है कि खड़े-खड़े काम करने की अपेक्षा बैठकर काम करने से व्यक्ति अधिक समय तक जीता है। वह दीर्घायु होता है। माना कि शिक्षण कार्य बैठ या खड़े होकर दोनों तरह से किया जाना संभव है। किंतु लिपिकीय कार्य खड़ी अवस्था में करना न उचित है और न सुविधाजनक ही है। ट्रैक्टर, बस, कार, ट्रेन, हवाई जहाज आदि की ड्राइविंग बैठकर ही की जानी है, की भी जाती है। हो न हो कि ऐसी भी खोज कर ली जाए कि ये वाहन भी खड़े-खड़े चलाने वाले बना दिए जाएं। हल-बैलों से खेत की जुताई खड़े हुए ही संभव है। यही उसकी आवश्यकता भी है। कुम्भकार का चाक, मोची का जूते गांठना यदि बैठकर ही करना है तो हैंडप्यू खड़े होकर ही चलाना होगा। यह कार्य की प्रकृति है। किंतु शरीर-जैविकी की वैज्ञानिकता छोड़कर खड़े होकर कार्य करना सर्वथा अनुचित ही होगा।

हम मनुष्य खड़ासन के इतने कुशल विशेषज्ञ हैं कि अपनी बोली-भाषा को भी खड़ी कर दिया और वह खड़ी बोली बना दी गई। हमारी प्राचीन भाषाएः जैसे- ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, कन्नौजी, हरियाणवी, राजस्थानी आदि बैठा दी गई या सुला दी गई। सब कुछ खड़ा-खड़ा, खड़ी-खड़ी, खड़े-खड़े। दूल्हा-दुल्हन भी न भावंरे लेने लगें कहीं घोड़ी पर चढ़े-चढ़े!

● डॉ. भगवत् स्वरूप 'शुभम'

# **SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.**



## **D-10™ Hemoglobin Testing System For HbA<sub>1c</sub>, HbA<sub>2</sub> and HbF**

**Flexible**  
to solve more testing needs

**Comprehensive**  
B-thalassemia and  
diabetes testing

**Easy**  
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA<sub>1c</sub> or HbA<sub>1c</sub>/F/A<sub>1c</sub> testing using primary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps. With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023  
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com  
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

# पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प



इस संजल्य ने हमारे मन-मानस  
में गहरी जड़ पड़ा ली है



कोल इण्डिया लिमिटेड

विश्व की बृहतम कोयला उत्पादक संस्था

A Maharatna Company

प्रकृति के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है